चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 28 मई–03 जून 2012 | मूल्य 5 रुपये

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सच छुपाया

पेज-3

माया को मिटाने की मुहिम

पेज-4

रामदेव मुस्लिमों के लिए लड़ेंगे

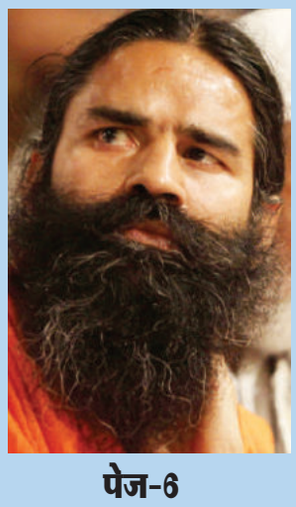

पेज-6

रेखा गूंगी गुड़िया नहीं हैं

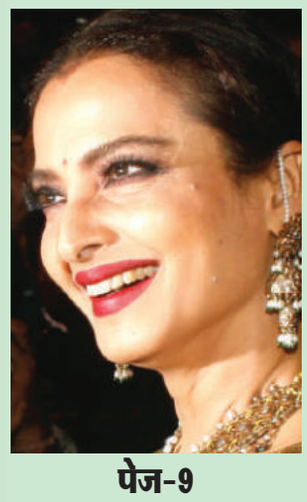

पेज-9

शिरडी

साईं बाबा संस्थान में घोटाला

राधा कृष्ण विखे पाटिल — शंकर राव कोल्हे

लूट मची है. धरती, पानी, आसमान, भगवान, सब जगह लूट. लुटेरों को इंसान तो क्या, भगवान का भी डर नहीं. वे करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक शिरडी साईं बाबा संस्थान में भी लूट मचाने से नहीं डरते. भक्तों की ओर से दिए जाने वाले दान के पैसों से जन कल्याण का काम होना था, लेकिन कुछ लोगों ने खुद का कल्याण करना शुरू कर दिया. यह कारनामा शिरडी साईं बाबा संस्थान के विश्वस्त मंडल के सदस्यों ने किया. धर्म और राजनीति के घालमेल का नतीजा क्या हो सकता है, उसी पर रोशनी डाल रही है चौथी दुनिया की यह खास पड़ताल.

आलोक मिश्रा

एक मुहावरा है, जहां धन एकत्र होगा, वहां चोर की नज़र पड़ेगी ही. शिरडी के साईं बाबा तो फकीर थे और फकीरी में ही उन्होंने सारा जीवन गुजार दिया. हां, उन्होंने गरीब–लाचार लोगों की मदद करने में कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखी. शिरडी के साईं बाबा संस्थान में जैसे–जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ी और चढ़ावे में इजाफा होने लगा, वहां भी चोरों की नज़र लग गई. फकीर के घर में भक्त के रूप में डाकू घुस आए और साईं की अमानत में खयानत करने का दौर शुरू हो गया. यह सब राजनीतिक संरक्षण में विश्वस्त मंडल के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है. साईं के घर में जबसे राजनीति ने घुसपैठ की, तबसे वहां घोटालों का कारोबार भी शुरू हो गया. विश्वस्त मंडल में शामिल हर नेता की कोशिश रहती है कि उसके साथ–साथ नाते–रिश्तेदार भी लाभांवित हों. इसके लिए वे नियम–कायदों और संस्थान को होने वाले आर्थिक नुकसान की परवाह भी नहीं करते. इसीलिए यहां प्रसाद के लड्डू से लेकर वाहन तक के मामलों में करोड़ों रुपये के घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं. इन घोटालों के खुलासे से साईं के भक्तों में आक्रोश देखा जा रहा है. साईं बाबा संस्थान में आर्थिक कदाचार वर्षों से जारी है. इस बात की जानकारी सरकार को भी थी, पर उसने इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी, जबकि यहां व्याप्त कदाचार से चिंतित साईं के कई भक्त लगातार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रधान सचिव और विधि मंत्रालय को पत्र लिखते रहे. बार–बार भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त किए जाने के बावजूद सरकार के उदासीन रवैये की वजह थी साईं बाबा संस्थान में कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस की विश्वस्त मंडल में बराबर की हिस्सेदारी. अदालत द्वारा बर्खास्त पुराने विश्वस्त मंडल के 13 सदस्यों में 7 राष्ट्रवादी कांग्रेस और 6 कांग्रेस के थे. दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों ने यह रणनीति बनाई थी कि बारी–बारी से अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पद बदल कर इस दुधारू संस्थान के विश्वस्त मंडल पर कब्ज़ा बरकरार रखा जाएगा. इसका पता इस बात से चल जाता है कि पुराने विश्वस्त मंडल को अदालत द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद जो नया विश्वस्त मंडल गठित हुआ, उस पर भी इन्हीं दोनों दलों का कब्जा बना रहा. जब इस राजनीतिक चालाकी को अदालत के समक्ष लाया गया तो उसने नए विश्वस्त मंडल के कार्यभार संभालने पर रोक लगा दी और जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को फिलहाल साईं बाबा संस्थान का कामकाज देखने का निर्देश दिया. अदालत की इस व्यवस्था के बाद धीरे–धीरे विश्वस्त मंडल में शामिल राजनेताओं के संरक्षण में पनपने वाले कदाचार से पर्दा उठने लगा है.

मोबाइल खरीदने में भी घोटाला हुआ. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, विश्वस्त मंडल के सदस्यों ने अपने लिए मोबाइल खरीदने में भी ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल किया. पूर्व मंत्री एवं संस्थान के उपाध्यक्ष शंकर राव कोल्हे ने पांच सालों में 6 महंगे मोबाइल सेट खरीदे और उनका भुगतान संस्थान द्वारा किया गया. उनके मोबाइल बिल के हजारों रुपये भी संस्थान द्वारा अदा किए गए. सीईओ और डिप्टी सीईओ ने जब विदेश दौरा किया तो उसका भी भुगतान संस्थान ने किया, जबकि उन्होंने इसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली थी. यात्रा करने के बाद उन्हें इस यात्रा की अनुमति दी गई.

श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था के सूचना एवं प्रशासकीय अधिकारी ने कोपरगांव निवासी संजय भास्करराव काले द्वारा सूचना का अधिकार क़ानून के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में लिखे पत्र में बताया है कि वर्ष 2010–11 के आर्थिक बजट के अनुसार संस्थान की आय 255 करोड़, खर्च 151.70 करोड़ और शेष रकम 103.30 करोड़ रुपये है. वर्ष 2011–12 में खर्च की गई रकम का ब्योरा इस प्रकार है:–

शिरडी की आंतरिक सड़कों के विकास के लिए 9 करोड़ 60 लाख 64 हजार 639 रुपये श्रीरामपुर के उप विभागीय अधिकारी को दिए गए. आईटीआई के छात्र रमेश गोपीनाथ अम्बरे के निधन पर एक लाख रुपये उसके पिता गोपीनाथ किशन अम्बरे को दिए गए. 2 लाख 59 हजार 95 रुपये शिरडी नगर पंचायत को डीपी रोड और रिंग रोड का विकास करने के लिए दिए गए. शिरडी नगर पंचायत को 50 लाख रुपये बतौर सेनीटेशन टैक्स दिए गए. महाराष्ट्र

(शेष पृष्ठ 2 पर)

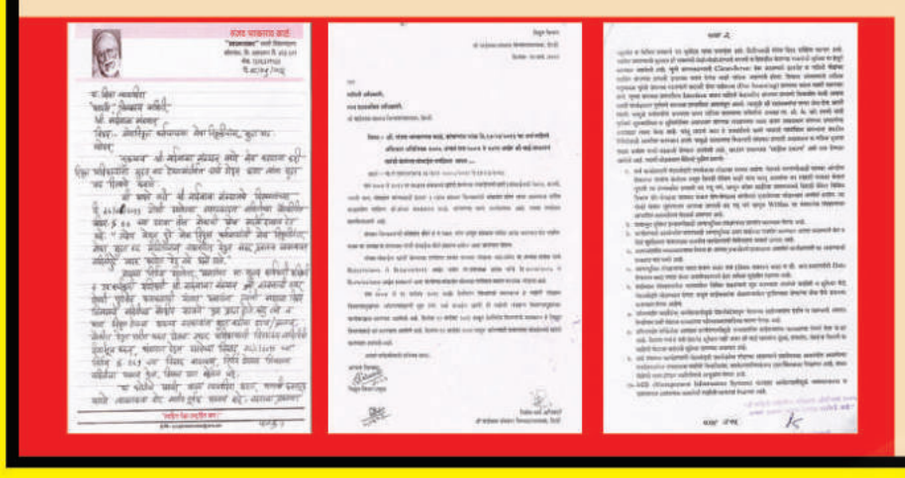

संजय काले

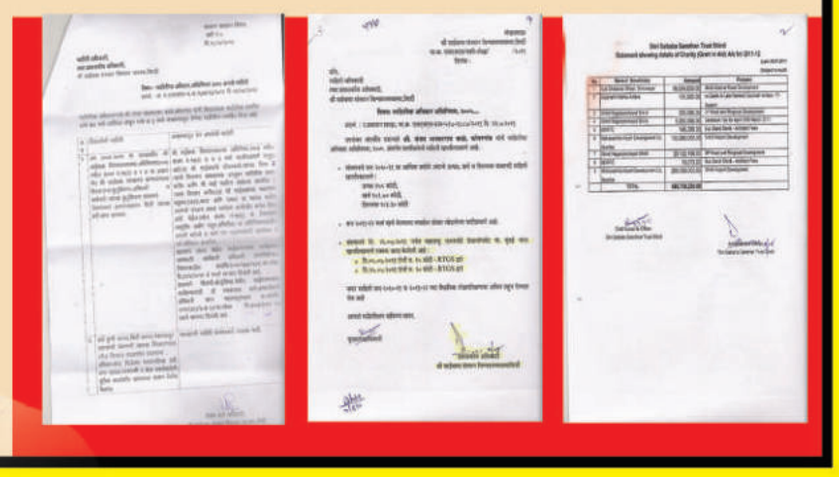

Coming Soon CHAUTHI DUNIYA Now in English

हाल-फिलहाल में एक विद्यार्थी ने गुड़गांव में आत्महत्या कर ली. कहा जा रहा है कि उसके साथ भी भेदभाव किया गया.

दिल्ली का बाबू

विशेष सुरक्षा

कुछ सालों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के साथ नस्लीय भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं. दिल्ली और आसपास पढ़ने या नौकरी करने के लिए आने वाले पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इस बात की भी शिकायत रहती है कि राजधानी में उनके क्षेत्र के बहुत कम अधिकारी हैं, इसलिए उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता. हाल-फिलहाल में एक विद्यार्थी ने गुड़गांव में आत्महत्या कर ली. कहा जा रहा है कि उसके साथ भी भेदभाव किया गया. ऐसी ख़बरें देश के दूसरे राज्यों से भी आ रही हैं. इस तरह की घटनाओं के बाद सरकार ने इन मुद्दों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है. पहली बार पूर्वोत्तर भारत के पांच आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली पुलिस में की गई है. सूत्रों के अनुसार, 23 आईपीएस अधिकारियों को कुछ समय पहले ही दिल्ली से बाहर भेजा गया है. लगता है, इन अधिकारियों को दिल्ली से बाहर भेजने की मुख्य वजह यही रही होगी. जिन पांच आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली में की गई है, वे हैं मिजोरम के जॉन नेहलई, अरुणाचल प्रदेश के किम कमिंग, नबाम गूंटे, अपूर्बितिन एवं एल एन रंगचल. उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में इन अधिकारियों की नियुक्ति के बाद पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों की हिम्मत बढ़ेगी और उन्हें भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा. ■

यूटीआई को सीईओ का इंतजार

यूटीआई के नए सीईओ की तलाश जारी है. पिछले साल यूटीआई के सीईओ यू के सिन्हा को सेबी का प्रमुख बनाया गया था, तबसे लेकर आज तक यूटीआई में सीईओ की नियुक्ति नहीं हो सकी. सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेश खोसला को इस पद पर नियुक्त करने के लिए यह देर की गई. जितेश खोसला पहले वित्त मंत्रालय में काम कर चुके हैं और उन्हें वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की सलाहकार ओमिता पाल का समर्थन भी हासिल है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जितेश खोसला का विरोध किया था और उनके सीईओ बनने के बाद समस्याएं बढ़ सकती थीं, इसलिए खोसला ने इस दौड़ से बाहर रहने की सोची है. अब हो सकता है कि जल्दी ही यूटीआई के सीईओ के पद पर किसी की नियुक्ति हो जाए. ■

विशिष्ट क्लब

वर्षों से आईएएस कैडर के अधिकारियों का दबदबा रहा है, जिसे दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पसंद नहीं करते. अब आईपीएस अधिकारी भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अब आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष क्लब बनाने की योजना बना रही है. स्वाभाविक है कि इससे सीबीआई में काम कर रहे गैर आईपीएस अधिकारी खुश नहीं हैं. सीबीआई सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दस पद आईपीएस अधिकारियों को सौंपने जा रही है. साथ ही वह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की संख्या बढ़ाना चाहती है और वहां पर भी आईपीएस अधिकारियों को लाया जाना है. सूत्रों का कहना है कि सीबीआई निदेशक ए पी सिंह ने कार्मिक विभाग को इस परिवर्तन के बारे में लिखा है. इससे गैर आईपीएस अधिकारी नाराज हैं, क्योंकि कुछ गैर आईपीएस अधिकारियों को उम्मीद थी कि उनकी प्रोन्नति एसपी या एसएसपी रैंक पर हो जाएगी, लेकिन वे नए फ़ैसले से निराश हैं. उन्हें लग रहा है कि उनकी प्रोन्नति अधर में लटक जाएगी. ■

dilipcherian@gmail..com

दिलीप चेरियन

साउथ ब्लॉक

राम प्रसाद मीणा और उत्कर्ष तिवारी निदेशक बने

1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. राम प्रसाद मीणा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक बनाया जाएगा. वह अविनाश मिश्रा की जगह लेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय भेजा गया है. इसी तरह उत्कर्ष आर तिवारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निदेशक बनाया गया है. वह मोनिका भाटिया की जगह लेंगे.

उषा शर्मा एडीजी बनीं

1985 बैच की आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है. वह देवेश चतुर्वेदी की जगह लेंगी.

नरेंद्र भूषण संयुक्त सचिव बने

1992 बैच के आईएएस अधिकारी नरेंद्र भूषण को कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह सुभाष चंद्र गर्ग की जगह लेंगे.

के ए प्रसाद परमाणु ऊर्जा विभाग गए

1992 बैच के आईएएस अधिकारी के ए प्रसाद सिन्हा को परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह पहले विदेश राज्य मंत्रालय में पीएस थे. वह विजय भूषण पाठक की जगह लेंगे, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

नीति सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मंजू राजपाल ग्रामीण विकास मंत्रालय गईं

1995 बैच की आईआरएएस अधिकारी नीति सरकार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह 1990 बैच की आईआरएस (आईटी) अधिकारी कविता पांडे की जगह लेंगी.

इसी तरह 2000 बैच की आईएएस अधिकारी मंजू राजपाल को ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह जगदीश सिंह की जगह लेंगी.

वी पी भारद्वाज बीआईएफआर के सचिव बने

सीएसएस कैडर के अधिकारी वी पी भारद्वाज को बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनांसियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) का सचिव बनाया गया है. वह गजेंद्र भुजबल की जगह लेंगे. यह पद संयुक्त सचिव के समकक्ष है.

राहुल खुल्लर टीआरएआई के चेयरमैन बनेंगे

1975 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल खुल्लर को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया जाएगा. वह जे एस शर्मा की जगह लेंगे. ■

साईं बाबा संस्थान में घोटाला

पृष्ठ एक का शेष

एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी मुंबई को 15 करोड़ रुपये शिरडी विमान तल के विकास के लिए दिए गए. इसके बाद पुन: शिरडी नगर पंचायत के नाम 2 करोड़ 91 लाख 22 हजार 190 रुपये जारी किए गए. एमएसआरटीसी के बस स्टैंड के विकास के लिए आर्किटेक्ट शुल्क के रूप में 15 हजार 75 रुपये का भुगतान किया गया. इसके बाद एक बार पुन: महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी मुंबई को 20 करोड़ रुपये शिरडी विमान तल के विकास के लिए दिए गए (यह हिसाब-किताब 26 जुलाई, 2011 तक का है). इन आंकड़ों पर नज़र डालने पर पता चलता है कि सड़कों के विकास के नाम पर संस्थान द्वारा बार-बार करोड़ों रुपये जारी किए जाते रहे हैं. विशेष बात यह है कि संस्थान द्वारा जारी इन पैसों से सड़कों का कितना विकास हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्थान ने रकम दे दी, उसके बाद उस रकम का क्या हुआ, उससे संस्थान का कोई लेना-देना नहीं. सवाल यह भी उठता है कि शिरडी के विकास के लिए सरकार द्वारा जो करोड़ों रुपये जारी किए जाते हैं, वे कहां चले जाते हैं?

आरटीआई एक्टिविस्ट संजय काले ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर साईं टेक परियोजना के लिए कॉग्नीजेंट कंपनी से अनुबंध करने में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया था. जवाब में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जो पत्र आया, उसमें इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया. इस पर काले ने 21 नवंबर को पुन: मुख्य सचिव को पत्र लिखा और ध्यान दिलाया कि 29 अगस्त को साईं संस्थान द्वारा कॉग्नीजेंट कंपनी से साईं टेक परियोजना के लिए जो करार किया गया, वह नियम-कायदों के अनुसार नहीं है. उसमें भ्रष्टाचार होने का अंदेशा व्यक्त करते हुए आपके पास निवेदन किया गया था, जिसका जवाब आपकी बजाय साईं संस्थान ने देने का प्रयत्न किया, जिसमें मुख्य मुद्दे को टाल दिया गया. इस पूरे प्रकरण में भारी भ्रष्टाचार होने की आशंका है. कॉग्नीजेंट कंपनी ने साईं टेक परियोजना पर जनवरी 2010 से काम चालू कर दिया है, जबकि करार हुए बिना दस माह पहले किसी कंपनी द्वारा काम किया जाना नियमानुसार सही नहीं है. साईं बाबा संस्थान का करार जब 22 मई, 2010 को हुआ तो कंपनी जनवरी से भला कैसे काम शुरू कर सकती है. इस करार में वर्क शेड्यूल का मसौदा भी मंजूर किया गया है. मसौदे में मुद्दा क्रमांक 1 के अंत में इस बात का साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि जनवरी 2010 से काम चालू है. मुद्दा क्रमांक दो में लिखा है कि मई माह के अंत में इस परियोजना का पहला चरण संस्थान को हस्तांतरित करना बंधनकार है, जबकि कंपनी ने साईं टेक परियोजना का पहला चरण जुलाई 2011 में मुख्यमंत्री के हाथों हस्तांतरित किया. इस दृष्टि से देखा जाए तो कंपनी यदि मई में परियोजना का पहला चरण पूरा करने में असमर्थ थी तो उसके साथ किया गया करार बेकायदा हो जाता है. करार के अनुसार कंपनी को साईं टेक परियोजना जनवरी 2011 में पूरी करके देनी थी, पर उसने परियोजना का पहला चरण ही जुलाई 2011 में पूरा किया. इस लिहाज से वर्क शेड्यूल की धारा 5.1 के तहत यह करार स्वत: रद्द हो जाता है. इस तरह 21.87 करोड़ रुपये की इस साईं टेक परियोजना का करार तुरंत रद्द किया जाना चाहिए. पहले पत्र में मुद्दा क्रमांक 2 में वर्ष 2007 से 2011 के बीच पूरे साईं संस्थान को कंप्यूटरीकृत करने पर कुल 46,87,080 रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख किया गया है. इसके तहत बीस सुविधाएं संस्थान की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं. संस्थान ने उनमें 17 नई सुविधाओं को जोड़ दिया है, जिनमें मुख्य रूप से जलापूर्ति, सुरक्षा, निर्माण, कर्मचारी, टेलीफोन बिल, उत्सव नियोजन, पुराने रिकॉर्डों की देखभाल, ई-मेल सुविधा, बिजली विभाग, यात्रा का आयोजन, वाहन, विधि एवं बैठक विभाग आदि को शामिल किया गया है. उक्त 17 में से 70 प्रतिशत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं. कामकाज भी अच्छा चल रहा है. मशीनरी (कंप्यूटर) 4.60 करोड़ रुपये की है तो बाकी 17.27 करोड़ रुपये पांच वर्ष में बीमा और देखभाल में खर्च होने की बात आपके विभाग द्वारा कही गई है. इसका अर्थ क्या लगाया जाए? 4.60 करोड़ रुपये के कंप्यूटर यदि पांच साल में हर वर्ष बदले भी जाएं तो किसी भी सूरत में 21.87 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो सकते. इसके बावजूद आपका विभाग एवं साईं संस्थान के पदाधिकारी कॉग्नीजेंट कंपनी का गुणगान गा रहे हैं. इससे तो 12,800 करोड़ रुपये की पूंजी और एक लाख तकनीकी विशेषज्ञों वाली इस कंपनी की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लग जाता है. इसके बाद काले ने 24 नवंबर को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिखकर साईं संस्थान के कामकाज में 15 खामियां बताईं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने साई संस्थान में हुए आर्थिक व्यवहारों का लेखा परीक्षण कैग द्वारा और मामले की जांच सीआईडी या सीबीआई या अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा कराने की मांग की. साथ ही सुझाव दिया कि हर विभाग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए.

इस पवित्र संस्थान में भ्रष्टाचार की कहानी यहीं नहीं रुकती है. अलग-अलग आर्थिक कदाचार के तहत करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका संजय काले ने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में जाहिर की है. साथ ही उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका भी दायर की है, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति भूषण गवई एवं न्यायमूर्ति सुनील देशमुख ने सरकार और विश्वस्त मंडल को तीन सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. याचिका में कहा गया है कि साईं संस्थान से संबंधित घोटालों और वहां के कामकाज में अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए किसी राजनीतिक व्यक्ति या उसके नाते-रिश्तेदारों को विश्वस्त मंडल में न लिया जाए. संस्थान में हुए गलत आर्थिक व्यवहार की रकम विश्वस्त मंडल के सदस्यों से वसूल की जाए. याचिका में बताया गया है कि साईं संस्थान के विश्वस्तों ने यह कहकर प्रसाद के लड्डुओं की बिक्री पर रोक लगा दी कि नुकसान हो रहा है, मगर वास्तविकता यह है कि प्रति दिन प्रसाद के लड्डुओं के 39-40 हजार पैकेटों की बिक्री होती थी. इस पर रोक लगाकर विश्वस्त मंडल ने प्रसाद में पेड़ों की बिक्री का ठेका एक निजी संस्था को दे दिया. इस निजी संस्था द्वारा प्रति दिन 911 किलो पेड़ों की बिक्री की जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि साल में 3 लाख 30 हजार किलो पेड़े की बिक्री प्रसाद के रूप में होती है. इस तरह निजी संस्था का वार्षिक कारोबार 115 करोड़ रुपये का है, जिसमें नफा अधिक है. वहीं विश्वस्तों के इस निर्णय से संस्थान को एक करोड़ 65 लाख रुपये का मासिक नुकसान हो रहा है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि साईं संस्थान के अध्यक्ष जयंत सयाणे, उपाध्यक्ष शंकरराव कोल्हे एवं राधाकृष्ण विखे पाटिल (वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री) ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया. इतना ही नहीं, बड़े नेताओं ने अपने नाते-रिश्तेदारों को ठेका दिलाने का प्रयास किया. काले का कहना है कि यदि संस्थान के आर्थिक लेनदेन की जांच सही तरीके से की जाए तो यह घोटाला और बड़ा रूप ले सकता है.

बहरहाल, साईं संस्थान के विश्वस्त मंडल की कारगुजारियों का जैसे-जैसे खुलासा हो रहा है, उसी के साथ साईं भक्तों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. दरअसल, जहां धन संग्रह होता है, वहां भ्रष्टाचार अपनी जगह बना लेता है. जिस धार्मिक संस्थान में राजनीति प्रवेश कर जाती है, वहां की पवित्रता पर आंच आने लगती है. साईं के घर में राजनीति के चलते जो गंदगी फैली, भ्रष्टाचार पनपा, क्या वह अदालत के हस्तक्षेप से साफ हो पाएगा या नहीं, साईं भक्तों के मन में आज सिर्फ़ यही सवाल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कैसे-कैसे घोटाले

मोबाइल ख़रीदने में भी घोटाला हुआ. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, विश्वस्त मंडल के सदस्यों ने अपने लिए मोबाइल ख़रीदने में भी ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल किया. पूर्व मंत्री एवं संस्थान के उपाध्यक्ष शंकर राव कोल्हे ने पांच सालों में 6 महंगे मोबाइल सेट ख़रीदे और उनका भुगतान संस्थान द्वारा किया गया. उनके मोबाइल बिल के हजारों रुपये भी संस्थान द्वारा अदा किए गए. सीईओ और डिप्टी सीईओ ने जब विदेश दौरा किया तो उसका भी भुगतान संस्थान ने किया, जबकि उन्होंने इसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली थी. यात्रा करने के बाद उन्हें इस यात्रा की अनुमति दी गई. लंदन में भजन गायक सुरेश वाडेकर के कार्यक्रम के लिए संस्थान ने दस लाख रुपये दिए, लेकिन वीजा न मिलने से कार्यक्रम नहीं हो सका, पर इसमें भी करीब 4 लाख रुपये संस्थान को वापस नहीं मिले. विश्वस्त मंडल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं. मसलन, संस्थान के नियम 8 बी के तहत प्रत्येक सदस्य को एक शपथ पत्र देना होता है कि वह साईं भक्त है, लेकिन विश्वस्त मंडल के सदस्यों ने ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं दिया था. इस हिसाब से देखें तो पुराने विश्वस्त मंडल के सदस्यों की नियुक्ति भी अवैध थी. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि विश्वस्त मंडल के उक्त सदस्य ट्रस्ट की बैठकों से भी गायब रहते थे.

बार-बार भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त किए जाने के बावजूद सरकार के उदासीन रवैये की वजह थी साईं बाबा संस्थान में कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस की विश्वस्त मंडल में बराबर की हिस्सेदारी. अदालत द्वारा बर्खास्त पुराने विश्वस्त मंडल के 13 सदस्यों में 7 राष्ट्रवादी कांग्रेस और 6 कांग्रेस के थे. दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों ने यह रणनीति बनाई थी कि बारी-बारी से अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद बदल कर इस दुधारू संस्थान के विश्वस्त मंडल पर कब्ज़ा बरकरार रखा जाएगा. इसका पता इस बात से चल जाता है कि पुराने विश्वस्त मंडल को अदालत द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद जो नया विश्वस्त मंडल गठित हुआ, उस पर भी इन्हीं दोनों दलों का कब्जा बना रहा.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 12
दिल्ली, 28 मई-03 जून 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888, 6452888, 011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दरअसल, जबसे नए सेनाध्यक्ष के तौर पर बिक्रम सिंह के नाम की घोषणा हुई, तभी से बिक्रम सिंह से जुड़े कुछ विवादास्पद मामले एक-एक कर सामने आने लगे.

बिक्रम सिंह और पीआईएल

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सच छुपाया

बिक्रम सिंह मामले में जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसे लेकर कुछ और नए सवाल सामने आए हैं. मसलन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार ने भावी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था? एक ख़बर के मुताबिक, कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे साफ़ पता चलता है कि सरकार ने न केवल सुप्रीम कोर्ट, बल्कि बिक्रम सिंह की नियुक्ति को हरी झंडी देने वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भी गुमराह किया. सरकार ने कुछ ऐसे तथ्यों को छुपाया, जिनसे बिक्रम सिंह की नए सेनाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति का मामला खटाई में पड़ सकता था. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को भारतीय सेना का नया सेनाध्यक्ष बनाने में कोई रुकावट सामने न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और नियुक्ति समिति को गुमराह करने का काम किया.

दरअसल, जबसे नए सेनाध्यक्ष के तौर पर बिक्रम सिंह के नाम की घोषणा हुई, तभी से बिक्रम सिंह से जुड़े कुछ विवादास्पद मामले एक-एक कर सामने आने लगे. एक मामला 2008 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के तहत गई भारतीय सैन्य टुकड़ी द्वारा यौन दुर्व्यवहार का भी है, जहां बिक्रम सिंह इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उस घटना को रोकने में असफल रहे थे. उस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है और बिक्रम सिंह उस घटना के लिए अब तक दोष मुक्त नहीं हुए हैं. वह घटना तब प्रकाश में आई, जब संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ इंटरनल ओवरसाइट सर्विसेज ने जांच की. यही वह संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाली सैन्य टुकड़ियों की निगरानी करती है. दिसंबर 2008 में नॉर्थ किवू ब्रिगेड में शामिल इस सैन्य टुकड़ी के ख़िलाफ़ ऑफिस ऑफ इंटरनल ओवरसाइट सर्विसेज को शिकायतें मिली थीं.

उक्त मामले में जब भारत में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें बिक्रम सिंह को उस घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनकी सेना प्रमुख पद पर दावेदारी को चुनौती दी गई तो जवाब में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उक्त घटना के समय बिक्रम सिंह यूएन के पे-रोल पर डिप्टी फोर्स कमांडर एवं इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट थे, इसलिए उन्हें उस घटना के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आधा सच ही बताया. यूएन की इंटरनल ओवरसाइट सर्विसेज (ओआईओएस) की जांच रिपोर्ट कुछ और ही कहती है. ओआईओएस यूएन के बैनर तले होने वाली किसी भी चूक की जांच करने के लिए ज़िम्मेदार एजेंसी है. उसे कांगो में नॉर्थ किवू ब्रिगेड की सहायक भारतीय सैन्य टुकड़ी द्वारा कथित तौर पर किए गए यौन दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली थीं. दस्तावेजों के मुताबिक, घटना के समय लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह दोहरी भूमिका में थे. यह तथ्य सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया गया. बिक्रम सिंह उस वक्त न केवल डिप्टी फोर्स कमांडर थे, बल्कि ईस्टर्न डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) भी थे. नॉर्थ किवू ब्रिगेड इसी ईस्टर्न डिवीजन के तहत आती थी. इससे यह तथ्य उजागर होता है कि वह सैन्य टुकड़ी लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के सीधे नियंत्रण में थी, जिस पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा था. भारतीय सेना ख़ुद इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चला रही है, जिसमें उक्त टुकड़ी के 12 अधिकारियों एवं 39 अन्य के ख़िलाफ़ मेरठ डिवीजन में जांच चल रही है, तब भी बिक्रम सिंह को इस पूरे मामले से अलग रखा गया, उन्हें इस जांच से बाहर रखा गया.

असल में तत्कालीन उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू के टूर नोट्स में भी बिक्रम सिंह और कांगो में उनकी अहम भूमिका का उल्लेख किया गया है. नायडू 25 मई से 29 मई 2008 तक कांगो में थे. उस वक्त नायडू ने कांगो में तीन भारतीय ठिकानों का दौरा किया था. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह एमओएनयूसी (कांगो में विशेष मिशन) में थे. ईस्टर्न डिवीजनल कमांडर के तौर पर उस वक्त बिक्रम सिंह के मातहत 301 इंफेंट्री ब्रिगेड थी और उसके ब्रिगेडियर इंदरजीत नारायण थे. अब सरकार कांगो में हुए यौन दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता की ज़िम्मेदारी ब्रिगेडियर नारायण के सिर पर डालने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ नायडू के टूर नोट्स के मुताबिक कहानी कुछ और है. नायडू के इस टूर नोट्स में एक और अहम चूक का जिक्र है. इसके मुताबिक, नार्थ किवू ब्रिगेड के तहत भारतीय टुकड़ियों को 16 जगहों पर तैनात किया जाना था, लेकिन यूएन को बिना कोई सूचना दिए ही भारतीय टुकड़ियों की तैनाती 39 जगहों पर कर दी गई. यह एक गंभीर चूक थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विवादित क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए सैनिकों की नियुक्ति बेहद संवेदनशील तरीक़े से करता है और इस मामले में खासी सावधानी बरती जाती है. गौरतलब है कि उप सेना प्रमुख ने कहा था कि सैन्य टुकड़ियों को तय मानकों के मुताबिक ही तैनात किया जाना चाहिए था और यह आदेश लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, ब्रिगेडियर नारायण और आर्मी हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल को यानी तीन जगहों पर भेजा गया था. वहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट में केवल ब्रिगेडियर नारायण को ही सारे मामले के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि टूर नोट्स के मुताबिक वह सिर्फ़ अपने बॉस बिक्रम सिंह को रिपोर्ट कर रहे थे. एक और तथ्य यह है कि इस मामले में जब जनहित याचिका दायर की गई थी, तब भी आर्मी हेडक्वार्टर ने रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा था.

13 अप्रैल, 2012 को एसडी डायरेक्टोरेट (सेना मुख्यालय की वह ब्रांच, जो यूएन शांति प्रक्रिया से जुड़े मामले देखती है) को एक पत्र लिखकर अगस्त 2007 से अगस्त 2008 के बीच डिप्टी फोर्स कमांडर, डिवीजन कमांडर एवं एमओएनयूसी की भूमिका और ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा गया था. यह वही वक्त है, जब बिक्रम सिंह कांगो में तैनात थे. उक्त पत्र का सेना मुख्यालय ने जो जवाब भेजा, जिसमें यूएन के आदेश का जिक्र भी था, उसके मुताबिक, ईस्टर्न डिवीजन के डिवीजनल कमांडर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह ही कांगो में तैनात चारों ब्रिगेडों के लिए ज़िम्मेदार थे. उन्हीं चार में से एक नॉर्थ किवू ब्रिगेड भी थी, जिसमें भारतीय और बांग्लादेशी सैन्य टुकड़िया शामिल थीं. यही वह ब्रिगेड है, जिस पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा और जिसका ख़ुलासा यूएन की की जांच में हुआ. केंद्र सरकार के विधि अधिकारियों ने यह बताया कि बिक्रम सिंह वहां पर यूएन के पे-रोल पर तैनात महज एक नौकरशाह थे और इसलिए भारतीय टुकड़ी की ओर से हुई किसी भी चूक के लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि यह भी एक तथ्य है कि यूएन की स्वतंत्र जांच से कांगो के उस क्षेत्र में, जहां उक्त घटना हुई थी, कई ऐसे बच्चे मिले, जिनका चेहरा भारतीय जैसा दिखता है और यह तथ्य यौन दुर्व्यवहार के आरोप को पुख्ता करता है. अब इस मामले की जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है, जो संभवत: डीएनए जांच का आदेश दे सकती है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और दोषियों की पहचान की जा सके. ■

सौजन्य-डीएनए

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आधा सच ही बताया. यूएन की इंटरनल ओवरसाइट सर्विसेज (ओआईओएस) की जांच रिपोर्ट कुछ और ही कहती है. ओआईओएस यूएन के बैनर तले होने वाली किसी भी चूक की जांच करने के लिए ज़िम्मेदार एजेंसी है. उसे कांगो में नॉर्थ किवू ब्रिगेड की सहायक भारतीय सैन्य टुकड़ी द्वारा कथित तौर पर किए गए यौन दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली थीं. दस्तावेजों के मुताबिक, घटना के समय लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह दोहरी भूमिका में थे.

बिक्रम सिंह और विवाद

बिक्रम सिंह और विवाद मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अभी भी उनसे संबंधित दो मामले चल रहे हैं. एक मामला जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में चल रहा है तो दूसरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच चल रही है. पहला मामला एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है. यह एनकाउंटर एक मार्च, 2001 को अनंतनाग के जंगलात मंडी इलाक़े में हुआ था, जिसमें कर्नल जे पी जानू और पांच अन्य लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह घायल हुए थे. सेना के सूत्रों के मुताबिक़, यह इलाक़ा 15 कोर की विक्टर फोर्स के अंतर्गत और अनंतनाग के 1 आरआर सेक्टर में आता है. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह उस वक्त ब्रिगेडियर हुआ करते थे और 1 आरआर सेक्टर के कमांडर थे. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह एक कमीशंड ऑफिसर के तौर पर 1972 में सिख लाइट इंफेंट्री रेजीमेंट से जुड़े थे. फिलहाल वह ईस्टर्न कमांड के मुखिया हैं और जनरल वी के सिंह के बाद सेनाध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं, लेकिन 38 साल के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह का विवादों से रिश्ता मानो चोली-दामन जैसा रहा है. मसलन, फ़र्ज़ी मुठभेड़ के आरोपियों को बचाने के लिए बिक्रम सिंह (तब वह कश्मीर में तैनात थे और ब्रिगेडियर थे) ने सीबीआई को पत्र लिखा. पूरा किस्सा कुछ यूं है. 20 मार्च, 2000 को जब बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे, आतंकवादियों ने कश्मीर के छत्तीसिंह पुरा में 36 सिखों की हत्या कर दी. इसके ठीक 5 दिनों बाद सेना के जवानों ने अनंतनाग के पथरीबल में 5 नागरिकों को इस आरोप में मार गिराया कि वे सिख नरसंहार की घटना में शामिल थे. 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाख़िल की, तब उसमें ब्रिगेडियर बिक्रम सिंह के उस पत्र (संख्या ए/38240/एमओ3ए, दिनांक 31 दिसंबर, 2004) को भी शामिल किया था, जिसमें यह लिखा गया था कि उक्त घटना में शामिल सेना के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें अफसपा (आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट) के तहत विशेष अधिकार मिला हुआ है. सीबीआई ने इस पत्र के माध्यम से सेना की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे. एक और गंभीर आरोप में बिक्रम सिंह फंस सकते हैं. मामला 2008 में यूएन की शांति सेना के तौर पर कांगो गए सिख रेजीमेंट के 51 अधिकारियों एवं जवानों द्वारा वहां पर बलात्कार और सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप का है. मेरठ स्थित आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले की जांच कर रही है. ग़ौरतलब है कि इस रेजीमेंट के 120 अधिकारियों एवं जवानों की एक कंपनी कांगो गई थी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह संभाल रहे थे. जाहिर है, अगर जांच में उक्त आरोप सही पाए गए तो यह लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के करियर पर काला धब्बा साबित होगा. ■

लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू के टूर नोट्स में भी बिक्रम सिंह और कांगो में उनकी अहम भूमिका का उल्लेख किया गया है. नायडू 25 मई से 29 मई 2008 तक कांगो में थे. उस वक्त नायडू ने कांगो में तीन भारतीय ठिकानों का दौरा किया था. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह एमओएनयूसी (कांगो में विशेष मिशन) में थे. ईस्टर्न डिवीजनल कमांडर के तौर पर उस वक्त बिक्रम सिंह के मातहत 301 इंफेंट्री ब्रिगेड थी और उसके ब्रिगेडियर इंदरजीत नारायण थे. अब सरकार कांगो में हुए यौन दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता की ज़िम्मेदारी ब्रिगेडियर नारायण के सिर पर डालने की कोशिश कर रही है.

मायाराज के सभी अफसरों को बिना उनकी काबिलियत देखे हाशिए पर डाल दिया गया है. उनकी जगह अपनी पसंद के अधिकारियों को बैठाया गया है.

माया को मिटाने की मुहिम

अजय कुमार feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी. बसपा शासनकाल की वे परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जो अधूरी हैं. अखिलेश युवा एवं ऊर्जावान हैं, उनकी कार्यशैली लोगों ने पहले कभी देखी-समझी नहीं, यही वजह थी उनकी बातें लोगों को अच्छी लगीं. वर्षों से बदले की राजनीति का दंश झेल रही प्रदेश की जनता भी नहीं चाहती थी कि नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार की खामियां निकालने में समय बिताती रहे, क्योंकि कोई भी सरकार बदले की कार्रवाई करती है तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है. विकास पर प्रभाव पड़ता है, जनता की मूलभूत ज़रूरतों से सरकार का ध्यान हट जाता है. अखिलेश की बातों से लगा कि प्रदेश में एक नई परंपरा पड़ेगी. बदले की भावना से काम करने वाली सरकारों का दौर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सरकार बनते ही यह तिलिस्म टूटने में देर नहीं लगी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्री बसपा सरकार की खामियों पर ही नहीं, अच्छाइयों पर भी उंगली उठाने लगे. सपा सरकार जिस तरह फ़ैसले ले रही है, उससे तो यही लगता है कि नई सरकार मायावती को राजनीतिक रूप से मिटाने की मुहिम पूरी कर लेना चाहती है.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मायाराज में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मायावती नौकरशाही पर हावी रहती थीं. वह जो काम चाहती थीं, करा लेती थीं. मायावती सर्वजन हिताय के नारे के साथ सत्ता में आई थीं और अपने पूरे कार्यकाल में इससे डिगी नहीं. अपवाद को छोड़कर उनका कोई भी फ़ैसला किसी जाति विशेष को लाभ पहुंचाने वाला नहीं होता था, जबकि सपा सरकार के फ़ैसले वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. सरकार का अधिकांश समय मायावती शासन की खामियां खंगालने में गुजर रहा है. खासकर आजम खां एवं शिवपाल यादव जैसे नेता और मंत्री इस काम में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी एनआरएचएम घोटाले के पुख्ता सबूत होने का दावा कर रहे हैं. पार्कों में लगी मूर्तियों की कीमत को लेकर भी बवाल मचा हुआ है. अखिलेश यादव बसपा प्रमुख का नाम लेकर तो उन पर हमला नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वह बार-बार यह कहते हैं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा. विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब वह मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने एनआरएचएम घोटाले में मायावती की भूमिका के सवाल पर कहा कि सच जल्दी सामने आ जाएगा. लगता है, सपा सरकार और उसके नेता मायावती को सलाखों के पीछे देखने के लिए काफी उतावले हैं. सपाई कहते घूम रहे हैं कि एनआरएचएम घोटाले में पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मायावती का नंबर आने वाला है.

मायाराज के सभी अफसरों को बिना उनकी काबिलियत देखे हाशिए पर डाल दिया गया है. उनकी जगह अपनी पसंद के अधिकारियों को बैठाया गया है. ईमानदार एवं कर्मठ नौकरशाहों की जगह चापलूस अधिकारियों को मलाईदार पदों पर बैठाया गया है. संजय अग्रवाल, दिल्ली से आए जे पी शर्मा, प्रवीर कुमार, वीरेश कुमार, माजिद अली, शैलेश कृष्ण, अशोक कुमार तृतीय जैसे नौकरशाहों को अच्छे पदों पर तैनात करने से परहेज किया गया. संजय अग्रवाल को मुख्य सचिव पद पर तैनाती के दो घंटे बाद ही चिकित्सा विभाग भेज दिया गया. संजय को हटवाने में पंचम तल की एक महिला आईएएस अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसी के चलते तेजतर्रार आईएएस अधिकारी शैलेश कृष्ण को भी अच्छी जगह तैनाती नहीं मिल सकी. आईएएस माजिद अली को पहले अच्छी पोस्टिंग दी गई, बाद में उन्हें चलता कर दिया गया. जे पी शर्मा को चिकित्सा शिक्षा विभाग में डाल दिया गया. प्रवीर कुमार को आजम खां के साथ शहरी नगर विकास विभाग में लगा दिया गया. आईएएस अशोक कुमार तृतीय को राजस्व विभाग और वीरेश कुमार को रेशम वस्त्र उद्योग विभाग भेज दिया गया.

प्रदेश में कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार उन तेजतर्रार अधिकारियों की अनदेखी कर रही है, जिन्होंने मायावती राज में अच्छा काम किया था. बात चाहे बृजलाल की हो या फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों शैलजाकांत मिश्र, रिजवान अहमद, सुबेश कुमार सिंह, सुलखान सिंह, अरुण कुमार गुप्ता, डी के नागर, आर आर भटनागर, भानु प्रताप सिंह, सुजान वीर सिंह, ओ पी सिंह, ए एल बनर्जी एवं नवनीत सिकेरा की, इन सबके पास अनुभव है, योग्यता है, कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाने का जज्बा भी. बसपा सरकार के समय के पंचायत अध्यक्षों को भी हटाया जा रहा है. करीब डेढ़ वर्ष पूर्व निर्विरोध चुने गए बसपा समर्थक जिला एवं क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है. एक दर्जन से अधिक अध्यक्षों की कुर्सी छिन गई है और कई के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा है. सिद्धार्थ नगर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लेकिन सत्ता बदली तो समर्थक ही उनके विरोधी हो गए और उनकी कुर्सी जाती रही. हमीरपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित के साथ भी यही हुआ. कन्नौज की जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी अंबेडकर, बांदा की जिला पंचायत अध्यक्ष किरन वर्मा, आजमगढ़ की मीरा आजाद, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, बागपत, मेरठ एवं बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्षों के समर्थकों ने भी बगावत कर दी. राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्षों पर भी सपा की नज़रें टेढ़ी हैं. यही खेल ब्लाक स्तर पर खेला जा रहा है. बसपा सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न निगमों एवं परिषदों के अध्यक्षों को हटा दिया गया है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह कदम इन इकाइयों की कार्य प्रणाली बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. अखिलेश सरकार ने मायावती सरकार की 26 परियोजनाओं को समाप्त कर दिया. पहले अखिलेश ने कहा था कि मायाराज में जो योजनाएं शुरू हुई हैं, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा और जिन पर काम शुरू होना है, उनकी समीक्षा की जाएगी. राज्य सरकार ने जो 26 परियोजनाएं समाप्त की हैं, वे चल रही थीं. अखिलेश सरकार के इस फ़ैसले पर बसपा द्वारा प्रश्नचिन्ह खड़ा करना जायज है. अखिलेश को बताना चाहिए कि उन्होंने योजनाएं गुण-दोष के आधार पर खत्म की हैं.

विधान परिषद में नेता विरोधी दल एवं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अधिकारियों को पत्र लिखकर स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान न देने पर चिंता जताई है. लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वार के पास बना पीतल का एक गेट काटकर गायब कर दिया गया. जेल रोड पर जगह-जगह से ग्रिल गायब हो रही है, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट न लिखाया जाना बताता है कि अखिलेश सरकार इन पार्कों को बसपा की संपति मानती है, जबकि इसमें सरकारी पैसा लगा है. डॉ. अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना को डॉ. लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना कर दिया गया. बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी डॉ. लोहिया का सम्मान करती है. सरकार उनके नाम पर कोई योजना बनाती है तो बसपा को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दलित महापुरुषों के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं को किसी अन्य के नाम पर चलाया जाना दलितों का अपमान है. पिछले दिनों राज्यपाल बी एल जोशी से मुलाकात कर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, रामवीर उपाध्याय एवं जगदीश नारायण राय ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. ■

मूर्तियों और ईको पार्क में चार खरब का घोटाला

बसपा सरकार में प्रदेश भर में फैले मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार और दलाली से नहीं बच पाए. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मायाराज में स्मारकों एवं पार्कों में मूर्तियों और खजूर के पेड़ों में चार खरब रुपये के घोटाले की बात कहकर बसपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. हो सकता है कि इस घोटाले की जांच देर सबेर सीबीआई के हाथों में पहुंच जाए. लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क और जेल रोड पर बने ईको पार्क में पत्थर के हाथियों के निर्माण में भी करोड़ो के घोटाले का खुलासा हुआ है. बीते 14 मई को पुलिस ने राजकीय निर्माण निगम पर छापेमारी की. घोटाले में निगम के पूर्व जीएम, एमडी, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं इंजीनियरों की मिलीभगत के पुख्ता सबूत मिले. पत्थर के एक-एक हाथी की कीमत 48-48 लाख रुपये थी. इन स्मारकों पर लखनऊ में ही करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. सभी कार्यों की नोडल एजेंसी लखनऊ विकास प्राधिकरण था, इसलिए सारा भुगतान उसी के माध्यम से किया गया. प्राधिकरण ने अपने करीब 1500 करोड़ रुपये इन योजनाओं में लगाए थे.

संजय सक्सेना

बंद मिलें और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी

अफ़ज़ल ईमाम मुन्ना feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर बिहार का प्रमुख ज़िला है. यहां पूर्व मध्य रेलवे का मंडलीय कार्यालय है, उत्तर बिहार का इकलौता राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है. फिर भी यह जिला औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा है. प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यहां उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं. ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की गई, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण 90 प्रतिशत इकाइयां बंद होकर खंडहर में तब्दील हो गईं, शेष बंद होने की कगार पर हैं. समस्तीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद है, ठाकुर पेपर मिल नीलाम हो चुकी है. वर्तमान उद्योग मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा इस ज़िले की प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. आज़ादी के पूर्व तत्कालीन समस्तीपुर अनुमंडल में स्थित मुक्तापुर में दरभंगा राजघराने ने रामेश्वर जूट मिल की स्थापना की थी. दलसिंह सराय में सिगरेट फैक्ट्री, समस्तीपुर एवं हसनपुर में चीनी मिल और पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों एवं मजदूरों की उपलब्धता को स्वत: प्रमाणित करती है.

उत्तर बिहार में गंगा के किनारे रेलमार्ग की स्थापना सर्वप्रथम समस्तीपुर ज़िले में मोहीउद्दीन नगर के सुल्तानपुर घाट से दलसिंह सराय होते हुए दरभंगा तक हुई. यह रेल लाइन 1874 में बिछाई गई. इसका उद्देश्य अकालग्रस्त इलाक़ों के लिए खाद्य सामग्रियों का परिवहन था. स्थाई तौर पर 1875 में दलसिंह सराय-समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन का निर्माण किया गया. रेल डिब्बों एवं इंजनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 1881 में रेलवे यांत्रिक कारखाने की स्थापना हुई, लेकिन इसकी हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है. अब यहां बड़ी लाइन के डिब्बों एवं इंजनों की मरम्मत का काम भी नहीं कराया जाता, जबकि पहले एमजी के इंजनों एवं वैगनों की मरम्मत (पीओएच) होती थी. वर्तमान में बड़ी लाइन के बाक्सन-एचएल वैगन का निर्माण कार्य हो रहा है. वह भी स्पेयर पार्ट्स के अभाव में बाधित होता रहता है. ज़िला मुख्यालय से क़रीब तीन किलोमीटर स्थित जितवारपुर (हसनपुर) में एक बड़े औद्योगिक घराने द्वारा स्थापित ठाकुर पेपर मिल कबाड़ियों की भेंट चढ़ चुकी है. वर्ष 1957 में इस मिल की स्थापना हुई थी. कुछ वर्षों तक इसमें अच्छा उत्पादन हुआ. स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी यह उद्योग मददगार साबित हुआ, लेकिन यूनियनबाज़ी से तंग आकर मिल प्रबंधन ने 29 वर्ष पूर्व 9 मई, 1982 को मिल में जो ताला लटकाया, उसे अब तक नहीं खोला जा सका. स्थिति यह आ गई कि प्रभावशाली लोगों ने मिल को नीलाम कराकर कलपुर्जे कबाड़ियों के हाथ बेच दिए और ज़मीन अपने चहेतों के नाम करा दी. अब कुछ क्वार्टर बचे हैं, उन पर भी नीलामी का ख़तरा मंडरा रहा है.

साठ के दशक में यहां 32 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेफाइट फैक्ट्री और 8 करोड़ रुपये की लागत से ऑटो मोबाइल्स स्पेयर्स फैक्ट्री लगाने के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि हरपुर एलौथ में अर्जित की गई. दोनों फैक्ट्री न लगने के कारण यह भूमि दरभंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई. बाद में प्राधिकरण ने यह ज़मीन उद्यमियों को आवंटित कर दी. इसमें फोम प्रोडक्ट्स, सीमेंट ह्यूम पाइप फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस, एवं इलेक्ट्रिक स्पेयर्स कारखाना आदि खुले, लेकिन एक-एक कर सब बंद हो गए. इसी प्रांगण में पुन: मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, समस्तीपुर डेयरी सुधा उत्पादन, शिव शक्ति एग्रो (इंडिया), पशु आहार एवं मुर्गी दाना उद्योग, सम्राट केमिकल लेबोरेट्रीज, बाला जी इंडस्ट्रीज, मैदा फैक्ट्री एवं कोल्ड स्टोरेज सहित 13 उद्योग लगे, जो चल रहे हैं. समस्तीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद है. हसनपुर चीनी मिल की हालत अच्छी नहीं है. जूट मिल में भी वर्ष में एक-दो बार तालाबंदी हो जाती है. ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों में से आठ पर जद-यू और भाजपा का क़ब्ज़ा है, जबकि दो पर राजद का. ज़िले की दोनों लोकसभा सीटों पर जद-यू का क़ब्ज़ा है. बिहार विधान परिषद में भी इस ज़िले के दो प्रतिनिधि हैं. एक राजद से और दूसरे जद-यू से.

सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से जद-यू के टिकट पर चुनाव जीतने वाले वर्तमान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने दस वर्षों तक समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. इसके पूर्व वह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे. लालू प्रसाद यादव की सरकार में वह पहली बार उद्योग राज्य मंत्री बने और नीतीश कुमार की सरकार में वह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और विधि, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री की कुर्सी पर पांच वर्षों तक विराजमान रहे, लेकिन उन्होंने समस्तीपुर के औद्योगिक विकास एवं शहर की सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया. उनके मंत्री रहते हुए न मोहनपुर में ग्रेफाइट कारखाना खुला और न समस्तीपुर चीनी मिल एवं ठाकुर पेपर मिल चालू हो सकीं. ■

बीते 9 मई को मुरैना कोतवाली में हुई घटना पुलिस-प्रशासन के लिए शर्म का विषय होनी चाहिए, लेकिन मुरैना के एसपी संजय कुमार सिंह उसे कभी- कभी हो जाने वाली घटना बता रहे हैं.

प्राथमिक शिक्षा

छह दशक बाद भी हालत जस की तस

डॉ. क़मर तबरेज़ feedback@chauthiduniya.com

हमारे देश में हर नागरिक को प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सरकार की है. चौदह साल तक की आयु के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया. क़ानून तो पास हो गया, लेकिन ज़मीनी स्थिति यह है कि बिहार में 26.21 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 8.09 प्रतिशत एवं झारखंड में 7.59 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां स्कूल की कोई इमारत नहीं है. नागालैंड में 29 प्रतिशत और मेघालय में 21 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. बिहार में 94 प्रतिशत, मणिपुर में 90 प्रतिशत, त्रिपुरा में 78 प्रतिशत, झारखंड में 76 प्रतिशत और उड़ीसा में 70 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है. बिहार में 85 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 77 प्रतिशत और पश्चिमी बंगाल में 72 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं हैं. यही नहीं, देश के हर छह में से एक स्कूल ऐसा है, जहां शौचालय नहीं है.

देश के दूरदराज़ के इलाक़ों में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का यह हाल है. बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां बच्चे हैं तो स्कूल नहीं, स्कूल हैं तो अध्यापक नहीं, अध्यापक हैं तो किताबें नहीं. ऐसे में भला हम देश के चालीस करोड़ से ज़्यादा बच्चों का भविष्य कैसे सुधार सकते हैं? जिस देश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा की यह स्थिति हो, उस देश का विश्व के विकसित देशों में शामिल होने का सपना बेमानी लगता है, क्योंकि शिक्षा के बग़ैर उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती. जब देश के नागरिकों को अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं होगी, तो फिर हम एक सभ्य समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं. हम एक जाहिल इंसान को यह कैसे समझा पाएंगे कि देश के प्रति भी उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं. चोरी, डकैती और अन्य अपराध कैसे ख़त्म होंगे? शिक्षा से ही इंसान में सोचने, समझने की शक्ति पैदा होती है.

सरकार ने हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सर्वशिक्षा अभियान के नाम से पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन अब भी देश का एक बड़ा तबक़ा अशिक्षित है. देश में अब भी पचास प्रतिशत बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते, लाखों बच्चे बंधुआ मज़दूरी करने के लिए मजबूर हैं, लाखों बच्चे सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं. कई राज्यों में ख़ासकर, लड़कियों को स्कूल की तरफ़ आकर्षित करने के लिए साइकिलें बांटी गईं. इसी प्रकार स्कूलों में मिड डे मील का प्रबंध किया गया, ताकि बच्चे लालच वश स्कूल आएं, लेकिन अब मिड डे मील और मुफ्त यूनिफार्म के नाम पर घोटालों की भी ख़बरें आने लगी हैं. होना तो यह चाहिए था कि स्कूल में ऐसा माहौल तैयार किया जाता, जिससे बच्चे स्कूल छोड़ते ही नहीं, लेकिन स्कूल पहुंचने पर मालूम हुआ कि छोटे-छोटे बच्चों को पेशाब करने के लिए बार-बार बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए स्कूल में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. नतीजा यह हुआ कि ये बच्चे पेशाब करने के बहाने स्कूल से अक्सर भाग जाते हैं. स्कूल में शौचालय न होने की वजह से लोग अपनी लड़कियों को वहां भेजना पसंद नहीं करते. इसके अलावा बहुत सी जगहों पर स्कूल खुले आकाश के नीचे चल रहे हैं. बहुत ज़्यादा धूप या बारिश में स्कूल चलाना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर पहाड़ी इलाक़ों में, जहां अक्सर वर्षा होती है.

इसके अलावा एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अधिकतर अध्यापकों को यही नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उनके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वे यह नहीं जानते कि बच्चों को शिक्षा के लिए कैसे प्रेरित किया जाए. ऐसे अध्यापकों के हाथ में बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है? 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ था, तो यह तय हुआ था कि अगले दस वर्षों में अर्थात 1960 तक देश के हर बच्चे को शिक्षित कर दिया जाएगा, लेकिन पचास वर्षों से अधिक समय बीत गया और अब तक यह ख्वाब अधूरा है. 1950-51 में देश में कुल दो लाख दस हज़ार प्राइमरी स्कूल थे, जो 2010-11 में बढ़कर 13 लाख 62 हज़ार 324 हो चुके हैं. इसी प्रकार 1950-51 में देश में सरकारी अध्यापकों की कुल संख्या 5 लाख 38 हज़ार थी, जो अब 64 लाख 3 हज़ार 234 हो चुकी है. इसके बावजूद पूरा देश शिक्षित नहीं हो पाया है. अब तो सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किए बग़ैर यह सपना कैसे पूरा हो सकता है. ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें इस ओर पूरा ध्यान दें और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल देश का भविष्य तय करेंगे और जब शिक्षा ही नहीं होगी तो हम तरक्क़ी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाएंगे. ■

पहली से आठवीं कक्षा तक के आंकड़े

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ज़िला	ब्लॉक	गांव	स्कूल	एनरोलमेंट	अध्यापक
अंडमान-निकोबार द्वीप	3	9	202	406	53353	5282
आंध्र प्रदेश	23	1128	25748	107597	11272063	572976
अरुणाचल प्रदेश	16	80	3181	4441	332065	18428
असम	23	145	21720	64653	5822163	270811
बिहार	38	536	39357	69379	19974702	344688
चंडीगढ़	1	20	79	184	149002	6179
छत्तीसगढ़	16	146	21997	51423	4637444	190489
दादर-नगर हवेली	1	1	70	297	59064	1468
दमन दीव	2	2	39	110	26143	880
दिल्ली	9	63	1165	5021	2710483	75515
गोवा	2	11	620	1491	181923	7733
गुजरात	26	228	19727	40746	8147024	260303
हरियाणा	21	119	7557	20869	3475846	132854
हिमाचल प्रदेश	12	121	10078	17439	1035627	64334
जम्मू-कश्मीर	22	200	7225	27095	1998138	149531
झारखंड	24	259	27724	44675	6840744	166672
कर्नाटक	34	203	28467	59484	7670492	297948
केरल	14	164	1893	12924	3438905	162997
लक्षद्वीप	1	3	10	46	10285	727
मध्य प्रदेश	50	318	54275	137113	15493689	436719
महाराष्ट्र	35	378	43683	97278	16081769	533813
मणिपुर	9	35	2103	3878	503682	27042
मेघालय	7	44	6070	12414	660129	40640
मिजोरम	8	36	809	2904	235327	16387
नागालैंड	11	48	1382	2826	411383	20367
उड़ीसा	30	419	38028	65730	6556425	249563
पुडुचेरी	4	6	147	709	182627	11716
पंजाब	20	142	13321	30858	3964427	204967
राजस्थान	33	249	38711	105190	12003827	460214
सिक्किम	4	9	774	1201	126542	10493
तमिलनाडु	30	413	19305	55175	9797264	333774
त्रिपुरा	4	45	1016	4386	610098	32004
उत्तर प्रदेश	71	969	95407	201475	32019087	728755
उत्तराखंड	13	95	11841	22720	1638492	72668
पश्चिमी बंगाल	20	485	40858	90187	14931765	494297
सभी राज्य	637	7129	584589	1362324	193051999	6403234

मध्य प्रदेश

क़ानून से खिलवाड़

नवीन चौहान navinchauhan@chauthiduniya.com

आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की हत्या के बाद मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सुर्खियों में आ गया था. लोगों में डर व्याप्त हो गया कि अगर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या हो सकती है, तो फिर राज्य की क़ानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है. मध्य प्रदेश को आदर्श राज्य बताने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनता को अपराध एवं भयमुक्त शासन उपलब्ध कराने की बात अब एक सुखद स्वप्न बनकर रह गई है. अब भी मुरैना में दबंग खनन माफियाओं का ही राज चलता दिख रहा है. बीते 9 मई को मुरैना कोतवाली में हुई घटना पुलिस-प्रशासन के लिए शर्म का विषय होनी चाहिए, लेकिन मुरैना के एसपी संजय कुमार सिंह उसे कभी- कभी हो जाने वाली घटना बता रहे हैं.9 मई को दिल्ली पुलिस की एक टीम फर्जी लैंड डील में एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी संजीव कंषाना की तलाश में मुरैना पहुंची. एसआई संदीप पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम जब संजीव को गिरफ्तार करके मुरैना कोतवाली ले गई, तभी उनके पीछे लगभग 50 हथियारबंद लोग भी कोतवाली पहुंच गए और उन्होंने कोतवाली को घेर लिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मारपीट करके उसके असलहे छीनने की कोशिश की और संजीव को छुड़ाकर फरार हो गए. यह पूरी घटना घटती रही और मुरैना कोतवाली पुलिस इस दौरान मूकदर्शक बनी खड़ी रही. बाद में संजीव कंषाना के छोटे भाई एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुराज कंषाना और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 307, 398, 353, 225, 224, 180, 186 और मध्य प्रदेश दस्यु अधिनियम की धारा 11, 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. आईजी ने तत्काल दोनों भाइयों के ऊपर दस हज़ार रुपये का ईनाम घोषित कर दिया. 9 मई को ही मुरैना के चिन्नौनी थाने के टीआई हितेंद्र राठौर और कुछ सिपाहियों को रेत माफिया ने ट्राली से कुचलने की कोशिश की और फायरिंग भी की. इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर पुलिस दबंगों और माफियाओं के आगे पंगु ज़रूर नज़र आई. पुलिस पर हो रहे हमलों से लोग सकते में हैं. उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं रह गया है. उनका कहना है कि जो पुलिस खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, वह उनकी क्या रक्षा करेगी. नरेंद्र कुमार की हत्या की जांच के दौरान सीबीआई को जो सबूत मिले हैं, उनसे यह जाहिर हुआ कि नरेंद्र कुमार की हत्या एक हादसा ज़रूर थी, मगर मुरैना में खनन माफियाओं का बोलबाला है. सीबीआई को जांच में मालूम हुआ कि मुरैना में करोड़ों रुपये का अवैध पत्थर खनन का कारोबार होता है. राज्य सरकार अवैध खनन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने की बात तो करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है. पूंजीपतियों, दबंगों एवं माफियाओं के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने में पुलिस कतरा रही है. यह खनन सभी पार्टियों की साझीदारी से किया जा रहा है. आपसी साठगांठ की वज़ह से सरकार और विपक्ष दोनों ही इस विषय पर मूक हैं.

नरेंद्र कुमार की हत्या हुए दो माह से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन मुरैना पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली. प्रदेश सरकार ने भी मुरैना में क़ानून व्यवस्था बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की. एक तरफ तो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वह एक ऐसे जिले की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य की छवि धूमिल हो रही है. ऐसी घटनाएं सरकार के प्रति जनता में अविश्वास बढ़ाती है. भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करने के दावे कर रही है, ऐसे में अगर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया और कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश नहीं की तो भाजपा के सपनों का महल टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. ■

क्या बाबा रामदेव उनके मुद्दे को जनलोकपाल और काले धन के मुद्दे के साथ जोड़ पाएंगे या फिर वह केवल अपने आंदोलन के साथ या अपने मंच से इस मुद्दे को उठाएंगे.

रामदेव मुस्लिमों के लिए लड़ेंगे

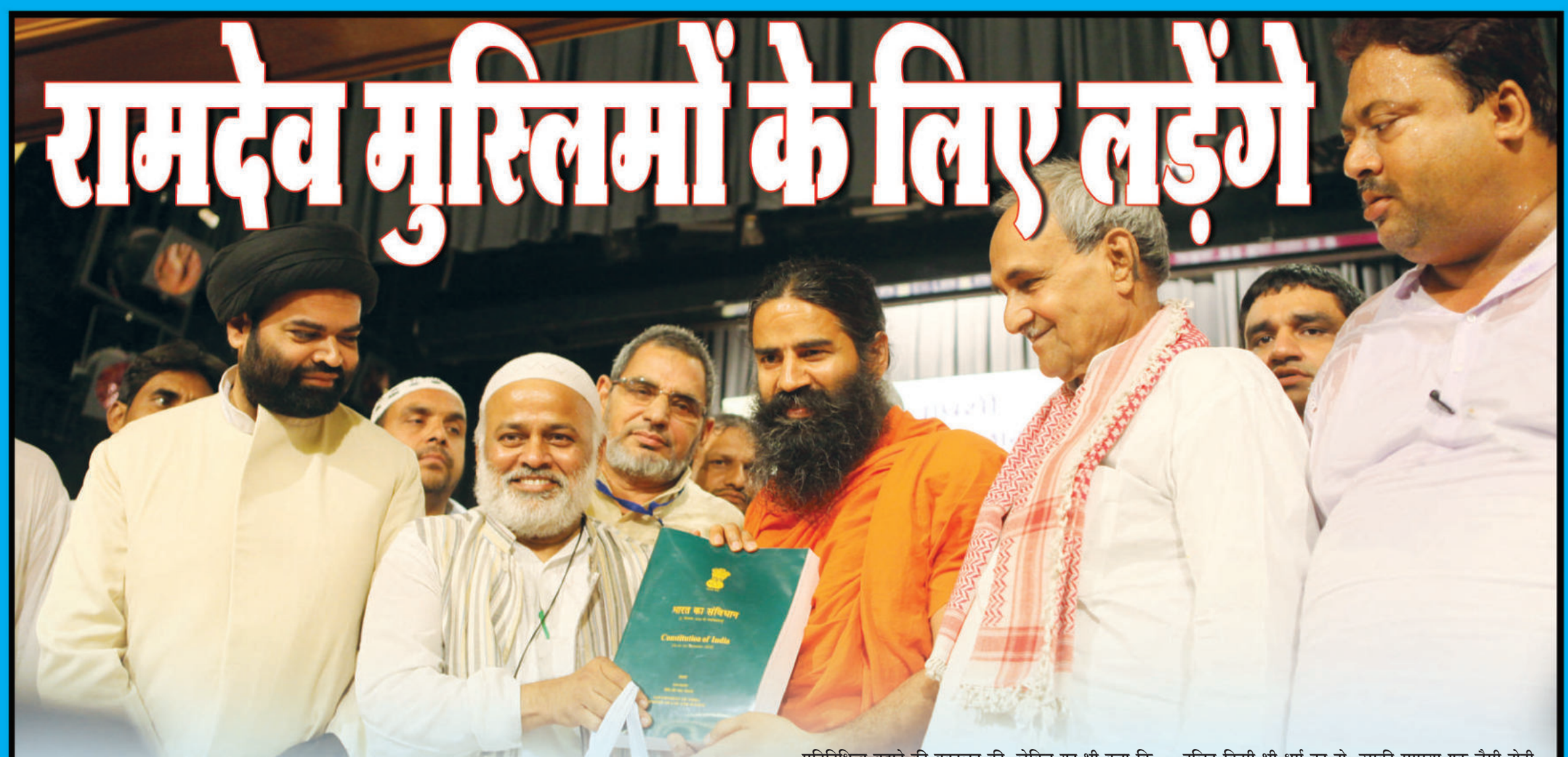

दलित दलित होता है, न कि हिंदू या मुसलमान. सभी धर्मों में उनकी समस्याएं एक जैसी होती हैं. फिर मुस्लिम दलितों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उन्हें उन लाभों से वंचित क्यों रखा जा रहा है, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वाले दलितों को दिए जा रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिले और अनुच्छेद-341 से धार्मिक प्रतिबंध समाप्त हो. भ्रष्टाचार केवल धन के गबन को नहीं कहा जाता है, बल्कि किसी को उसके अधिकारों से वंचित करना भी भ्रष्टाचार है. इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एक बैठक की, जिसमें काले धन को देश में वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव को बुलाया गया, जिन्होंने उसका समर्थन किया और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में साथ मिलकर लड़ने की बात कही.

राजीव कुमार
rajiv@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार का मतलब केवल घोटालों से नहीं है. भ्रष्टाचार का मतलब लोगों के अधिकारों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना भी है. काले धन को देश में वापस लाने के मुद्दे पर सरकार से लड़ रहे बाबा रामदेव और जन लोकपाल लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे अन्ना हज़ारे के बीच एकता स्थापित हो गई. दोनों को यह समझ में आ गया कि उनका साझा शत्रु एक है और अगर देश को भ्रष्टाचार रूपी दानव के बढ़ते प्रभाव से मुक्त कराना है तो साथ आना ही पड़ेगा. इसी बीच एक मुस्लिम संगठन को भी यह लगा कि संघर्ष करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो धर्म, जाति एवं संप्रदाय के बंधन से ऊपर उठकर सामाजिक अन्याय के शिकार लोगों के लिए संघर्ष कर सकें. हालांकि बाबा रामदेव पर यह आरोप लगता रहा है कि वह संघ के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन इस आरोप को इस संगठन ने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को कमज़ोर करने और धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश क़रार दिया. पूर्व सांसद एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा द्वारा बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे इलियास आज़मी ने कहा कि सरकार बाबा रामदेव को संघ के साथ जोड़कर भ्रष्टाचार विरोधी इस मुहिम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है. उनका कहना था कि जब 1974 में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के लिए ख़तरा बन गईं इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाया था, तब भी कांग्रेस ने उन्हें संघ का एजेंट क़रार दिया था, ताकि मुसलमानों को उस आंदोलन से दूर रखा जा सके. लेकिन मुसलमान उनकी इस चाल को समझ गए और उन्होंने जेपी का साथ न केवल आंदोलन में दिया, बल्कि चुनाव में भी कांग्रेस के ख़िलाफ़ मतदान किया, जिसका नतीजा कांग्रेस की भारी पराजय के रूप में सामने आया.

इलियास आज़मी ने दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में बाबा रामदेव का साथ मांगा. उन्होंने अनुच्छेद-341 से धार्मिक प्रतिबंध ख़त्म करने की मांग की और इस प्रतिबंध को दलित मुस्लिमों के पिछड़ेपन का कारण बताते हुए कांग्रेस को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ख़तरा कांग्रेस से है. उनका कहना था कि दस नहीं, सौ नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों का उतना नुक़सान नहीं कर पाएंगे, जितना नुक़सान कांग्रेस सरकार ने किया है. आज मुस्लिम समुदाय जिस तरह ग़रीबी, बेरोज़गारी एवं पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, उसके लिए कांग्रेस सरकार ज़िम्मेदार है. उन्होंने बाबा रामदेव से मुस्लिम समुदाय के इस वर्ग की लड़ाई में साथ देने का आग्रह किया. ऑल इंडिया मुस्लिम युनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एम एजाज़ अली ने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस सरकार के साथ-साथ उन नेताओं को भी ज़िम्मेदार ठहराया, जो राजनीति में बड़े ओहदे प्राप्त करने के लिए अपने समुदाय के लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं. उन्होंने राजनीति में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वकालत की, लेकिन यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर किया जाना सही नहीं है. अभी तक सियासत की भेंट चढ़ रहे इस समुदाय को जागना होगा और राजनेताओं की साज़िश को समझना होगा. उनका निशाना कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय के उन तथाकथित नेताओं की ओर था, जो इस समुदाय के अधिकारों के लिए कुछ करने की बजाय अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने तक ही स्वयं को सीमित कर देते हैं.

डॉ. एजाज़ ने सच्चर कमेटी का भी हवाला दिया, जिसमें मुस्लिमों की स्थिति बदतर होने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि अभी भी 85 फ़ीसदी मुसलमान अशिक्षित हैं और 80 फ़ीसदी मुसलमानों की स्थिति दलितों की तरह है. इस मंच पर आए पसमांदा मुस्लिम नेताओं ने वही बात कही, जो हिंदू दलित आंदोलन करने वाले नेता कहते हैं. उनका कहना था कि उनके समुदाय का दर्द वही समझ सकते हैं, क्योंकि वे इस दर्द को झेल रहे हैं. वे इस तरह की बात कहकर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को दु:खी कर सकते हैं, उन्हें अगड़े मुसलमानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है. बाबा रामदेव ने अनुच्छेद-341 से धार्मिक प्रतिबंध ख़त्म करने और नौकरियों एवं राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मुद्दे का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि दलित दलित होता है, न कि हिंदू और मुसलमान.

रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में भी मुस्लिम को आरक्षण की बात कही गई है. अगर इस बैठक में उठाए गए मुद्दों को आगे बढ़ाया गया तो आंदोलन मज़बूत होगा, लेकिन इसके लिए टीम अन्ना, बाबा रामदेव और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा को एक साथ खड़ा होना होगा.

दलित किसी भी धर्म का हो, उसकी समस्या एक जैसी होती है. इसलिए अगर हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर मुस्लिम समुदाय के दलितों को इस तरह के लाभों से वंचित क्यों किया जा रहा है? यह सरासर अन्याय है. बाबा रामदेव ने कहा, अगर आपके धार्मिक अगुवा आपकी समस्याओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो अब हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे. बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मज़बूत करने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि केवल आरक्षण से ही समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए काले धन को देश में लाने की ज़रूरत है, जिससे भारत का समग्र विकास हो सके. उन्होंने एक सक्षम लोकपाल की बात भी की, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके.

इस अवसर पर भ्रष्टाचार पर बात हुई, मुस्लिमों के पिछड़ेपन के कारणों पर बात हुई और बाबा रामदेव, डॉ. उदितराज एवं वेद प्रताप वैदिक जैसे लोगों को बुलाया गया, ताकि इनका समर्थन हासिल किया जा सके. इस बैठक में जो प्रमुख मुद्दे उठाए गए, उनमें सिटीजन चार्टर लागू करना, काला धन वापस लाना, जन लोकपाल बिल पारित करना, अनुच्छेद-341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाना और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना शामिल था. काले धन को देश में वापस लाने के लिए लड़ रहे बाबा रामदेव को बुलाया गया. मुस्लिम दलितों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से हिंदू दलितों को परेशानी हो सकती है, इसलिए डॉ. उदितराज को बुलाया गया, जिन्होंने इसका समर्थन भी किया. लेकिन इसमें टीम अन्ना के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं बुलाया गया. अभी बाबा रामदेव और अन्ना हजारे साथ हैं, लेकिन अन्ना हजारे के कुछ सहयोगियों का कहना था कि उनका कोई साझा कार्यक्रम नहीं है. दोनों भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों एक-दूसरे का साथ देंगे, लेकिन डॉ. एजाज़ का कहना था कि उनके मुद्दों को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में शामिल किया जाए. क्या बाबा रामदेव उनके मुद्दों को जन लोकपाल और काले धन के मुद्दे के साथ जोड़ पाएंगे या फिर वह केवल अपने आंदोलन के साथ या अपने मंच से इन मुद्दों को उठाएंगे, अभी यह साफ नहीं है. जिस तरह बाबा रामदेव और अन्ना हजारे साथ आए, उसी तरह अगर एक अन्य संगठन यानी मुस्लिम संगठन उनके साथ जुड़ता है तो बेशक आंदोलन को मज़बूती मिलेगी. पिछले दिनों टीम अन्ना से एक मुस्लिम चेहरे शमून कासमी को बाहर निकाला गया. तर्क जो भी दिया गया हो, लेकिन टीम अन्ना के इस फ़ैसले से मुस्लिम समुदाय में थोड़ी नाराज़गी तो थी ही. फिर से एक मौक़ा मिला है, जिससे मुसलमानों को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जोड़ा जा सकता है. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में भी मुस्लिम को आरक्षण की बात कही गई है. अगर इस बैठक में उठाए गए मुद्दों को आगे बढ़ाया गया तो आंदोलन मज़बूत होगा, लेकिन इसके लिए टीम अन्ना, बाबा रामदेव और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा को एक साथ खड़ा होना होगा. जो भी हो, बाबा रामदेव पर हिंदूवादी होने के जो आरोप लग रहे हैं, उन पर इस बैठक से विराम लगेगा और उनके आंदोलन का आधार व्यापक एवं मज़बूत होगा. ■

मेरी दुनिया.... रामदेव का नया आसन!

अन्ना चर्चा समूह

जनलोकपाल पर सर्वे के नतीजे

इस हफ्ते आईएसी टीम ने एक सर्वे किया था. आइए, आज उसके नतीजों को देखते हैं. सर्वे में 4 सवाल पूछे गए थे और 6948 लोगों ने देश भर से ई-मेल द्वारा अपने जवाब भेजे . नतीजों के आधार पर बनी टेबल नीचे दी गई है :

सारांश (सर्वेक्षण 10 मई, 2012)	हां %	नहीं%	हां	नहीं
संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि के 162 सांसद हैं. देश में 4200 विधायक हैं, जिनमें 1170 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. इसके अलावा इन्हीं में से कई लोगों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं. क्या आपको लगता है कि ऐसे सांसद और विधायक जन लोकपाल बिल पास करेंगे?	4	96	276	6650
34 केंद्रीय मंत्रियों में 16 ऐसे मंत्री हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा मंत्रिमंडल जनलोकपाल पास करेगा?	4	96	298	6672
क्या आपको लगता है कि जब साफ़ छवि के लोग संसद या विधानसभाओं में आएंगे तभी जनलोकपाल बिल पास हो पाएगा?	93	7	6488	460
क्या आपको लगता है कि अन्ना जी को अच्छे और साफ़ छवि के उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए?	82	4	5736	253
			sample	6948

एक बार फिर यह ज़ाहिर हो गया कि भारत की जनता को इस संसद और विधानसभाओं में बैठे सांसदों और विधायकों पर विश्वास नहीं रहा, या यह भी कह सकते हैं कि जनता को पूरा विश्वास हो गया है कि यह संसद एक सशक्त जनलोकपाल नहीं पास करेगी. ऐसा लग रहा है कि खानापूर्ति करने के लिए यह सरकार एक लचर बिल पास करेगी. सारी पार्टियां भी अपनी मंज़ूरी दे चुकी हैं. ऐसी सूरत में हम चुप नहीं बैठेंगे. हमारी मांग एक सशक्त लोकपाल रही है और रहेगी. मेरी आप सबसे अपील है कि एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए. आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है. लेकिन आंदोलन का आकार इतना बड़ा होगा कि सारी पार्टियां और उसमें भ्रष्ट नेता जनता की आवाज़ से हिल जाएंगे और उन्हें जनता की बात माननी ही पड़ेगी. सवाल उठता है कि जनतंत्र में सरकार तानाशाही पर उतर आई है और जनता की नहीं चल रही. सर्वे के आख़िरी सवाल में पूछा गया था कि बिना ख़ुद चुनाव में खड़े हुए क्या अन्ना जी को साफ़ सुथरे छवि के लोगों का समर्थन करना चाहिए. 82 प्रतिशत जनता ने कहा है कि अन्ना जी को साफ़ छवि के उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए. इस सवाल में जनता ने हां या ना के अलावा अपनी राय भी दी है. जनता का कहना है कि राजनीति बहुत ही घिनौनी और गंदी चीज़ है. एक व्यक्ति ने यह राय दी है कि अन्ना जी जैसे साफ़ छवि के लोगों को राजनीति की तरफ़ देखना भी नहीं चाहिए.

आप इस विषय पर चर्चा करें कि क्या सरकार की ऐसी तानाशाही का कोई जवाब नहीं है? अबकी बार हमें ऐसा जवाब ढूंढना है, जिसके चलते हमें फिर सरकार के सामने झोली न फैलानी पड़े. सरकार को समझ में आए कि मालिक कौन है और सेवक कौन. अबकी बार व्यवस्था परिवर्तन के रूप में जवाब ढूंढना है.

जयहिंद
अरविंद केजरीवाल

चर्चा समूह के अनुभव

मैं और मेरे कई साथी मिलकर एक चर्चा समूह राजीव चौक के पास चलाते हैं. इस समूह में ज़्यादातर लोग गार्ड, ड्राइवर या सब्ज़ी बेचने वाले हैं. हर सप्ताह यह चर्चा समूह रविवार दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक होता है. इस दौरान वहां आए सभी भागीदारों के नाम, फ़ोन नंबर और उपस्थिति लिखी जाती है. उनसे मिले सभी अच्छे सुझावों को लिखा जाता है और अगर उनकी कोई भी समस्या होती है तो उनको भी सुझाव दिए जाते हैं. यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि पढ़ा-लिखा न होकर भी, मैं चर्चा समूह द्वारा इस आंदोलन का एक सक्रिय भाग हूं.

विजय बाबा, *राजीव चौक, दिल्ली*

सभी इस बात में एकमत थे कि हमें भ्रष्टाचारियों की चालों से सावधान रहना होगा और वे बार-बार जो हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया किए बिना अपने काम में जुटे रहना है. जीत हमारी ही होगी. इस चर्चा समूह में महीने में एक बार मोहल्ला सभा करने पर भी सहमति व्यक्त की गई. स्थानीय पार्षद के साथ मोहल्ला सभा की तिथि की वह शीघ्र ही घोषणा करेंगे.

कीर्ति पाठक, *अजमेर, राजस्थान*

उच्च एवं मध्य आय वर्ग को धनोपार्जन केसाथ साथ राष्ट्र धर्म को भी ज़रूरी मानते हुए उसमे अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, अब वो समय आ गया है कि जब सिर्फ़ बातों से काम चलने वाला नहीं है, राजनीति का स्वरुप बदले बिना कुछ भी होने वाला नहीं है.

गणेश तिवारी, *कानपुर.*

कांग्रेस अन्ना से डर गई है

महाराष्ट्र दौरे पर निकले अन्ना हजारे की यात्रा जब नागपुर पहुंची तो उनके क़ाफ़िले पर नागपुर के चिटणिस पार्क में कुछ युवाओं ने पत्थरबाज़ी की. ये युवा युवक कांग्रेस के सदस्य थे. हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुक़सान नहीं हुआ, लेकिन यह घटना बताती है कि अन्ना हजारे के महाराष्ट्र दौरे को लेकर कांग्रेस में किस हद तक बेचैनी बढ़ी हुई है. पुलिस ने युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को इस घटना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार भी किया है. यह घटना 16 मई को तब घटी, जब अन्ना हजारे नागपुर पहुंचे थे और शाम 6 बजे पत्रकार वार्ता के बाद चिटणिस पार्क में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे. इस पार्क में शहर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्ना हजारे के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान अन्ना हजारे के क़ाफ़िले पर पत्थरबाज़ी की घटना घटी. इस घटना में किसी को चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन एक गाड़ी ज़रूर क्षतिग्रस्त हो गई.

दरअसल, जबसे अन्ना हजारे ने यह घोषणा की है कि वह अपने अगले आंदोलन की तैयारी 2014 के लोकसभा चुनाव और जनलोकपल क़ानून को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तबसे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है. ऊपर से महाराष्ट्र में एक मज़बूत लोकायुक्त क़ानून की मांग से भी महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार की नींद उड़ी हुई है. अन्ना साफ़-साफ़ कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं है, तभी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए सक्षम क़ानून नहीं बन सका है. ग़ौरतलब है कि 2014 में ही लोकसभा के साथ-साथ महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी चुनाव होना है. अन्ना हजारे यह कह रहे हैं कि इन चुनावों में साफ़ छवि के लोगों को जिताना है, ताकि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक मज़बूत क़ानून बनाया जा सके. इसके अलावा जून के पहले सप्ताह में अन्ना हजारे बाबा रामदेव के साथ दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे. ज़ाहिर है, अन्ना का रामदेव के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ना, कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. यह बात कांग्रेस भी समझ रही है. नागपुर की यह घटना शायद इसी झुंझलाहट का नतीजा है. ■

आप अपनी प्रतिक्रिया हमें 09718500606 पर फोन करके या पर ई-मेल करके भेज सकते हैं. अगर आप अपने चर्चा समूह की कोई वीडियो बनाते हैं या फोटो खींचते हैं तो हमें ज़रूर भेजें. इस बार आपके चर्चा समूह में कितने लोग आए, यह आप हमें SMS करके ज़रूर बताएं. SMS करने का वही तरीक़ा है-DF<space> आपका पिन कोड <space> चर्चा समूह में कितने लोग आएं तो आप 09212472681 नंबर पर निम्न SMS करेंगे.

अन्ना चर्चा समूह से जुड़े सवाल आप हमें *ईमेल: sawal@chauthiduniya.com* पर भेज सकते हैं.

सोलहवीं शताब्दी में जब मुगल बादशाहों का राज्य चरम शिखर पर पहुंचा, तब भारत में चांदी के सिक्के ख़ूब प्रचलित थे. भारत में अकबर महान जैसा सारे देश में एक शासन कभी हुआ ही नहीं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

सबसे आसान माध्यम

इतना सब कह चुकने के बाद एक मूल प्रश्न खड़ा होता है कि पैसा है क्या? किस चीज को हम पैसा कहें? कोई भला आदमी बहुत पैसे वाला है तो यह पैसा है क्या? अमुक व्यक्ति के पास बहुत रुपया है, यह रुपया है क्या? यानी रुपया–पैसा, धन–दौलत, रकम–वित्त, कुछ भी कहें, यह जानना ज़रूरी है कि इसका स्वरूप क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है? जैसा कि हम कह चुके हैं कि आदमी के लिए दैनिक जीवनोपयोगी जो भी वस्तुएं हैं, जैसे अन्न, कपड़ा, रहने को मकान इत्यादि, ये सब निश्चय ही धन हैं. मसलन गाय, भैंस, बकरी दूध देती है. दूध से मक्खन, दही इत्यादि अनेक खाद्य पदार्थ बनते हैं, लिहाज़ा ये पशु भी धन ही हैं. ज़मीन से अनाज पैदा होता है, रुई पैदा होती है तो ज़मीन भी धन ही है. घोड़े, बैल, गधे इत्यादि पशु सवारी या बोझा ढोने के काम आते हैं, अतएव वे भी धन हैं. सारांश यही है कि मानवोपयोगी जो–जो वस्तुएं आपके अधिकार में हैं, वे सब वित्त हैं, धन हैं.

अब आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है. रेलगाड़ी में सवारी करने से पहले आप किसी को यह नहीं कह सकते कि मेरे पास 1 भेड़ या बकरी है, सो यह ले लीजिए और बदले में मुर्गियां या अंडे या साग–सब्जी दे दीजिए. शायद ऐसी स्थिति कभी आदिकाल में रही होगी, पर अब तो सैकड़ों, बल्कि हज़ारों वर्षों से इन सब व्यापारों के लिए एक बहुत ही सुगम माध्यम बना दिया गया है. वह है, धातु के बने हुए सिक्के. सोना या चांदी बहुमूल्य धातु मान ली गई. कुछ तो इनकी दुर्लभता के कारण, कुछ सार्वभौम उपयोगिता के कारण, सभ्य मानव समाज ने इन क़ीमती धातुओं को वस्तु क्रय–विक्रय या

अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो नोट 100 या 1000 रुपये का है, वह 6 इंच लंबे, 4 इंच चौड़े काग़ज़ का टुकड़ा है, जिस पर इतनी ज़्यादा छपाई हो गई है कि लिखने में काम आ नहीं सकता. शायद कोई एक नए पैसे के सौ या पचास की दर में भी उसे न पूछे, पर उसकी क़ीमत 100 रुपये या 1000 रुपये इसलिए है कि वह 100 रुपये या 1000 रुपये क़ीमत की वस्तुएं प्राप्त करा सकने का अधिकार पत्र है. आप अन्न, वस्त्र धन, पशु धन कुछ भी ख़रीद लीजिए, बदले में वे काग़ज़ के टुकड़े दे दीजिए, उनका उचित मूल्यांकन होगा. जिस तरह से सैकड़ों वर्ष पहले राजा लोग बेईमानी से सिक्कों में खोट मिलाकर चांदी या सोने की मात्रा कम कर दिया करते थे, इस वक्त की सरकारें भी नोट ज़्यादा छापकर एक प्रकार से उसी तरह नोटों में जो धन है, उसे कम कर देती हैं.

आदान–प्रदान का सुगम माध्यम बना लिया. आज से कोई 3–4 हज़ार वर्ष पूर्व महाराजा अशोक से भी पहले भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हो गया था.

दस हज़ार वर्ष पहले भगवान रामचंद्र के युग में या इससे भी पहले वैदिक युग में कई जगह स्वर्ण धेनुओं का वर्णन आता है. स्वर्ण धेनु एक प्रकार का सिक्का था, जो सोने का बना था, जिस पर गाय की आकृति अंकित थी. ऐसे अनेक सिक्के मोहनजोदड़ो में और अन्य अनेक पुरातत्व अन्वेषणों में कई जगह उपलब्ध हुए हैं. अजंता या एलोरा की गुफाओं में कई जगह स्वर्ण सिक्कों के संकेत प्राप्त होते हैं. कहने का तात्पर्य यही है कि भारत में शायद विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा यह धातु मुद्रा का प्रचलन पहले हो चुका था. सोलहवीं शताब्दी में जब मुगल बादशाहों का राज्य चरम शिखर पर पहुंचा, तब भारत में चांदी के सिक्के ख़ूब प्रचलित थे. भारत में अकबर महान जैसा सारे देश में एक शासन कभी हुआ ही नहीं. अतएव अलग–अलग राजा या मंडलेश्वर अपने–अपने सिक्के चलाया करते थे. इनमें मात्रा में कमबेसी चांदी रहा करती थी. उसी हिसाब से इनकी वास्तविक क़ीमत का अंदाज़ा लगा लिया जाता था. कोई भी राजा, जो प्रजा के साथ अन्याय करना चाहता था या जो ख़ुद अपने ऐशोआराम में फिजूलख़र्च करता था, वह चालाकी से अपनी टकसाल के कर्मचारियों द्वारा सिक्कों में चांदी या सोने की मात्रा कम करवा देता था, जिससे बिना कुछ करे–धरे उसकी धनराशि द्विगुणित या ज़्यादा हो जाया करती थी. जब लोगों को पता चलता तो सभी वस्तुओं की क़ीमत उसी अनुपात से बढ़ जाया करती थी. मज़दूरों की मज़दूरी भी बढ़ जाती थी.

भारत में उन दिनों कोई निश्चित आर्थिक धरातल तो था नहीं, इसलिए ये सब जालसाजियां भी बहुत बड़ा विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकी थीं. कहा जाता है कि एक बादशाह ने एक दिन के लिए एक भिश्ती को दिल्ली का शहंशाह बना दिया था और उसने उसी दिन चमड़े के सिक्के का चलन करा दिया था. उसके हिसाब से उसकी फटी हुई चमड़े की मशक ज़्यादा मूल्यवान वस्तु थी, बनिस्पत उन धातुओं से, जिनके सिक्के उस वक्त प्रचलित थे. ख़ैर, चमड़े के सिक्के भले ही एक दिन चले हों, पर इससे यह नया दृष्टिकोण समझ में आता है कि शासन यदि किसी भी वस्तु को बिना धन के भी धन मनवाना चाहे तो कुछ समय के लिए तो यह भ्रांति पैदा हो ही सकती है. सारे विश्व में सोने या चांदी को द्रव्य या धन माना जाता था. उसी को आधार बनाकर बाद में काग़ज़ के नोट छापे गए. अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो नोट 100 या 1000 रुपये का है, वह 6 इंच लंबे, 4 इंच चौड़े काग़ज़ का टुकड़ा है, जिस पर इतनी ज़्यादा छपाई हो गई है कि लिखने में काम आ नहीं सकता. शायद कोई एक नए पैसे के सौ या पचास की दर में भी उसे न पूछे, पर उसकी क़ीमत 100 रुपये या 1000 रुपये इसलिए है कि वह 100 रुपये या 1000 रुपये क़ीमत की वस्तुएं प्राप्त करा सकने का अधिकार पत्र है. आप अन्न, वस्त्र धन, पशु धन कुछ भी ख़रीद लीजिए, बदले में वे काग़ज़ के टुकड़े दे दीजिए, उनका उचित मूल्यांकन होगा. जिस तरह से सैकड़ों वर्ष पहले राजा लोग बेईमानी से सिक्कों में खोट मिलाकर चांदी या सोने की मात्रा कम कर दिया करते थे, इस वक्त की सरकारें भी नोट ज़्यादा छापकर एक प्रकार से उसी तरह नोटों में जो धन है, उसे कम कर देती हैं.

प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ. विजयी देशों ने जर्मनी पर लड़ाई में हुए नुक़सान के हर्जाने में करोड़ों–अरबों का क़र्ज़ मढ़ दिया. अब जर्मनी की इतनी कर्ज़ चुकाने की सामर्थ्य तो थी नहीं. उसने उतने ही मार्क्स (जर्मनी सिक्के) के नए नोट छापकर क़र्ज़ चुका दिया. जहां तक विदेशी क़र्ज़ चुकाने के लिए इस तरह नोट छापने पड़ें, वहां तक तो यह शायद देशभक्ति का और उचित काम भी कहा जा सकता है, पर चूंकि देश के अंदर भी सरकार ने करोड़ों मार्क्स उधार ले रखे थे, वे भी उसी तरह करेंसी बढ़ाकर चुकाने पड़े. एक बार जब जर्मनी में झूठी करेंसी हो गई तो भेदभाव कैसे रखा जा सकता था? जर्मन सरकार के छापे हुए सब नोटों का इकसार ही तो मूल्य होगा. चाहे वह नोट जर्मन नागरिक के पास हो, चाहे अंग्रेजों के पास. हालत यह हो गई कि होटल में भोजन की क़ीमत 50 लाख मार्क्स हो गई. इसी तरह एक चाय की प्याली के लिए बोरों में भर–भरकर गाड़ी भर जाए, इतने करेंसी नोट देने पड़ते. ■

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

प्राकृतिक संपदा अस्तित्व के लिए ख़तरा बनी

अमरेंद्र सुमन

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड की कोयला खदानों में लगी आग धीरे–धीरे उसके अस्तित्व के लिए ख़तरा बनती जा रही है. कोयले के लगातार दोहन और तस्करी ने इस प्राकृतिक संपदा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया. गोड्डा जिले में स्थापित ललमटिया कोल परियोजना झारखंड में उत्तम कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है. यहां से निकलने वाले कोयले से विद्युत उत्पादन कर बिहार एवं पूर्वी बंगाल को रोशनी प्रदान की जाती है, लेकिन वर्षों से धू–धू कर जल रहे इस क्षेत्र के कोयले पर केंद्र अथवा राज्य सरकार की निगाह अभी तक नहीं गई और न नष्ट हो रही इस राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने का कोई सार्थक प्रयास किया जा रहा है. आग की वजह से आसपास के इलाकों से लोगों का पलायन हो रहा है. कोयला माफिया इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं.

हजारों टन कोयला प्रतिदिन बाहर भेजा जा रहा है. जिला मुख्यालय गोड्डा से महज 30 किमी की दूरी पर राजमहल परियोजना अंतर्गत ईसीएल ललमटिया से प्रति वर्ष लाखों टन कोयला निकाला जाता है, जिसे बिहार (कहलगांव विद्युत परियोजना) और पश्चिम बंगाल (फरक्का विद्युत परियोजना) को भेजा जाता है. 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में दक्षिण बिहार (अब झारखंड) के तीन स्थानों यानी तत्कालीन गोड्डा (अनुमंडल) धनबाद एवं रांची के आसपास मिलने वाली प्राकृतिक संपदा के राष्ट्रीयकरण को स्वीकृति प्रदान की गई थी. इन स्थलों पर भूगर्भशास्त्रियों द्वारा सर्वे कराने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया था कि राजमहल में दो सौ वर्षों तक कोयला खत्म नहीं हो सकता. इस निष्कर्ष ने क्षेत्र के विकास

पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला, अलबत्ता निजी कंपनियों ने यहां अपना डेरा ज़रूर डाल दिया.

ललमटिया में पहली बार एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइंस कनाडा सरकार को पांच वर्ष की लीज पर दे दी गई. जिले के भादो टोला ग्राम के समीप कोयला खुदाई का काम जोर–शोर से किया जा रहा है. उक्त स्थल पर पिछले डेढ़–दो वर्षों से जबरदस्त आग की लपटें उठ रही हैं, लेकिन उसे बुझाने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं. इतने बड़े क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के लिए यह दावा किया जा रहा है कि आग को मिट्टी डालकर बुझाने का प्रयास जारी है. पिछले माह कोल इंडिया के अध्यक्ष राजमहल परियोजना के औचक निरीक्षण पर थे. कोयले में लगी आग से संबंधित कई सवाल उनसे किए गए, लेकिन उन्होंने किसी का संतोषजनक जवाब नहीं दिया. खदानों में लगी आग सत्ता के गलियारे को भी तपा रही है. राजनीतिक दल इसे राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के तौर पर तो अवश्य देख रहे हैं, परंतु इससे होने वाले फायदे को देखते हुए कोई भी इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. खदान में लगी आग के कारण आसपास के ग्रामीणों का जीना दूभर होता जा रहा है. इससे निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है. ललमटिया कोल प्रबंधन जमीन के अंदर लगी आग पर काबू पाने के लिए कोयला मंत्रालय से लगातार संपर्क में है. आग की वजह से कोयला उत्पादन लगातार प्रभावित हो रहा है. यही हाल उप राजधानी दुमका का है, जहां माफियाओं द्वारा प्रतिदिन कोयला निकाल कर बाहर भेजा जा रहा है. दुमका में शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत सरसाजोल एवं आसपास के गांवों में स्थित लुटिया पहाड़ और खड़ीजोल में एक दर्जन से ज़्यादा अवैध खदानें हैं. हाल में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने कोल इंडिया लिमिटेड के निजीकरण का मुद्दा उठाकर एक बार फिर इस बहस को जन्म दे दिया कि क्या सरकारी उद्यम काम के लायक नहीं रह गए हैं?

विश्व कोयला एसोसिएशन के अनुसार, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है. तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश है. भारत विश्व के उन देशों में है, जो विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर हैं. देश में 69 प्रतिशत विद्युत उत्पादन कोयले पर आधारित है. भारत विश्व में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शुमार किया जाता है, फिर भी हमें विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आयात करना पड़ता है. यदि हम इस संपदा का सही इस्तेमाल करें तो हमारी कई समस्याओं का हल संभव हो जाएगा. आवश्यकता है एक ठोस नीति को सख्ती से अमल में लाने की, अन्यथा काला हीरा के नाम से मशहूर इस राष्ट्रीय संपदा को धू–धू कर जलते देखना हमारी नियति बन जाएगी. (चरखा)■

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

महिलाओं की भागीदारी

देश भले ही संसद की 60वीं सालगिरह मना रहा हो, लेकिन जनतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक हमारे संसदीय लोकतंत्र में मुल्क की आधी आबादी को उसका हक़ नहीं मिल पाया है. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है. इसकी सबसे बड़ी वजह है, हमारे नेताओं में इच्छाशक्ति की कमी. यही कारण है कि एक दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी महिला आरक्षण विधेयक अभी तक लंबित है. वैसे तो पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास फ़ीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण का सपना तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि संसद और विधानसभाओं में उनका वाजिब हक़ नहीं मिलेगा.

–नीतू सिंह, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड.

साइबर अपराध

इंटरनेट ने जहां लोगों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई हैं, वहीं इसके कारण अपराधों में भी बढ़ोत्तरी हुई है. ऐसे ही अपराधों में शामिल है साइबर क्राइम. महिलाओं को परेशान करने के लिए असामाजिक तत्व इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं. पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जो लड़की से दोस्ती न होने पर फेसबुक पर फ़र्ज़ी अकाउंट बनाकर उसे बदनाम कर रहा था. उसने फेसबुक में लड़की का मोबाइल नंबर भी डाल दिया. देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती रहती हैं. सरकार को चाहिए कि वह सख्ती करे, ताकि कोई भी किसी को बदनाम करने से पहले सौ बार सोचे.

– सईद, *ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.*

ऑनर किलिंग का समर्थन

जिस प्रदेश में अधिकारी ही ऑनर किलिंग का समर्थन कर रहे हों, वहां की महिलाएं कितनी सुरक्षित हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा कोई भी आसानी से लगा सकता है. हाल में सहारनपुर के डीआईजी ने एक फ़रियादी की गुहार पर उसे फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उनकी बहन भागती तो वह उसे गोली मार देते. इसी तरह संत कबीर नगर के एसपी ने भी कहा था, पुलिस का काम चोरों को पकड़ना है, न कि ग़ायब हुई लड़कियों को खोजना. अगर पुलिस पीड़ितों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी तो वे इंसाफ़ के लिए कहां जाएंगे?

– सौरभ मालवीय, *नई दिल्ली.*

मुसलमानों की उपेक्षा

आज़ाद देश में सबसे पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था, जो मुसलमान थे. हैरानी की बात है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम होने के बावजूद मुसलमान सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में ही पिछड़े. इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के शैक्षिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वे लगातार पिछड़ते चले गए. उर्दू भाषा का विकास भी रुक गया और यह भाषा ख़त्म होती चली गई.

– मुहम्मद आसिफ़ वारसी, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

कांग्रेस–भाजपा गठबंधन करें

यूपीए गठबंधन की मुखिया कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की मुखिया भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों के कारण राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं. अगर कांग्रेस और भाजपा को राष्ट्रीय हितों की चिंता है तो दोनों पार्टियां क्षेत्रीय दलों का सहारा क्यों लेती हैं? कांग्रेस और भाजपा मिलकर केंद्र में सरकार क्यों नहीं बनातीं? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कुछ वर्षों के लिए केंद्र में गठबंधन कर लें तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति अपने आप समाप्त हो जाएगी.

–किशन नाथ शर्मा, *आगरा, उत्तर प्रदेश.*

हिंदी पत्रकारिता की ज़िम्मेदारी

चौथी दुनिया में प्रकाशित संपादकीय–हिंदी पत्रकारिता अपनी ज़िम्मेदारी समझे, पढ़कर यही कहा जा सकता है कि इसका एक–एक शब्द हिंदी पत्रकारिता की सच्चाइयां बयां करता है. ख़बर ढूंढना, ख़बरों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना एवं जानकारी देना पत्रकार का कर्तव्य और मिशन होता है. पत्रकारिता वैचारिक शून्यता में तो उभरती नहीं है. हिंदी पत्रकारिता का जो स्वरूप देश की स्वतंत्रता से पहले था, उसमें परिवर्तन आया है. औपनिवेशिक काल में यूरोपियनों द्वारा नियंत्रित अंग्रेजी पत्रकारिता की तुलना में हिंदी पत्रकारिता, ख़ासकर भाषाई पत्रकारिता ने हर स्तर पर गुणात्मक रूप से अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी पत्रकारिता भाषाई पत्रकारिता पर हावी हो गई.

–पी के प्रभाकर, *सरस्वती गार्डन, नई दिल्ली.*

अंत में

बेरोज़गारी

बेरोज़गारी के दंश से
आहत है देश इस कलंक से
बेरोज़गारी मिटाने की बात
करते हैं नेता डंके की चोट से
हर युवा के हाथ होगा रोज़गार
लगाते हैं नारे ज़ोर–ज़ोर से
सत्ता मिलते ही वादे गए भूल
हाथ जोड़कर निकल जाते हैं दूर से
यहां सत्ता बदलती रहती है
पर नहीं बदलते हालात
बेरोज़गार लड़ते हैं भूख से
बेरोज़गारी तो मिटती नहीं
बेरोज़गार झूल जाते हैं फंदों पर.

–तरुण कुमार, *आगरा, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448
राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

रेखा गूंगी गुड़िया नहीं हैं

कुछ लोगों का व्यक्तित्व आग की तरह होता है. वे जहां जाते हैं या तो लोगों को तपिश का अनुभव कराते हैं या झुलसा देते हैं और जिन्हें झुलसा नहीं पाते, उन्हें जला देते हैं. रेखा एक आग का नाम है और रेखा का संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसा ही व्यक्तित्व है. रेखा राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं. किसने उनका नाम सोनिया गांधी को सुझाया, अभी तक बात साफ़ नहीं हो पाई है. बस इतना पता चला है कि एक महिला हैं, जो राजनीति में नहीं हैं, उनकी सलाह पर रेखा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है. रेखा को राज्यसभा सदस्य बनाने से दो निशाने सधे. पहला निशाना, अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को यह संदेश भेजा गया कि आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपके दुश्मन हमारे साथ हैं. दूसरी तरफ़ देश में उन्होंने यह संदेश भेजा कि उन्हें सही व्यक्तित्व का चुनाव करना कम से कम फिल्म क्षेत्र से आता है.

अभी तक फिल्मों से जितने भी मनोनयन हुए हैं, वे सारे नाम ऐसे हैं, जो मनोनयन योग्य थे और रेखा भी उनमें से एक हैं. रेखा राज्यसभा में आईं और संयोगवश वे सभी सदस्य उस दिन राज्यसभा में उपस्थित थे, जो अक्सर राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहते हैं. घूम-घूमकर चोर निगाहों से रेखा को देखना, गैलरी में बैठे लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बन गया था. रेखा ग्यारह बजे स्मृति ईरानी के साथ राज्यसभा में पहुंचीं. हर सदस्य उनकी तरफ़ देख रहा था, कुछ आंखें फाड़े, कुछ मुस्कुराती आंखों से और कुछ ऐसे, जैसे उन्होंने ग्लैमर की देवी को देख लिया हो. सेंट्रल हॉल में जब मैंने सत्यव्रत चतुर्वेदी से पूछा, आप काफ़ी मुड़-मुड़कर रेखा को देख रहे थे तो उनका जवाब था कि भाई, उनकी फिल्में देखने के लिए लोग दौड़-दौड़ कर जाते हैं और ब्लैक में टिकट ख़रीदते हैं और जब वह राज्यसभा में आ गई हैं और हमारे साथ बैठी हैं तो हम क्यों न देखें? यह जवाब एक मासूम जवाब है और सचमुच, रेखा के लिए या रेखा को देखने की उत्सुकता भरे सवाल का सत्यव्रत चतुर्वेदी द्वारा दिया गया जवाब सारे सांसदों का जवाब माना जाना चाहिए.

अफसोस इस बात का है कि राज्यसभा टीवी ने रेखा के शपथ ग्रहण समारोह को दो महिलाओं की आपसी तनातनी में बदल दिया. यह काम दूरदर्शन, लोकसभा, राज्यसभा से अलग वे चैनल करते, जो इस खेल में माहिर हैं तो कोई अफसोस न होता, क्योंकि यह उनका काम था, लेकिन यह काम राज्यसभा टीवी ने किया. उसने एक कैमरा रेखा पर लगाया और दूसरा जया बच्चन पर. जया बच्चन टेंशन में थीं. जया बच्चन को मालूम था कि अगर वह मुस्कुराएंगी तो देश में यह माना जाएगा कि वह मज़ाक में मुस्कुरा रही हैं और अगर वह गंभीर रहेंगी तो यह माना जाएगा कि रेखा का राज्यसभा में आना शायद उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा. शायद जया बच्चन ने गंभीर रहना ज़्यादा उचित समझा. जया बच्चन को यह नहीं मालूम कि गंभीर रहते हुए उन्होंने एक छोटी सी हरकत की, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा के गंभीर सांसदों ने देखा और महसूस किया. भारतीय जनता पार्टी के सांसद शाहनवाज़ हुसैन ने मुझसे कहा, ज़रा किसी साइको एनालिस्ट से पूछिए कि जब रेखा शपथ ले रही थीं तो जया बच्चन बार-बार अपनी नाक क्यों पोंछ रही थीं. शाहनवाज़ हुसैन इतनी गंभीरता से रेखा और जया बच्चन को देख रहे होंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था. मैंने शाहनवाज़ हुसैन से कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि शाहनवाज़ हुसैन जैसे लोगों की भी साइको एनालिसिस होनी चाहिए कि वे जया बच्चन के नाक पोंछने को इतना गंभीर या फिर विश्लेषण योग्य क्रिया क्यों मान बैठे.

राज्यसभा इसलिए बनी है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ राज्यसभा में जाएं और देश की उन समस्याओं के बारे में बातचीत करें, जिन्हें लोकसभा अपनी चर्चा का विषय नहीं बनाती. दूसरी बात यह कि लोकसभा जिन विषयों पर चर्चा करती है, उन विषयों पर कहां कमी रह गई, उस चर्चा में कहां खामी रह गई, उसे भी राज्यसभा उजागर करे. राज्यसभा अपनी इस ज़िम्मेदारी को कितना और किस तरह निभाती है, इस पर तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत सालों के बाद राज्यसभा देश में चर्चा का विषय बनी है. अफसोस सिर्फ़ इस बात का है कि अगर राज्यसभा चर्चा का विषय देश की बेकारी, महंगाई, भुखमरी, बेरोज़गारी, दुःख, आंसू और तकलीफ पर चिंता की वजह से बनती तो उसका स्वागत हम अलग तरह से करते, लेकिन वह चर्चा का विषय रेखा के आने, रेखा के बैठने, रेखा की साड़ी, रेखा के कान के झुमके, जया बच्चन के तनाव भरे चेहरे और जया बच्चन के नाक पोंछने की वजह से बनी. इसके लिए भी राज्यसभा की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्यसभा के बदलते हुए चरित्र का प्रतीक है. राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर का मनोनयन देश में विवाद का विषय बन गया. विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए. हालांकि कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को इसलिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कराने का निर्णय लिया, क्योंकि सरकार सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं देना चाहती थी. अब इस मनोनयन के बाद सचिन को भारत रत्न न दिया जाना लगभग पक्का हो गया है.

बहुत सालों के बाद राज्यसभा देश में चर्चा का विषय बनी है. अफसोस सिर्फ़ इस बात का है कि अगर राज्यसभा चर्चा का विषय देश की बेकारी, महंगाई, भुखमरी, बेरोज़गारी, दुःख, आंसू और तकलीफ पर चिंता की वजह से बनती तो उसका स्वागत हम अलग तरह से करते, लेकिन वह चर्चा का विषय रेखा के आने, रेखा के बैठने, रेखा की साड़ी, रेखा के कान के झुमके, जया बच्चन के तनाव भरे चेहरे और जया बच्चन के नाक पोंछने की वजह से बनी. इसके लिए भी राज्यसभा की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्यसभा के बदलते हुए चरित्र का प्रतीक है.

फिर रेखा के ऊपर आते हैं. रेखा जैसी लड़की सैकड़ों सालों में पैदा होती है. पारिवारिक तनाव, मां-बाप का अलगाव, जिस लड़की ने बचपन कभी जाना ही न हो. मुझसे एक बार रेखा ने बहुत मायूस शब्दों में कहा था कि 12-13-14 साल की उम्र में किशोरावस्था क्या होती है, मैंने जाना ही नहीं. मेरा बचपन बीता और मैं सीधे जवान हो गई. किशोरावस्था की शरारतें, किशोरावस्था के सपने और किशोरावस्था का चुलबुलापन जैसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं. ऐसी लड़की, जिसने सी ग्रेड की फिल्मों से अपना करियर शुरू किया हो, वह ए ग्रेड की फिल्मों की हीरोइन बनी. उन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित किया कि आज इस उम्र में भी वह जहां चली जाती हैं, वहां चाहे कितनी ही करीना कपूर हों, कितनी भी कैटरीना कैफ हों, रेखा अलग दिखाई देती हैं और रेखा का व्यक्तित्व उन सब पर भारी पड़ जाता है. उम्र जैसे आकर रेखा के ऊपर रुक गई है. उम्र ही नहीं, शोहरत भी रेखा के पास आकर ठहर गई है. मैंने एक बार उनसे पूछा था, रेखा, किससे शादी करना चाहेंगी? रेखा ने मेरी तरफ़ आंख उठाकर कहा था, क्या रेखा पागल है, जो किसी से शादी करेगी. इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है, जो रेखा को सह सके, जो रेखा को संभाल सके. यह वह दौर था, जब रेखा के किस्से किसी एक शख्स के साथ चारों तरफ़ फिजाओं में गूंजते रहते थे. रेखा ने जो कहा, शायद वह सच था, रेखा की ज़िंदगी में कोई पुरुष स्थाई तौर पर आ ही नहीं सका. रेखा का कहना सही था. रेखा में वह आग है, जिसे कोई पुरुष सह ही नहीं सकता. कहानियों में एक पुरुष है, लेकिन वह भी शायद अगर रेखा के साथ होता तो जल कर भस्म हो गया होता. रेखा को हवाएं, बादल, चिड़ियों की चहचहाहट, सूरज का डूबना और सूरज का उगना बहुत पसंद है. रेखा से किए गए मेरे रविवार अख़बार के दिनों के तीन इंटरव्यू आज भी हिंदी पढ़ने वालों के दिमाग़ में ताजा हैं. जब मुझे कोई भी साथी मिलता है तो मेरी बाक़ी रिपोर्टों के साथ-साथ मेरे रेखा के साथ इंटरव्यू को ज़रूर याद करता है.

रेखा राज्यसभा में आई हैं तो मैं राज्यसभा के सांसदों को बस एक बात बताना चाहता हूं कि रेखा सिर्फ़ ग्लैमर नहीं हैं, रेखा की समझदारी का कोई जवाब नहीं है. रेखा की पैनी नज़र राजनेताओं पर तो नहीं रहती, लेकिन राजनेताओं द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर रहती है. इसके बारे में कई बार रेखा ने बातचीत की है. देश के हालात से रेखा चिंतित हैं. रेखा अब जब राज्यसभा में आई हैं तो यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वह उन लोगों को भी बोलने की प्रेरणा देंगी, जो छह साल तक राज्यसभा में रहने के बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं. सदस्य बनते हैं, शपथ लेते हैं और विदाई समारोह में अपने लिए अच्छी बातें सुनकर चले जाते हैं. राज्यसभा को ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन रेखा ऐसी नहीं हैं. रेखा राज्यसभा में जब बोलेंगी तो हो सकता है कि राज्यसभा में कुछ ज़्यादा हलचल हो. ज़्यादा हलचल इसलिए होगी, क्योंकि एक बात का मुझे एहसास है कि कहीं रेखा के बोलने से जया बच्चन देश के हालात पर उनसे पहले न बोल उठें.

इसमें कोई दो राय नहीं कि हम तमाशा देखने के आदी हैं, इसलिए हमारे जेहन में रेखा और जया बच्चन के बीच कोई तमाशा हो, इसका इंतज़ार है. शायद इसीलिए हर एक टीवी चैनल ने इस एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सिलसिला, रेखा और जया का सिलसिला, राज्यसभा में भी सिलसिला. यह ग़लत मानसिकता है. रेखा रेखा हैं, जया जया हैं. रेखा को न जया बच्चन के साथ देखना चाहिए और न जया बच्चन से रेखा की तुलना करनी चाहिए. दोनों अपनी-अपनी तरह से ज़िंदगी में करिश्मे कर चुकी हैं. आशा करनी चाहिए कि जब दोनों राज्यसभा में हैं तो दोनों वहां करिश्मा करेंगी, सवालों पर बोलेंगी और उन लोगों को भी एक संदेश देंगी, जो सिनेमा में काम करने वाली लड़कियों या महिलाओं को गूंगी गुड़िया कहते हैं. आशा करनी चाहिए कि रेखा गूंगी गुड़िया नहीं बनेंगी. ■

संपादक

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

साठ साल का युवा

यह विचार कि भारत में संसदीय लोकतंत्र होगा और यह साठ वर्षों तक चलेगा तथा उसके बाद और ज़्यादा मज़बूत होता जाएगा, न केवल विंस्टन चर्चिल, बल्कि विश्व के कई देशों के नेताओं को हैरान कर सकता है. मुझे याद है कि पहले मेरे कुछ संबंधी यह तर्क देते थे कि भारत की ज़रूरत राजतंत्र है. यहां तक कि 1857 के विद्रोह का आधार भी मुग़ल शासन को फिर से स्थापित करना था, लेकिन भारत एक लोकतंत्र बना. इसका कारण भारत में ब्रिटिश शासन था. भारत में लोकतंत्र का कोई प्राचीन इतिहास नहीं रहा है. प्राचीन भारत के जनपद गणतंत्र थे, लेकिन उसे लोकतंत्र नहीं, बल्कि कुलीन तंत्र कहा जा सकता है. पंचायत भी कुछ विशिष्ट लोगों तक सीमित थी, न कि निर्वाचित संस्था थी. उसमें दलितों एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता था. भारत में समानता का विचार पश्चिम से आया. हालांकि विदेशी शासक भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार करते थे. यह एक विरोधाभास था कि असमानता करने वाले लोगों ने समानता के विचार को पनपने में सहयोग किया. ब्रिटिश शासन के कारण पश्चिमी शिक्षा का भारत में प्रचलन हुआ और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों ने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया. गांधी जी ने संसदीय रास्ते को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्रीकरण किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया. हालांकि कांग्रेस भारत सरकार अधिनियम 1935 में बदलाव चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका इस्तेमाल 1946 की संविधान सभा में बहुमत लाने के लिए किया. उस समय जो चुनाव हुआ था, उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन साठ साल पहले जिस लोकतंत्र को अपनाया गया, वह वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र था, जिसमें सभी वयस्क लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया.

आज़ादी के बाद का पहला दशक सबसे अच्छा लोकतंत्र था. सांसदों को आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष का ताज़ा अनुभव था. आज़ादी के लिए हुए आंदोलन उनके आदर्श थे और भारत में परिवर्तन लाना उनका विजन था. उस समय के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र था और सांसदों को संसद की गरिमा का ख्याल था. शुरुआत के कई वर्षों तक संसद में कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन एक मज़बूत विपक्ष भी था. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसमें नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज नेता थे. हालांकि जयप्रकाश नारायण कभी संसद में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर उनका काफ़ी प्रभाव था. कम्युनिस्ट पार्टी को बुर्जुआ लोकतंत्र स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन उसने भी इसे स्वीकार किया और पार्टी के लोग सांसद भी बने. उस समय संसद में गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती थी. थोड़ा शोरगुल भी होता था, लेकिन आज की तरह नहीं. दूसरी संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें आचार्य कृपलानी ने नेहरू की चीन नीति का विरोध किया था. तीसरी संसद इस मायने में दुर्भाग्यशाली रही, उसे पांच साल में तीन प्रधानमंत्री देखने को मिले. चौथी संसद में संसदीय मानकों में गिरावट आनी शुरू हो गई. कांग्रेस के विभाजन के बाद दल के अंदर का लोकतंत्र ग़ायब हो गया. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी टूट गई और कम्युनिस्ट पार्टी भी कई धाराओं में विभाजित हो गई. संसद प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द घूमने लगी और फ़िरोज़ गांधी जैसे स्वतंत्र सोच वाले सांसद कम ही रहे.

पांचवीं संसद में लोकतंत्र की स्थिति सबसे निम्न स्तर पर रही और आपातकाल की घोषणा हो गई, जिसके कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया. उस समय जयप्रकाश नारायण ने जनता को जगाया और आंदोलन किया. हालांकि जनता पार्टी की सरकार असफल साबित हुई, लेकिन जो बीज लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने बोया था, उसका प्रभाव दस साल बाद दिखाई पड़ा, लेकिन इसमें एक कमी रह गई थी. इन लोगों ने शासन की अवज्ञा का विरोध करना तो सिखाया, लेकिन पार्टी के अंदर लोकतंत्र बहाली का पाठ नहीं पढ़ाया. कहा जा सकता है कि भारत ने पचास और साठ के दशक के लोकतंत्र को फिर से प्राप्त नहीं किया. आज के राजनीतिक दल बिजनेस फर्म की तरह हैं, जो राजनीतिक ताक़त का व्यापार करते हैं. राजनीति में प्रवेश करो और चुनाव जीतने के लिए धन निवेश करो. यह सबसे फ़ायदेमंद व्यापार बन गया है. नेताओं की संपत्ति में अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक तेज़ गति से वृद्धि हो रही है. चुनाव काले धन से लड़े जा रहे हैं. एक बार चुनाव जीत जाने के बाद चुनाव जिताने वालों के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती है. उन लोगों की ओर देखना भी उनके लिए कष्टकारी होता है. अगले चुनाव से छह महीने पहले ही उन्हें अपने क्षेत्र की याद आती है. अब निकट भविष्य में इस व्यवस्था में परिवर्तन की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है. लेकिन एक दिन आएगा, जब राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास होगा और संसद फिर से देश की आवाज़ बनेगी. देर हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा. वह सुबह कभी तो आएगी. ■

भारत में समानता का विचार पश्चिम से आया. हालांकि विदेशी शासक भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार करते थे. यह एक विरोधाभास था कि असमानता करने वाले लोगों ने समानता के विचार को पनपने में सहयोग किया. ब्रिटिश शासन के कारण पश्चिमी शिक्षा का भारत में प्रचलन हुआ और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों ने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया. गांधी जी ने संसदीय रास्ते को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्रीकरण किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया. हालांकि कांग्रेस भारत सरकार अधिनियम 1935 में बदलाव चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका इस्तेमाल 1946 की संविधान सभा में बहुमत लाने के लिए किया.

feedback@chauthiduniya.com

नए नियम-क़ानूनों के तहत यह पहला लाइसेंस जारी किया गया और इससे नेवादा स्वचालित वाहन विकास के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में आ गया है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

स्कूल की हालत कैसे सुधरेगी

सरकारी स्कूल इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं हैं. वजह, निजी स्कूलों का ख़र्च उठा पाना देश की उस 70 फ़ीसदी आबादी के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो रोज़ाना 20 रुपये से कम की आमदनी पर अपना जीवन यापन करती है. ऐसे में सरकारी स्कूल ही एक रास्ता बचता है, जहां ग़रीब बच्चों को शिक्षा मिल सके. निश्चित तौर पर सरकार ने शिक्षा और ख़ासकर, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं और वह इन योजनाओं पर अरबों रुपये ख़र्च भी कर रही है. सर्वशिक्षा अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है. बावजूद इसके, अभी भी ऐसी हालत है कि गांवों में अधिकांश प्राथमिक स्कूलों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं. यही नहीं, कभी इन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है तो चाक नहीं होती. चाक होती है तो बैठने के लिए मेज-कुर्सियां नहीं होतीं. होती भी हैं तो टूटी-फूटी. ऐसा नहीं है कि स्कूलों को इन चीजों के लिए पैसा नहीं मिलता. हर स्कूल को हर साल इन ज़रूरी चीजों के लिए बजट आवंटित किया जाता है. अब सवाल उठता है कि आख़िर पैसा मिलने के बाद भी प्राथमिक स्कूलों की हालत ख़राब क्यों रहती है.

ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस बात पर नज़र रखें कि आख़िर स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसों का कहीं ग़लत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसों का हेडमास्टर, मुखिया-प्रधान एवं अधिकारी मिलकर गबन कर जाते हैं. हमें पैसों की इस चोरी को रोकने के लिए क़दम तो उठाना ही होगा, क्योंकि यह हमारा ही पैसा है, जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार फिर उन पैसों को हमारे विकास के लिए ख़र्च करती है. तो क्या हम अपने विकास के लिए आने वाले पैसों का हिसाब नहीं मांगना चाहेंगे? आइए, इस अंक में प्रकाशित आवेदन पत्र का इस्तेमाल कीजिए और अपने इलाक़े के सरकारी स्कूल के विकास से जुड़े ख़र्च का हिसाब-किताब मांगिए. आप इस आवेदन पत्र के माध्यम से पूछ सकते हैं कि किसी खास साल में आपके क्षेत्र के स्कूल के विकास के लिए कितनी रकम आवंटित की गई, यह रकम किन कार्यों के लिए आवंटित की गई, किन एजेंसियों के माध्यम से उक्त काम कराए गए, किन लोगों ने उक्त कार्यों को सही बताया और ठेकेदार को भुगतान की अनुमति दी, ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए कितनी रकम का भुगतान किया गया? यदि आप इस तरह की सूचना मांगते हैं तो तय मानिए, इस आवेदन से एक तरह का दबाव बनेगा, उन लोगों पर, जो विकास का पैसा हजम कर जाते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमल ज़रूर करेंगे और साथ ही अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सूचना के सिपाही वीरपाल लाखा

एटा (उत्तर प्रदेश) के अवागढ़ में रहने वाले वीरपाल लाखा एक आम नागरिक हैं, लेकिन वह आम होते हुए भी ख़ास हैं, क्योंकि उनका काम ख़ास है. वह आम आदमी होते हुए भी आम आदमी को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं. वीरपाल लाखा दरअसल अपने क्षेत्र में सूचना का अधिकार क्रांति की अलख जगा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर आरटीआई क़ानून को लेकर जन जागरण कर रहे हैं. लोगों को इस क़ानून के बारे में बताकर उन्हें एक सजग-सशक्त नागरिक बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. वीरपाल लाखा किसी अन्य स्रोत से मदद लिए बिना वह काम कर रहे हैं. चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए वीरपाल लाखा बताते हैं कि उन्हें यह काम शुरू करने में सबसे ज़्यादा मदद मिली चौथी दुनिया में प्रकाशित होने वाले आरटीआई के नियमित कॉलम से. पिछले एक साल से वह इस कॉलम को सहेज कर रख रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उन्हें आरटीआई के बारे में बताते हैं, लोगों को इस क़ानून के इस्तेमाल के तरीक़े सिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं. चौथी दुनिया अख़बार ख़रीदने के लिए वीरपाल लाखा को ज़िला मुख्यालय तक जाना पड़ता है, लेकिन वह नियमित तौर पर यह अख़बार ख़रीदते हैं और लोगों के बीच मुफ्त में बांटते हैं. वीरपाल लाखा ख़ुद भी आरटीआई का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के कई मामलों का ख़ुलासा कर चुके हैं. वह कहते हैं कि गांव के लोग भले ही ज़्यादा पढ़े-लिखे न हों, लेकिन इस अख़बार में प्रकाशित आरटीआई कॉलम को देखकर आरटीआई आवेदन बना लेते हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

गुस्से में लाखों का नुक़सान

इंसान गुस्से में न जाने क्या-क्या कर बैठता है. उसे यह नहीं पता होता कि वह क्या कर रहा है और अपना ही नुक़सान कर बैठता है. अगर आपकी पत्नी गुस्से में है तो अपने नोटों को बचाने की जुगत लगाना शुरू कर दीजिए. चीन में पति-पत्नी की आपसी अनबन में एक महिला ने 4 लाख रुपये के नोट चिंदी-चिंदी कर डाले. जब उसका पति उन फटे हुए नोटों को लेकर बैंक पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए. उन्हें माजरा समझ में नहीं आ रहा था और यह भी कि आख़िर अब वे करें क्या? बैंक कर्मचारियों ने उसकी मदद करने का बीड़ा उठाया और जुट गए नोटों को जोड़ने की मुहिम में, लेकिन नोटों को इतना छोटा-छोटा, चिंदी-चिंदी करके फाड़ा गया था कि सारी मेहनत धरी रह गई. 6 घंटे की मशक्कत के बाद केवल एक नोट ही पूरा जोड़ा जा सका. बैंक वालों ने हार मानकर हाथ खड़े कर दिए. बताया जाता है कि जिस महिला ने नोट फाड़े थे, वह मानसिक रूप से कुछ परेशान रहती थी और उसके इलाज के लिए ही उसके पति ने घर में इतने सारे पैसे रख छोड़े थे. यह पता नहीं चल सका कि उसे नोट जोड़ने में सफलता मिली कि नहीं. ■

बिल्ली बनी मौत की वजह

जब किसी का कोई प्रिय शख्स मर जाता है तो मारे दु:ख के वह पागल सा हो जाता है, कभी-कभी उसकी मौत तक हो जाती है. इसी तरह कई लोग पालतू जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी मौत के सदमे को सहन नहीं कर पाते. पिछले दिनों ब्रिटेन में अपनी पालतू बिल्ली की मौत से दु:खी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. समाचारपत्र सन अनुसार, माइकल मैकअलीस (44) अपनी पालतू बिल्ली की मौत हो जाने के बाद तीन दिनों तक उसके शव के साथ सोता रहा. श्रद्धांजलि के तौर पर उसने इंटरनेट पर अपनी उस 13 वर्षीय पालतू बिल्ली का एक वीडियो भी डाला और लिखा, ये उसकी यादें हैं, वह एक शानदार बिल्ली थी. बिल्ली की मौत के आठ दिनों बाद मैकअलीस का शव उसके डोरसेट काउंटी स्थित घर में मिला. उसकी बहन जूलियट विलमोर ने कहा, मेरे भाई ने बिल्ली के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए एक व्यक्ति को बताया था कि वह अपने आपको ख़त्म कर लेगा. ■

कार ख़ुद चलेगी

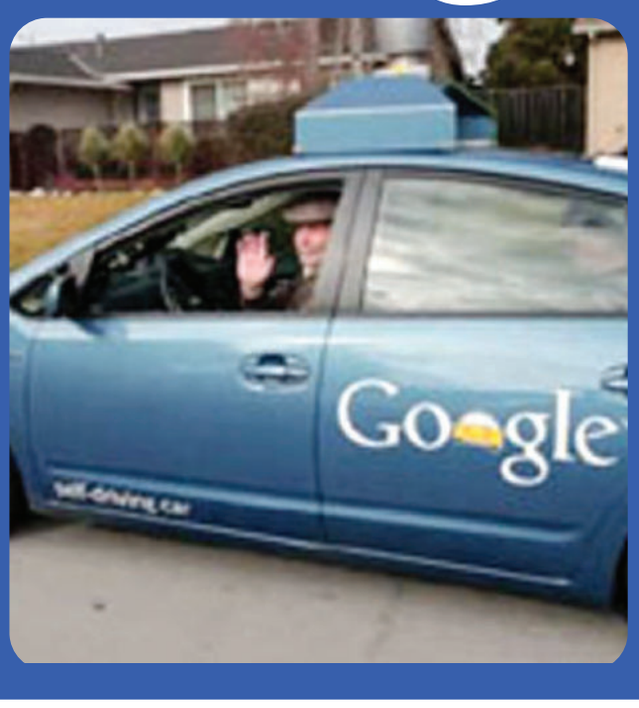

आजकल दिन-प्रतिदिन नए-नए प्रयोग होते जा रहे हैं. अपने सर्च इंजन एवं ई-मेल सेवाओं के लिए विख्यात गूगल को अमेरिका में स्वचालित कारों के परीक्षण का लाइसेंस मिल गया है. वह नेवादा की व्यस्त सड़कों पर बिना चालक के चलने वाली कारों का परीक्षण करेगा. नेवादा (कैलिफोर्निया) में मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने गूगल को देश में अपनी तरह का पहला लाइसेंस दिया है. इसके तहत वह आम गलियों में ऐसे स्वचालित वाहनों का परीक्षण करेगा, जिसमें चालक की ज़रूरत नहीं होती. विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उसने कई स्थानों के प्रदर्शन देखने के बाद यह विशेष लाइसेंस जारी किया है. नए नियम-क़ानूनों के तहत यह पहला लाइसेंस जारी किया गया और इससे नेवादा स्वचालित वाहन विकास के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में आ गया है. स्वचालित वाहन की यह परियोजना गूगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप कोई कार्य संपादित करने के लिए सख्त रुख़ न अपनाएं. धैर्य से कार्य करें, अन्यथा नुक़सान होगा. किसी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा न करें. नौकरीपेशा लोग ख़ुश रहेंगे. व्यापारी थोड़ा चिंतित रहेंगे. परिवार में शुभ कार्य के संकेत हैं. किसी यात्रा का योग बनेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आपका पद-प्रभाव बढ़ने का प्रबल योग है. धन से संबंधित विवाद न बढ़ने न दें. कोई पुराना रोग आपकी चिंता का कारण बनेगा. इस सप्ताह आप सफल कहलाएंगे. आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होने का वक्त रहेगा. विद्यार्थी ख़ुशी मनाने के मूड में रहेंगे. सामाजिक रूप से आपका कोई बड़ा काम संपन्न हो सकता है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आप स्वयं निर्णय लें, किसी अन्य से प्रभावित होकर निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे. उदर विकार से बचने के लिए मसालेदार भोजन से बचें. नौकरीपेशा लोग ख़ुश रहेंगे. व्यापारी भी अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे. धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी संभव है. पारिवारिक रूप से ख़ुशनुमा वातावरण रहेगा. कार्यस्थल पर सहयोगी आपके साथ रहेंगे. व्यापारी अपने स्टाफ को लेकर चिंतित होंगे. स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह यात्रा की योजना सोच-समझ कर बनाएं. कार्यस्थल पर मित्रों के साथ तनाव न बढ़ने दें. वाहन तेज न चलाएं. गर्म भोजन कर यात्रा पर न निकलें. आर्थिक रूप से थोड़ा तनाव में रहेंगे. पारिवारिक रूप से कोई शुभ समाचार आने की संभावना रहेगी. विद्यार्थी थोड़े चिंतित रहेंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आप इस सप्ताह मानसिक उत्तेजना में कोई कार्य न करें. वाद- विवाद से बचें. ऐश्वर्य की वस्तु का क्रय होगा. आप पारिवारिक रूप से मौजमस्ती के मूड में रहेंगे. जल्दबाज़ी में कोई संपत्ति क्रय न करें, क़ानूनी दस्तावेजों को परखने के बाद क्रय करें. स्वास्थ्य थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव के साथ अच्छा रहेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह कोई जिद न करें. आपका आत्मविश्वास सर्वोत्तम रहेगा. ख़र्चों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, अन्यथा सप्ताहांत में आप चिंतित हो जाएंगे. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग ख़ुश रहेंगे और उन्नति के लिए प्रयास करेंगे. नेत्र और अस्थि विकार के प्रति सचेत रहें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आप सफल सिद्ध होंगे. कोई पुराना कार्य, जो काफी समय से लंबित है, पूर्ण होगा और आर्थिक रूप से आपको मज़बूत करेगा. कोई मांगलिक कार्य पूर्ण होने की संभावना है. इस सप्ताह आपके विरोधी भी आपसे पनाह मांगेंगे. किसी भी क़ानूनी मामले से बचने का प्रयास करें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यह सप्ताह आम तौर पर मिला-जुला साबित होगा, लेकिन आप ख़ुश रहेंगे. सप्ताह के पूर्वार्द्ध में थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन फिर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परिवार में अपनी कोई बात रखकर विवाद न उभरने दें, उससे बचें. दांपत्य जीवन का सही महत्व समझते हुए थोड़ा समय परिवार में भी व्यतीत करें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यह पूरे दम से मेहनत करने का सप्ताह रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके व्यक्तित्व में निखार के साथ-साथ आर्थिक स्तर में भी वृद्धि करेगी. संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक प्रोन्नति का समाचार मिलेगा. व्यापारी भी ख़ुश रहेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आप परिवार में ख़ुशी लाने का प्रयास करेंगे. किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपकी मानसिक परेशानी का कारण बनेगा. व्यवसायी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. नौकरीपेशा लोग कुछ चिंतित रहेंगे. युवा कार्यशील होने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफल भी होंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह आप ख़ुश रहेंगे. आर्थिक रूप से मज़बूती आएगी, लेकिन किसी बड़े ख़र्च की योजना से बचें. सामाजिक स्तर पर आपका कद बढ़ेगा. कोई नया व्यक्ति आपकी दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा. क़ानूनी रूप से बंधकर कोई पार्टनरशिप न करें. स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा.

cshekhar_3@hotmail.com

म्यांमार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उसकी दूरी काफी कम है. बंगाल की खाड़ी भारत के जलीय व्यापार की रीढ़ है.

भारत-म्यांमार रिश्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत

राजीव कुमार
rajiv@chauthiduniya.com

म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के प्रयास शुरू होने के साथ ही अमेरिका–यूरोप ने उसके संबंध में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है. अमेरिका की ओर से उस पर आर्थिक प्रतिबंधों में ढिलाई देने का बयान आने लगा है. हिलेरी क्लिंटन ने म्यांमार यात्रा के दौरान इसका संकेत भी दे दिया है. अमेरिका एशिया पैसिफिक की ओर रुख़ कर रहा है. यूरोप भी अमेरिका का अनुसरण करेगा. चीन भी नई रणनीति बनाएगा. पश्चिमी देशों की निवेश करने की नीति के साथ ही यहां भारत के लिए प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना लाज़िमी है. ऐसे समय में भारत को म्यांमार की ओर तेजी से अपना क़दम बढ़ाना चाहिए.

आंग सान सू की रिहाई और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिलने के साथ ही ऐसा लगने लगा कि म्यांमार अब लोकतंत्र के लिए तैयार हो गया है. म्यांमार में 46 संसदीय सीटों के लिए चुनाव हुए. अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह चुनाव निष्पक्ष तरीक़े से कराया जाएगा या नहीं. सू ने भी कहा था कि चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हुआ. इसलिए नहीं कि चुनाव में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बुलाए गए, बल्कि इसलिए कि 46 में से 43 सीटें आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मिली. अगर चुनाव में धांधली की जाती तो जो सीटें एनएलडी को मिलीं, वे सत्तारूढ़ दल यूएसडीपी को मिली होतीं. स्वयं सू ने भी संसदीय उपचुनाव में जीत हासिल की और उन्हें 75 फ़ीसदी मत मिले. हालांकि उनके दल की इस जीत से सरकार के ऊपर कोई विशेष फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव से यह लगने लगा कि 2015 का चुनाव भी निष्पक्ष होगा और जल्दी ही म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा. म्यामांर सरकार के इस फ़ैसले के बाद अमेरिका के साथ–साथ यूरोपीय देशों ने म्यांमार के प्रति अपनी नीति बदलने का संकेत दे दिया है. एक तरफ सू विदेश यात्राएं कर रही हैं तो दूसरी तरफ़ दूसरे देश के मंत्री एवं प्रशासक म्यांमार की यात्रा कर रहे हैं. लोकतंत्र न होने के कारण जो प्रतिबंध म्यांमार पर लगाए गए थे, उनमें ढील देने या फिर उन्हें समाप्त करने की बात कही जा रही है. ऐसे में भारत के लिए भी ज़रूरी है कि वह म्यांमार की ओर विशेष ध्यान दे. लोकतंत्र न होने के कारण म्यांमार से भारत के वैचारिक मतभेद रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से म्यांमार में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ये मतभेद भी जल्द दूर होने की उम्मीद है. भारत के साथ म्यांमार के संबंध कुछ समय को छोड़कर अच्छे रहे हैं, लेकिन इस संबंध को मज़बूत करने की आवश्यकता है.

भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगी हुई है. इन राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं. अलगाववादियों के लिए म्यांमार एक सुरक्षित देश रहा है, जहां से वे अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं. इस वजह से भारत को म्यांमार के साथ वैसे ही संबंधों की आवश्यकता है, जैसे उसके भूटान के साथ हैं. अगर म्यांमार भी भूटान की तरह इन अलगाववादियों के विरुद्ध भारत का साथ दे तो उत्तर पूर्वी भारत में चल रहे अलगाववादी आंदोलन को कमज़ोर किया जा सकता है. हालांकि अभी भी म्यांमार भारत का साथ दे रहा है, लेकिन जितनी शिद्दत से साथ देने की

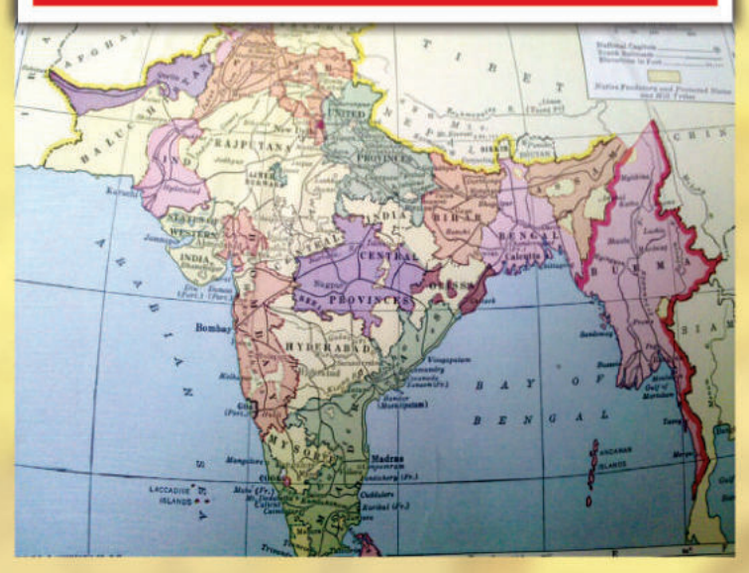

आवश्यकता है, उतना नहीं दे पा रहा है. म्यांमार को अपने साथ लाकर भारत मणिपुर एवं नागालैंड जैसे राज्यों में शांति स्थापित कर सकता है. चूंकि म्यांमार की सीमाएं चीन एवं बांग्लादेश के साथ भी हैं, इसलिए भारत को और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. चीन ने म्यांमार में काफी निवेश किया है और वह म्यांमार का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझीदार है. चीन एवं म्यांमार के बीच सड़क परिवहन की व्यवस्था है और भारत को घेरने की अपनी नीति के तहत चीन म्यांमार का इस्तेमाल भी करता रहा है. हालांकि म्यांमार इससे इंकार करता रहा है कि उसके यहां उत्तर पूर्वी भारत के अलगाववादी शरण लेते हैं. वह इस बात को भी अस्वीकार करता है कि चीन उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है.

म्यांमार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उसकी दूरी काफी कम है. बंगाल की खाड़ी भारत के जलीय व्यापार की रीढ़ है. बंगाल की खाड़ी से होने वाले भारतीय व्यापार को म्यांमार प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा भारत म्यांमार के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों, जैसे वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एवं कंबोडिया आदि के साथ जल अथवा सड़क मार्ग से व्यापार कर सकता है. आसियान देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने में भी म्यांमार की भूमिका भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी. म्यांमार के साथ संबंध चीन के बंगाल की खाड़ी में बढ़ते प्रभाव को रोकने का एक आधार हो सकता है. म्यांमार के सहयोग से भारत नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण करने में भी सफल हो सकता है. म्यांमार के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, जो कि भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी भेजे जाते हैं. ग़ौरतलब है कि नशीले पदार्थों के व्यापार से हासिल धन का इस्तेमाल अलगाववादियों द्वारा हथियार ख़रीदने में किया जाता है, जिनके ज़रिये वे आतंक फैलाते हैं. इन तमाम कारणों के चलते म्यामांर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

हालांकि भारत और म्यांमार के बीच व्यापार सही दिशा में है. भारत इसका चौथा बड़ा व्यापारिक साझीदार है और भारत ने म्यांमार की आधारभूत संरचना के निर्माण में भी निवेश किया है, लेकिन अब म्यांमार में परिस्थितियां बदलने वाली हैं. जैसे ही म्यांमार में लोकतंत्र लाने की कवायद शुरू हुई, अमेरिका–यूरोप ने उससे संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए. अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक महीने के भीतर आंग सान सू के साथ दो बार मुलाक़ात की. हिलेरी क्लिंटन ने म्यांमार का दौरा भी किया. उन्होंने विश्व बैंक एवं आईएमएफ के ज़रिये आर्थिक सहायता देने और म्यांमार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1.2 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं की भी घोषणा की. अमेरिका म्यांमार संबंधी अपनी नीति में बदलाव कर रहा है. वह वहां चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है. अमेरिका अब एशिया पैसिफिक में अपना वर्चस्व चाहता है, ताकि वह चीन को मात दे सके. इसके लिए वह म्यांमार के साथ संबंधों में सुधार करेगा और बड़े पैमाने पर निवेश की कोशिश करेगा. इसके अलावा यूरोप के अन्य देश भी अमेरिका के पीछे–पीछे म्यांमार आएंगे. इन देशों के प्रवेश के साथ ही चीन का सतर्क होना निश्चित है. चीन भी अपनी रणनीति में बदलाव करेगा. ऐसे में भारत को म्यांमार में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए एक साथ कई देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी. इसके लिए भारत को पहले से ही तैयार रहना चाहिए. जब तक अमेरिका–यूरोप के निवेश की रफ्तार तेज हो, तब तक भारत को म्यांमार में अपनी स्थिति मज़बूत कर लेने की ज़रूरत है. म्यांमार में ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं. भारत वहां के गैस भंडारों का उपयोग सुविधाजनक तरीक़े से कर सकता है, म्यांमार से पाइप लाइन के सहारे गैस ला सकता है. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए भी म्यांमार के साथ संबंध बेहतर करना ज़रूरी है. जो परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, उन्हें शीघ्र पूरा करने की ज़रूरत है. कालादान परियोजना पर 2008 से ही काम चल रहा है, लेकिन जिस तीव्रता की उम्मीद की जा रही थी, वह नहीं दिखाई पड़ रही है. इस परियोजना के तहत भारत कालादान नदी के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों में सामान भेज सकता है. कुछ समय पहले ही म्यांमार ने इरावदी नदी पर चीन के सहयोग से बनाए जा रहे डैम पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि उसका विरोध हो रहा था. इसके बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन कर रहा है. चीन नहीं चाहेगा कि म्यांमार में भारत की आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, लेकिन भारत को इसके लिए प्रयास करने होंगे. भारत की ओर से कोशिशें जारी हैं, लेकिन उनमें और तेजी लाने की ज़रूरत है, वरना देखते ही देखते एक और पड़ोसी देश चीन के साथ चला जाएगा, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा. ■

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

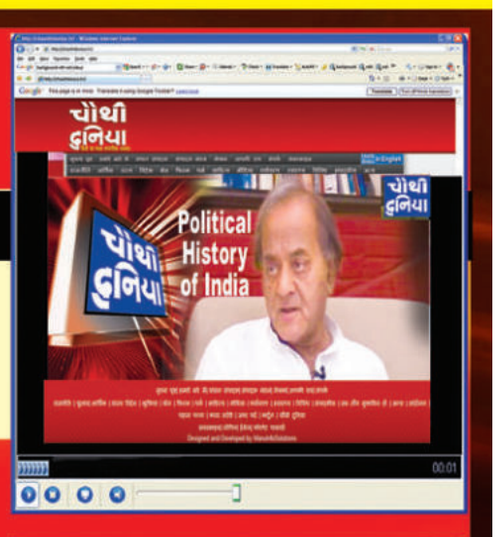

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

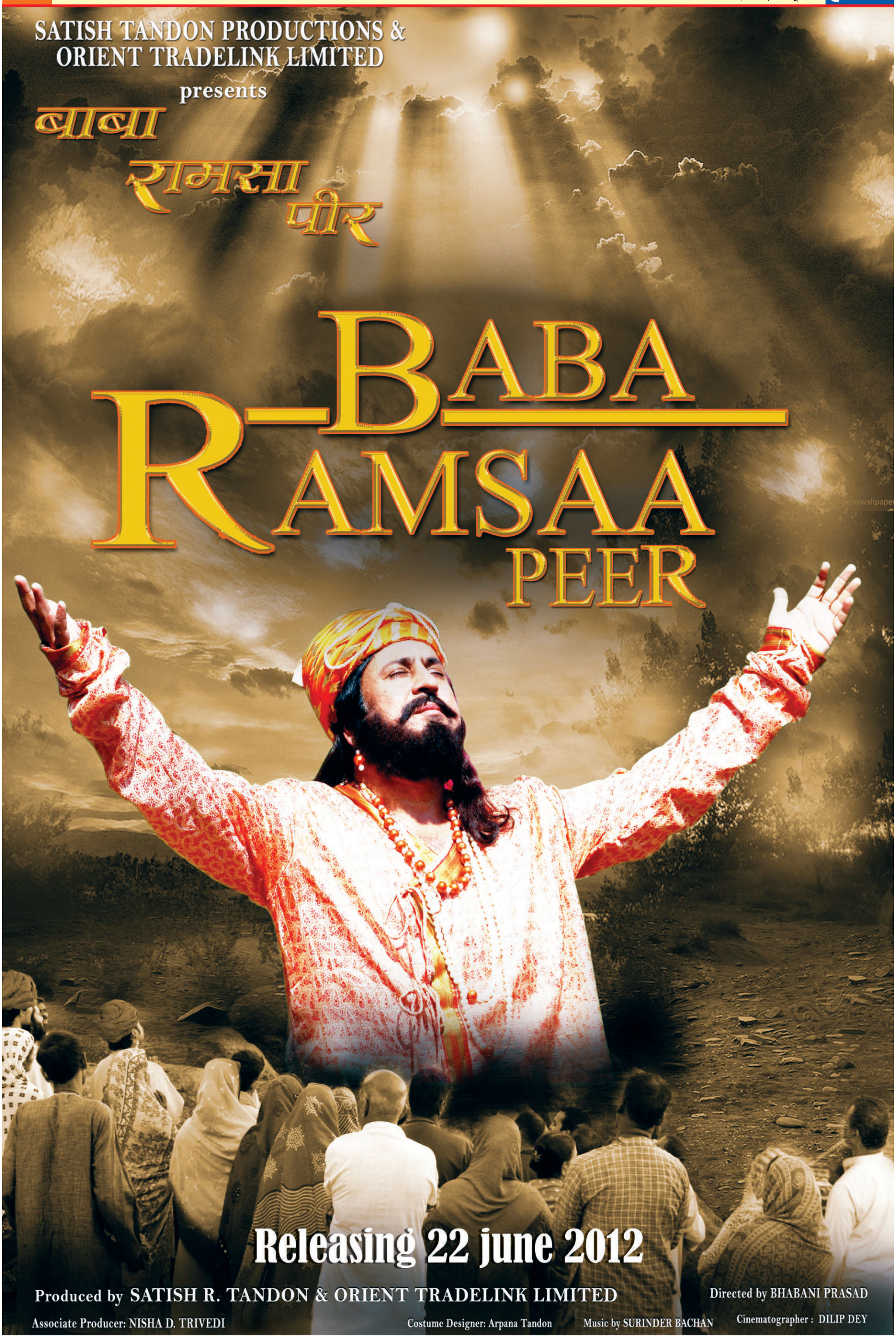
SATISH TANDON PRODUCTIONS &
ORIENT TRADELINK LIMITED
presents
बाबा रामसा पीर
R-BABA RAMSAA PEER
Releasing 22 june 2012
Produced by SATISH R. TANDON & ORIENT TRADELINK LIMITED
Directed by BHABANI PRASAD
Associate Producer: NISHA D. TRIVEDI
Costume Designer: Arpana Tandon
Music by SURINDER BACHAN
Cinematographer : DILIP DEY

विकिरण से जूझते आदिवासियों की महागाथा

नवनीत कुमार मालवीय
feedback@chauthiduniya.com

राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित महुआ माजी का उपन्यास-मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ आदिवासियों की कथा पर आधारित है. उपन्यास के पात्र सगेन, चारिबा, आदित्यश्री, प्रज्ञा, मोमोका, मासायुकि, अरिना, जाम्बीरा, मेंजारी, सुकुरमुनी, रेकोंडा एवं लुइधु जीवंत लगते हैं. उपन्यास में आदिवासियों के जीवन के उस संघर्ष का वर्णन किया गया है, जो वे जीवित रहने के लिए करते हैं. लेखिका ने इस उपन्यास को विकिरण, प्रदूषण एवं विस्थापन से जूझते आदिवासियों की गाथा बताया है, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं अधिक विस्तृत और व्यापक है. यह द्वितीय विश्व युद्ध में हुए विध्वंस से लेकर आज प्राय: संपूर्ण विश्व में रेडियोधर्मी विकिरण एवं विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण द्वारा निरंतर विस्थापित होते आदिवासियों की करुण कथा है. इसके अलावा यह जंगल जीवन की महागाथा है. इसमें जंगल जीवन जीने वाले आदिवासियों की अंतरंग एवं प्रामाणिक कथा अत्यंत सूक्ष्म और विविधवर्णी ब्योरों के साथ वर्णित की गई है. यह उपन्यास भारत के सिंहभूम के आदिवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं विभिन्न द्वीपों पर रहने वाले आदिवासियों के जीवन तक है. आज आदिवासियों के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव यूरेनियम प्राप्त करने के लिए होने वाले खनन का पड़ रहा है, जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल रहा है और जिसका दुष्प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के दुष्परिणामों से भी कई गुना अधिक है. आदिवासियों की अनेक पीढ़ियां विकृत और विकलांग बच्चों को जन्म दे रही हैं. इसके अतिरिक्त विकास के नाम पर किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के कारण वे विस्थापित होकर दोहरी मौत मर रहे हैं.

पुरस्कृत पुस्तक समीक्षा

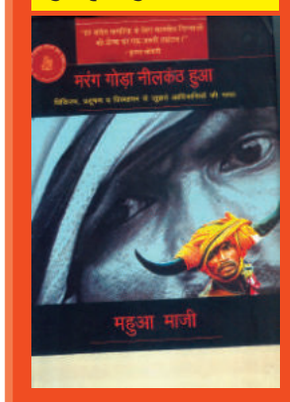

बक़ौल वीरेंद्र यादव, महुआ माजी का उपन्यास मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ अपने नए विषय एवं लेखकीय सरोकारों के चलते इधर के उपन्यासों में एक उल्लेखनीय पहलक़दमी है. जब हिंदी की मुख्य धारा के लेखक हाशिये के समाज को लेकर लगभग उदासीन हों, तब आदिवासियों की दशा, दुर्दशा और जीवन संघर्ष पर केंद्रित यह उपन्यास एक बड़े खालीपन की भरपाई है. इस उपन्यास में महुआ माजी यूरेनियम की तलाश से जुड़ी जिस संपूर्ण प्रक्रिया को उजागर करती हैं, वह हिंदी उपन्यास का जोखिम के इलाक़े में प्रवेश है. महुआ माजी ने गहरे शोध, सर्वेक्षण एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि का सहारा लेकर इस उपन्यास के माध्यम से एक ज़रूरी हस्तक्षेप किया है. उपन्यास का केंद्रीय पात्र सगेन प्रतिरोध की स्थानिकता बरक़रार रखते हुए विकिरण विरोधी वैश्विक आंदोलन के साथ भी संवाद बनाता है. हिरोशिमा की दहशत और चेरनोबिल एवं फुकुशिमा सरीखे हादसे उसकी चेतना को लगातार प्रतिरोधी दिशा देते हैं. अच्छा यह भी है कि यह सब कुछ मानवीय संबंधों की ऊष्मा एवं अंतर्द्वंद्व में घुल- मिलकर प्रस्तुत हुआ है. उपन्यास में वर्णित कई तथ्य एवं मुद्दे अभी तक गंभीर चर्चा का विषय नहीं बन सके हैं. ■

काव्य दुनिया

मानव

प्रकृति की उत्तम रचना मानव
आज हुआ परिचय विहीन
भुलाकर उद्देश्य
छोड़कर दर्शन
कुचल कर आदर्श
विस्मृत कर कर्तव्यों को
होकर दिग्भ्रम का शिकार
अर्थ विहीन विषय की लालसा लिए
शामिल है स्पर्धा की
अंधी दौड़ में
रौंद कर समस्त रिश्तों को
और खोकर अपनी विरासत
पाना चाहता है छद्म सुख
मानवता से विमुख होकर
संवेदना को त्याग कर
स्वार्थ के मद में डूबा मानव
चल पड़ा अंतहीन यात्रा पर.

अभिषेक रंजन सिंह
arsingh@chauthiduniya.com

किताब मिली

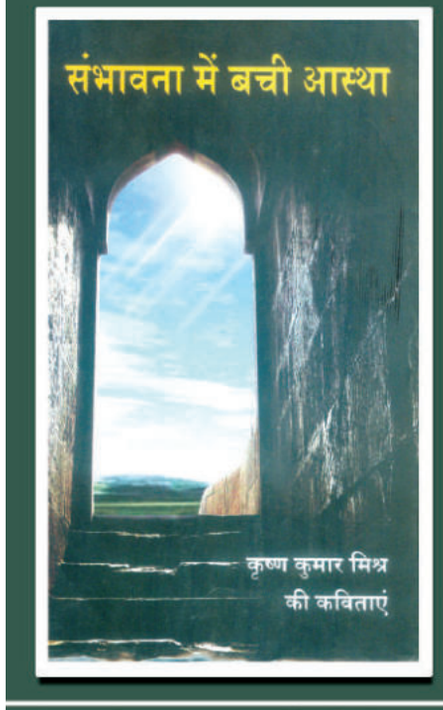

पुस्तक
संभावना में बची आस्था
कवि
कृष्ण कुमार मिश्र
प्रकाशक
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
मूल्य
200 रुपये

यह पुस्तक सौ कविताओं का एक संग्रह है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

इब्ने इंशा ने बहुत कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था. वह अपने असली नाम की बजाय इब्ने इंशा नाम से लिखते थे और इसी नाम से उन्हें ख्याति मिली.

कार्टून के बहाने उठे सवाल

अनंत विजय

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लगभग छह दशक पहले छपे एक कार्टून के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में फिर से छपने पर संसद में जमकर बवाल हुआ. बवाल और हंगामे के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने सदन में माफ़ी मांगी और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने नैतिकता के आधार पर माफ़ी मांगी, लेकिन इस माफ़ी में नैतिकता से ज़्यादा एक मंत्री की लाचारी भी दिखाई देती है. कार्टून छपने में कपिल सिब्बल की भूमिका सिर्फ़ इतनी है कि उनके संबंधित विभाग के मंत्री रहते यह मामला संसद में उठा. सरकार ने आनन-फ़ानन में यह ऐलान भी कर दिया कि बाबा साहब के कार्टून को अगले सत्र से हटा दिया जाएगा. फ़िलहाल पुस्तक के वितरण पर भी रोक लगा दी गई है. जिस त्वरित गति से मंत्री ने माफ़ी मांगी, कार्रवाई की, उससे भी तेज़ गति से इस किताब को तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले मशहूर समाजवादी चिंतक योगेंद्र यादव ने भी एनसीईआरटी की राजनीति शास्त्र की किताबों के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफ़ा दे दिया. यहां सवाल यह उठता है कि क्या एनसीईआरटी में ऐसे किसी पद पर योगेंद्र यादव अब तक थे? जानकारी के मुताबिक़, जब कृष्ण कुमार एनसीईआरटी के निदेशक थे तो योगेंद्र यादव एवं उनकी टीम को राजनीति शास्त्र की किताबें तैयार करने का ज़िम्मा सौंपा गया था. जब किताब तैयार हुई थी तो योगेंद्र का नाम लेखक के रूप में न जाकर सलाहकार के रूप में छपा था. माना यह जाता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी निभा रहा व्यक्ति स्वत: कार्यमुक्त हो जाता है. योगेंद्र यादव के इस्तीफ़े के बारे में एनसीईआरटी या फिर सरकार को स्थिति साफ़ करनी चाहिए.

दरअसल, बाबा साहब के नाम पर दलितों की राजनीति करने वालों को इस मुद्दे में एक संभावना नज़र आई. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से दलितों के संवेदनात्मक एवं रागात्मक जुड़ाव को देखते हुए इस वक़्त किसी भी राजनीतिक दल में यह साहस नहीं है कि वह शंकर द्वारा तक़रीबन छह दशक पहले बनाए गए इस कार्टून के पक्ष में अपनी बात रख सके. शंकर हमारे देश में कार्टून विधा के पितामह हैं और ख़ुद बाबा साहब अंबेडकर भी उनके कार्टूनों पर कभी नाराज़ नहीं हुए. जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संसद में बवाल किया, उनके आज़ाद भारत के सबसे बड़े नेता जवाहर लाल नेहरू शंकर के कार्टूनों के ज़बरदस्त प्रशंसक थे. नेताओं को आपत्ति इस बात पर है कि बाबा साहब के कार्टून को कोर्स की किताब में क्यों लगाया गया. अंबेडकरवादियों का तर्क है बाल मन पर पहली शिक्षा का असर लंबे समय तक रहता है, लिहाज़ा इस कार्टून से अंबेडकर की जो छवि बच्चों के मन में बनेगी, वह वास्तविक तस्वीर से भिन्न होगी. योगेंद्र यादव का तर्क है कि किताबों में कार्टून का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, ताकि पढ़ाई में बच्चों की रुचि बनी रहे. उनका मानना है कि इस कार्टून से अंबेडकर का कोई अपमान नहीं हुआ है. योगेंद्र यादव ने दु:ख जताया कि इस बात का सहारा लेकर किताब को अंबेडकर विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है. अब इस तर्क पर कुछ भी कहना उचित नहीं है कि कार्टून से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहेगी. अगर राजनीति शास्त्र की किताबों पर नज़र डालें तो उसमें पॉलिटिकल क्लास के प्रति एक उपहास सा नज़र आता है. उस उपहास से पॉलिटिकल क्लास की क्या छवि बाल मन में बनेगी, इसकी कल्पना इन किताबों को तैयार करने वालों ने शायद नहीं की या फिर सयास ऐसा किया गया. दो ही स्थितियां बनती हैं और दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं.

अंबेडकर कार्टून विवाद पर जितना हो-हल्ला मचा, माफ़ी और इस्तीफ़े हुए, उस कोलाहल में कई बड़े प्रश्न गुम गए, जिन्हें शिक्षाविदों के सामने खड़ा होना चाहिए था. उन प्रश्नों का जवाब देश की जनता भी जानना चाहती है. एनसीईआरटी या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा से जुड़ी कमेटियों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, जो एक ख़ास विचारधारा से जुड़े या प्रेरित हैं या रहे हैं. उनकी सोच वस्तुनिष्ठ नहीं है. वे हर मुद्दे को विचारधारा के चश्मे से देखते हैं. बात बहुत पुरानी नहीं है, जब एनसीईआरटी की किताबों में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आधे पन्ने में जगह दी गई थी और रूस के क्रांतिकारी नेता लेनिन को तीन पन्ने दिए गए थे. यह क्या है? क्या हमारे देश के नौनिहालों को महात्मा गांधी से ज़्यादा लेनिन के बारे में जानना ज़रूरी है? क्या बच्चों को लेनिन के बारे में, उनकी सोच एवं उनके जीवन के बारे में पढ़ाकर एक ख़ास क़िस्म की रुचि का निर्माण करने की कोशिश नहीं की गई? क्या बच्चों को महात्मा गांधी एवं उनके विचारों को उसी विस्तार से जानने का हक़ नहीं है, जिस विस्तार से लेनिन को जानने का है? सवाल यह उठता है कि क्या महात्मा गांधी की महानता लेनिन से कम थी? बच्चों के लिए किताबें तैयार करने वालों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि एनसीईआरटी की किसी भी किताब में मदन मोहन मालवीय का नाम प्रमुखता से क्यों नहीं मिलता? क्या मदन मोहन मालवीय ने देश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ भी नहीं किया? क्या देश के स्वतंत्रता संग्राम में मालवीय की कोई भूमिका नहीं थी? जिस अनुपात में पाठ्य पुस्तकों में नेहरू के जीवन, उनके संघर्ष एवं योगदान के बारे में बताया-पढ़ाया जाता है, उस अनुपात में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद को, उनके संघर्षों, देश के प्रति उनके योगदान को जगह क्यों नहीं मिलती? क्या देश के प्रति उनका योगदान कम है? अगर तर्क यह है कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता और देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो क्या डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे? क्या संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर उनका योगदान नेहरू से कम था? कम से कम संविधान सभा की बहसों को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता. नेहरू के वक़्त डॉ. प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे और वह नेहरू के आभा मंडल से बाहर रहकर संविधान सम्मत कार्य करते थे. नेहरू से कई मुद्दों पर उनके गंभीर मतभेद रहे, लेकिन सिर्फ़ अपनी प्रतिभा और साख की बदौलत वह दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, पर किताबें तैयार करने वालों को उनका योगदान नहीं दिखाई देता. यहां यह बताते चलें कि राजेंद्र प्रसाद को बापू ने देशरत्न की उपाधि दी थी और वह हमेशा कहा करते थे कि राजेंद्र प्रसाद उनके सर्वश्रेष्ठ सहकर्मी हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक लिखने वालों को लगता है कि जो आदमी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ा है, वह सेक्युलर नहीं हो सकता है. उनकी नज़रों में धर्म निरपेक्ष होने के लिए हिंदू विरोधी होना या हिंदू विरोधी होने का दिखावा करना पहली शर्त है और जो उनकी नज़र में सेक्युलर नहीं है, उसे पाठ्य पुस्तक में जगह कैसे मिल सकती है. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी इन्हीं वजहों से किताबों से बाहर हैं. जब 1952 के आम चुनाव के बाद मद्रास की बिगड़ती हालत के मद्देनज़र वहां के गवर्नर श्रीप्रकाश जी ने नेहरू की इच्छा के विपरीत राजा जी को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया तो एक साम्यवादी सदस्य ने पूछा था कि आपकी नीति क्या होगी? राजा जी ने फ़ौरन जवाब दिया था कि आप मेरे दुश्मन नंबर एक हैं और मैं आपका दुश्मन नंबर एक हूं. वहीं से शुरू हुआ उनके ख़िलाफ़ अभियान. हालांकि बाद में नेहरू के विरोध के चक्कर में राजा जी ने दुश्मन नंबर एक से दोस्ती कर ली थी. डॉ. प्रसाद की तरह राजा जी भी अपने धार्मिक विचारों को सामने रखने में गुरेज़ नहीं करते थे. उनके अंदर किसी प्रकार का छद्म नहीं था, लेकिन उनका भी दोष यही था कि रामायण और महाभारत को वह भारतीय संस्कृति का आधार मानते थे.

दरअसल, भारत में पाठ्य पुस्तकों का लेखन या कहें कि देश की शिक्षा व्यवस्था शुरुआत से ही विचारधारा की गुलामी में जकड़ी रही है. जवाहर लाल नेहरू के समय से यह काम शुरू हुआ और इंदिरा गांधी के ज़माने में इसने अपनी जड़ें बेहद गहरी कर लीं. इमर्जेंसी के समर्थन की क़ीमत वामपंथी बुद्धिजीवियों ने जमकर वसूली और सरकारी संस्थानों पर क़ब्ज़ा जमा लिया. इंदिरा गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझती थीं कि वामपंथी बुद्धिजीवियों को किसी भी संस्थान का झुनझुना पकड़ा कर देश एवं समाज की समस्याओं के बारे में सोचने का वक़्त न देना ही बेहतर है. उन्होंने अपने इस सिद्धांत पर अमल करते हुए बौद्धिक वर्ग का बेहतर तरीक़े से गवर्नेंस में इस्तेमाल किया. बाद के वर्षों में तो शिक्षा व्यवस्था में वे इतने गहरे पैठ गए कि उन्हें हिलाना मुमकिन नहीं रहा. बीच में कुछ लोहियावादी बुद्धिजीवी धूमकेतु की तरह उभरे, लेकिन लोहियावादियों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है. उनका मुख्य काम था व्यवस्था को जी भरकर कोसना और हर चीज़ की आलोचना करना. लिहाज़ा वे ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाए और अब तो वामपंथियों का हाथ पकड़ कर किसी तरह अपनी पहचान बचाने में जुटे हैं. कई लोहियावादियों ने तो भगवा चोला भी धारण कर लिया. उससे इतर वामपंथियों के सामने हमेशा से एक उद्देश्य था या और वे उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे. इस वजह से वे अब भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक बने हुए हैं.

आज़ादी के बाद से ही इस देश में पाठ्य पुस्तकों का लेखन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या विचारधारा विशेष के प्रभाव में किया गया है. लेखन में निरपेक्षता या वस्तुनिष्ठता रही नहीं. लेखन में जिस तरह से विचारधारा को थोपा गया या फिर उसे किनारे लगाया गया, उन सवालों से टकराने की कोशिश शिक्षा जगत में कम ही हुई है. जिसने भी इस तरह के सवाल उठाने की कोशिश की, उसे भगवा क़रार देकर ठिकाने लगा दिया गया. इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं, लेकिन जिस तरह से देश में नई पीढ़ी का उदय हो रहा है और देश के युवा विचारधारा मुक्त हो रहे हैं, वे इन सवालों को उठाने लगे हैं. सरकार के सामने वक़्त रहते चेतने का विकल्प अब भी है. अगर वह ऐसा कर पाई तो हम भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे, जिसका आधार निरपेक्षता होगी, विचारधारा नहीं. वरना आने वाली पीढ़ियां सवालों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देंगी कि विचार तो दूर, धारा भी उससे पार नहीं पा सकेगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

उर्दू के मशहूर कवि एवं व्यंग्यकार इब्ने इंशा का असली नाम शेर मुहम्मद ख़ान था. उनका जन्म 15 जून, 1927 को पंजाब के जालंधर ज़िले के फिल्लौर में हुआ था. उनकी शुरुआती शिक्षा लुधियाना में हुई. उन्होंने 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया, लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया. उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए 1953 में कराची यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की. उन्होंने रेडियो में भी काम किया. बाद में वह क़ौमी किताब घर के निदेशक बने. इब्ने इंशा इंग्लैंड स्थित पाकिस्तान दूतावास में सांस्कृतिक मंत्री और फिर पाकिस्तान में यूनेस्को के प्रतिनिधि रहे.

इब्ने इंशा ने बहुत कम उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था. वह अपने असली नाम की बजाय इब्ने इंशा नाम से लिखते थे और इसी नाम से उन्हें ख्याति मिली. वह उर्दू की रचनाओं में हिंदी शब्दों का ख़ासा इस्तेमाल करते थे. उन्हें यात्रा लेखक और स्तंभकार के तौर पर भी जाना जाता है. उनकी रचनाओं के कई संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें कविता संग्रह-इस बस्ती के इक कूचे में, चांद नगर, दिले-वहशी, यात्रा वृतांत-आवारा गार्ड की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बबूता के ताक़ुब, चलते हों तो चीन को चलिए, नगरी-नगरी फिरा मुसाफ़िर और हास्य व्यंग्य कुमार-ए-गंदम, ख़त इंशा जी के शामिल हैं. उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ. कैंसर से जूझते हुए 11 जनवरी, 1978 को लंदन में उनका निधन हो गया. उनका शव पाकिस्तान लाया गया और कराची में उन्हें सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया. इब्ने इंशा की किताब-उर्दू की आख़िरी किताब की व्यंग्य कथाएं बहुत मशहूर हुईं.

हमारा मुल्क

ईरान में कौन रहता है?
ईरान में ईरानी क़ौम रहती है.
इंगलिस्तान में कौन रहता है?
इंगलिस्तान में अंग्रेजी क़ौम रहती है.
फ्रांस में कौन रहता है?
फ्रांस में फ्रांसीसी क़ौम रहती है.
ये कौन सा मुल्क है?
ये पाकिस्तान है.
इसमें पाकिस्तानी क़ौम रहती होगी?
नहीं, इसमें पाकिस्तानी क़ौम नहीं रहती. इसमें सिंधी क़ौम रहती है, इसमें पंजाबी क़ौम रहती है, इसमें बंगाली क़ौम रहती है, इसमें यह क़ौम रहती है, इसमें वह क़ौम रहती है.
लेकिन पंजाबी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सिंधी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, फिर यह अलग मुल्क क्यों बनाया?
ग़लती हुई, माफ़ कीजिए, आइंदा नहीं बनाएंगे.

भारत

यह भारत है. गांधी जी यहीं पैदा हुए थे, यहां उनकी बड़ी इज़्ज़त होती थी, उन्हें महात्मा कहते थे. चुनांचे मारकर उन्हें यहीं दफ़न कर दिया और समाधि बना दी. दूसरे मुल्कों के बड़े लोग आते हैं तो इस पर फूल चढ़ाते हैं. अगर गांधी जी नहीं मारे जाते तो पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं के लिए फूल चढ़ाने के लिए कोई जगह ही न थी. यह मसला हमारे यानी पाकिस्तान वालों के लिए भी था. हमें क़ायदे आज़म जिन्ना साहब का एहसानमंद होना चाहिए कि वह ख़ुद ही मर गए और टूरिस्टों के लिए फूल चढ़ाने की एक जगह पैदा कर दी, वरना शायद हमें भी उनको मारना ही पड़ता. भारत का पवित्र जानवर गाय है. भारतीय उसी का दूध पीते हैं, उसी के गोबर से लीपा करते हैं, लेकिन आदमी को भारत में पवित्र जानवर नहीं माना जाता.

कछुआ और ख़रगोश

एक था कछुआ, एक था ख़रगोश. दोनों ने आपस में शर्त लगाई. कोई कछुए से पूछे कि तूने शर्त क्यों लगाई, क्या सोचकर लगाई? बहरहाल, तय यह हुआ कि जो पहले नीम वाले टीले पर पहुंचेगा, उसे हक़ होगा कि दूसरे के कान काट ले. दौड़ शुरू हुई तो कछुआ रह गया और ख़रगोश तो यह जा कि वह जा. कछुआ अपनी परंपरागत रफ्तार से चलता रहा. कुछ देर चला तो ख्याल आया कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, बहुत चल लिए. आराम करते-करते नींद आ गई. न जाने कितना ज़माना सोते रहे. आंख खुली तो सुस्ती बाक़ी थी. बोले, अभी क्या जल्दी है. इस ख़रगोश के बच्चे की क्या औक़ात कि मुझसे जीत सके. वाह भाई वाह, मेरे क्या कहने. काफ़ी ज़माना सुस्ता लिए तो फिर मंज़िल की तरफ़ चल पड़े. वहां पहुंचे तो देखा ख़रगोश न था. बेहद ख़ुश हुए. अपनी मुस्तैदी की दाद देने लगे. इतने में उनकी नज़र ख़रगोश के एक पिल्ले पर पड़ी. उससे ख़रगोश के बारे में पूछने लगे. ख़रगोश का बच्चा बोला, जनाब वह मेरे वालिद साहब थे और मुद्दतों आपका इंतज़ार करने के बाद मर गए और वसीयत कर गए कि कछुए मियां यहां आ जाएं तो उनके कान काट लेना. लिहाज़ा लाइए इधर कान...

कछुए ने फ़ौरन कान और अपना सिर ख़ोल के अंदर कर लिया और आज तक छिपाए फिरता है.

इब्ने इंशा ने गद्य ही नहीं, पद्य में भी अच्छी ख़ासी लोकप्रियता हासिल की. उनकी एक रचना:-

कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा
कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा
हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए
हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंज़ूर था पर्दा तेरा
इस शहर में किससे मिलें, हमसे तो छूटी महफ़िलें
हर शख़्स तेरा नाम ले, हर शख़्स दीवाना तेरा
कूचे को तेरे छोड़कर, जोगी ही बन जाएं मगर
जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा
तू बेवफ़ा, तू मेहरबां, हम और तुझसे बदगुमां
हमने तो पूछा था ज़रा, ये वक़्त क्यूं ठहरा तेरा
हां, हां तेरी सूरत हसीं, लेकिन तू ऐसा भी नहीं
इस शख़्स के अश्आर से, शोहरा हुआ क्या-क्या तेरा
बेशक उसी का दोष है, कहता नहीं ख़ामोश है
तू आप कर ऐसी दवा, बीमार हो अच्छा तेरा
बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी ग़ज़ल
आशिक़ तेरा, रुसवा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा. ■

4-स्ट्रोक, 112.8 सीसी, सिंगल सिलेंडर की क्षमता की इस बाइक में कंपनी ने 4-स्पीड गियर बॉक्स को शामिल किया है.

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यहां के बाज़ार में एक नई कार को उतारा गया है. इस कार का नाम है लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर. लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में वी12 इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इस कार की अधिकतम स्पीड लगभग 342 किलोमीटर प्रतिघंटा है.

लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर का जलवा

देश में कार का क्रेज बढ़ रहा है. यही वजह है कि महंगी से महंगी कारें भारतीय बाज़ार में उतारी जा रही हैं. अच्छी बात यह है कि कारों की कंपनियां यहां बेहतर व्यापार भी कर रही हैं. इसी क्रम में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यहां के बाज़ार में एक नई कार को उतारा गया है. इस कार का नाम है लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर. लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में वी12 इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इस कार की अधिकतम स्पीड लगभग 342 किलोमीटर प्रतिघंटा है.

इस कार की पिकअप तो आप सभी को हैरान करने में सक्षम है. यह कार महज़ 2.9 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है. इस कार का इंजन लगभग 700 बीएचपी की शक्ति उत्पन्न करता है, जो कार को एक बेहतर गति देता है. लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर एलपी 700-4 एक दमदार इंजन क्षमता से लबरेज़ है. 12 सिलेंडर, और 6.5 लीटर की इंजन क्षमता, 700 हार्स पावर, 515 किलोवाट की शक्ति इस कार को एक शानदार गति प्रदान करती है. भारतीय बाज़ार में इस कार की क़ीमत लगभग 3.69 करोड़ रुपये तय की गई है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सुजुकी की किफ़ायती बाइक हयाते

यदि आप कम बजट में एक बेहतरीन कम्यूटर बाइक से फर्राटा भरना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौक़ा है. जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी ने इस बार भारतीय बाज़ार में अपनी बेहतरीन कम्यूटर बाइक हयाते को पेश कर दिया है. सुजुकी ने इस बाइक को बेहद किफ़ायती दाम में बाज़ार में उतारा है. सुजुकी की इस नई बाइक की क़ीमत महज़ 41,000 रुपये है. कंपनी ने इस बाइक में 110 सीसी की क्षमता का शानदार इंजन प्रयोग किया है. इस बाइक में कंपनी ने अपने सेगमेंट के अनुसार, लगभग सभी फीचर्स को शामिल किया है. नई हयाते में कंपनी ने 8 लीटर का पेट्रोल टैंक है. 4-स्ट्रोक, 112.8 सीसी, सिंगल सिलेंडर की क्षमता की इस बाइक में कंपनी ने 4-स्पीड गियर बॉक्स को शामिल किया है. इसके अलावा 17 इंच का एलॉय व्हील और 5-वे एडजेस्टेबल हाइड्रोक्यूलिक शॉकर का प्रयोग किया है, जो आपको लंबे सफ़र में भी बेहतरीन राइड का अनुभव कराएगी. इस बाइक का कुल वज़न मात्र 112 किलोग्राम है, जो बाइक की बेहतर माइलेज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बेहद शानदार इंजन क्षमता और स्टाइलिश लुक इस बाइक को ख़ास बनाता है. भारतीय बाज़ार में कंपनी ने इस बाइक को आकर्षक रंगों के साथ उतारा है. सुजुकी की यह नई हयाते आपको सफ़ेद, हरे, ग्रे, लाल और काले रंग में मिलेगी. कंपनी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड के दबंग सलमान ख़ान को अपनी इस बेहतरीन बाइक का ब्रांड एम्बेस्डर चुना है.■

बेहतर और सस्ता टैबलेट

आईएक्सए नाम से लांच किए गए नए एंड्रॉयड टैबलेट में आकाश और यूबीस्लेट टैबलेट के मुक़ाबले बेहतर फीचर दिए गए हैं.

बाज़ार में आकाश टैबलेट की बात क्या हुई, सभी गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों के बीच मारा-मारी शुरू हो गई. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मरकरी ब्रांड ने भी एक नया प्रोडक्ट लांच किया है. मरकरी ब्रांड के अंतर्गत आने वाले कोबियन ने भारतीय बाज़ार में एक नया एंड्रॉयड टैबलेट लांच किया है. कोबियन ने नए टैबलेट को मात्र 3,999 रुपये की आकर्षक क़ीमत में पेश किया है. इससे पहले इतनी कम क़ीमत में आकाश टैबलेट लांच किया गया था, मगर अभी तक बाज़ार में आकाश उपलब्ध नहीं हो पाया है. आईएक्सए नाम से लांच किए गए नए एंड्रॉयड टैबलेट में आकाश और यूबीस्लेट टैबलेट के मुक़ाबले बेहतर फीचर दिए गए हैं. तकनीकी रूप से टैबलेट के फीचरों पर एक नज़र डालें तो इस कोबियन आईएक्सए टैबलेट में एंड्रॉयड 2.3 वर्जन ओएस के साथ 1 गीगाहर्ट का कोर प्रोसेसर डाला गया है. 241 ग्राम वज़न के इस टैबलेट को कहीं लाने ले जाने में कोई मुश्किल नहीं है. इसमें 512 एमबी रैम और 4 जीबी इंटरनल मैमोरी का ऑप्शन भी दिया गया है. इससे काफ़ी सारा डाटा एक साथ इस टैबलेट में रखा जा सकता है, और वह भी किसी भी फॉरमेट में. इतना ही नहीं टैबलेट की मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट की मदद से 32 जीबी तक एक्पेंड भी कर सकते हैं. साथ ही एक बोनस की तरह इसमें 0.3 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसे कसी भी वक़्त अपने बेहतरीन क्षणों को संजोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. किसी भी ऑडियो-वीडियो को प्ले करने के लिए इसमें एमपी3, वेव, डब्ल्यूएमए और एएसी फाइल फार्मेट सपोर्ट सिस्टम डाला गया है. ■

बाएं से दाएं, मार्क केनवर्थी जनरल मैनेजर, राधे कपूर चेयरमैन, सेलेक्ट कार प्राईवेट लिमिटेड, यदुर कपूर सीईओ सेलेक्ट कार प्राईवेट लिमिटेड, नील स्लेड रीजनल जनरल मैनेजर (बीच में) एंडी गौथोप, ग्लोबल सेल्स डायरेक्टर एसटन मार्टिन नई दिल्ली में कार लांच करते हुए

सोनी एक्सपीरिया में दो नए मॉडल

सोनी ने अपनी एक्सपीरिया सीरीज के तहत दो नए स्मार्ट फोन मॉडल लांच किए हैं. फीचरों के मामले में दोनों हैंडसेट एक दूसरे से अलग हैं, मगर सोनी एक्सपीरिया जीएक्स और एसएक्स में एक ही तरह का 4.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. एक्सपीरिया एसएक्स में 3.7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है. इसके अलावा एसएक्स में 1.5 गीगाहर्ट का क्वालकॉम प्रोसेसर दिया गया है. फोन में डेटा सेव करने के लिए 8 जीबी का अच्छा मैमोरी सपोर्ट मौजूद है, जबकि जी एक्स में 4.6 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो 1280/720 पिक्सल रेज्योलूशन को सपोर्ट करती है. एक्सपीरिया के पहले मॉडल के मुक़ाबले जीएक्स में 16 जीबी की इंटरनल मैमोरी दी गई है. एक्सपीरिया एसएक्स में 8 मेगापिक्सल कैमरे के साथ इमेज सेंसर भी लगा हुआ है, जो ऑटोमेटिक इमेज सेंस कर उसे कैपचर कर लेता है. एक्सपीरिया जीएक्स में 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, जो एसएक्स से ज़्यादा पॉवरफुल है. हालांकि दोनों में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा लगा हुआ है. सोनी एक्सपीरिया जीएक्स और एसएक्स 95 ग्राम का है. इसमें 1.5 गीगाहर्ट का ड्युअल कोर प्रोसेसर डाला गया है. यह एंड्रॉएड 4.0 आईस्क्रीम सैंडविच ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जिससे इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है. 8 जीबी इंटरनल मैमोरी के साथ इसमें इंफ्रारेड डेटा पोर्ट डाला गया है. इसमें ख़ास मोबाइल वॉलेट सॉफ्टवेयर भी डाला गया है, जिससे यूजर को इस फोन का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है. ■

मस्त है निकॉन डी 5100

निकॉन का डी-5100 एक नया 16.2 मेगापिक्सल कैमरा डीएसएलआर कैमरा है, जो डी 3100 और डी-7000 के बीच की कड़ी है. यह न केवल यूजर फ्रेंडली है, बल्कि कार्यक्षमता में भी बेहतर है. इस कैमरे को सबसे ख़ास बनाती है इसकी स्क्रीन. कैमरे का 3 इंच का टीएफटी एलसीडी मॉनीटर आपको मुश्किल समय में भी बेहतरीन शॉट्स देता है. निकॉन डी-5100 से आप 1920/1280 पिक्सल/25 एफपीएस की स्पीड पर पूर्ण एचडी फिल्मों को रिकॉर्ड कर सकते हैं. इस एक गैजेट में आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे 4 एफएक्स शूटिंग मोड 3 डी फोकस ट्रैकिंग आदि. भारतीय बाज़ार में इस कैमरे की क़ीमत क़रीब 49,000 रुपये है. कैमरा जितना हल्का है, उतना ही इसको चलाना आसान है. अगर कैमरे की बनावट पर ग़ौर किया जाए तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर को उंगलियों को आराम देने के लिए इसकी ग्रिप में रबड़ का इस्तेमाल किया गया है. कैमरे में 18-55 लैंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इससे ली गई तस्वीरों को एक अलग ही ख़ूबसूरती देता है. इस कैमरे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए भी शूट किया जा सकता है. यह 3:2 का इमेज रेशियो देता है और इसका व्यू फाइनडर कवरेज 95 प्रतिशत है. इसमें बिल्ट इन फ्लैश है, जो 12 मीटर का फ्लैश रेंज देता है. इसमें निकॉन ईएनईल बैटरी का इस्तेमाल होता है.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सरकार खिलाड़ियों से खेल रही है

नवीन चौहान
navinchauhan@chauthiduniya.com

कुछ दिन पहले पान सिंह तोमर नाम की एक फिल्म आई थी. फिल्म के निर्देशक तिगमांशु धूलिया ने खिलाड़ी से बाग़ी बनने की एक कहानी को रूपहले परदे पर दिखाया. हिमांशु ने इस फिल्म को उन खिलाड़ियों को समर्पित किया, जिन्होंने देश के गौरव और सम्मान के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया और इसके बाद भी वे गुमनामी और बदहाली में जीने को मजबूर रहे. एक और फिल्म है चक दे इंडिया, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की बदहाली से बाहर निकलने और विजेता बनने की कहानी है. इन फिल्मों को बहुत पसंद किया गया. दोनों फिल्मों ने सरकार और समाज के सामने यह सवाल खड़ा किया कि देश में क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों के खिलाड़ियों की हालत ख़राब क्यों है? सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कोई क़दम क्यों नहीं उठा रही है? इन दोनों फिल्मों में कठघरे में सरकार ही खड़ी नज़र आई. पान सिंह तोमर का सरकार की बेरुख़ी से डकैत बन जाना और खिलाड़ियों का पाई-पाई के लिए मोहताज हो जाना, दोनों ही परिस्थितियां हमें सोचने को मजबूर करती हैं. आज़ादी के समय जो परिस्थितियां थीं, आज उनमें मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले झारखंड की एक महिला तीरंदाज़ द्वारा तंगहाली से परेशान होकर धनुष बेचने की ख़बर आई और सरकार के खिलाड़ियों के कल्याण के दावों को खोखला साबित कर गई.

50 का दशक भारतीय खेलों के लिहाज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. आज़ादी के बाद खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत को पहचान दिलाई थी. उन्होंने अपने हुनर के दम पर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया था, लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा हुई. उनमें से आज जो जीवित हैं, वे बदहाल हैं. जो जीवित नहीं हैं, उन्होंने तंगहाली में अपना जीवन गुज़ार दिया. सरकार ने न तो उनकी जीते जी सुध ली और न उनकी मौत के बाद उन्हें याद किया. पान सिंह तोमर फिल्म के माध्यम से एक बार फिर चंबल के बीहड़ों की कहानियां सामने आ गईं. इस फिल्म में दिखाया गया कि खेलों से देश का सम्मान बढ़ाने वाले मेडलों की सरकार की नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है. उनकी सेवा का कोई मूल्य नहीं है. भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाने वाले केडी जाधव, हॉकी में चार स्वर्ण पदक जीतने वाले शंकर लक्ष्मण, 1954 के एशियाई खेलों में भारत को बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जिताने वाले सरवन सिंह, 1954 के एशियाई खेलों में भारत को गोला फेंक और डिस्कस थ्रो का स्वर्ण पदक दिलाने वाले प्रदुम्य सिंह सहित ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, जिन्हें कंगाली में अपना जीवन गुज़ारना पड़ा. किसी को अपने इलाज के लिए जूझना पड़ा, तो किसी को अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पदकों को बेचना पड़ा.

हमारे नेता खेलों के विकास के लिए कितने गंभीर हैं, यह नए खेल बिल पर उनके विरोध से ज़ाहिर हो जाता है. आज दुनिया में खेल केवल खेल नहीं रह गए हैं, इसके राजनीतिक मतलब भी हो गए हैं. अब देश के विकास को खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रदर्शन के साथ जोड़कर देखा जाता है.

आज तक सरकार कोई ऐसी खेल नीति नहीं बना पाई है, जिसमें पुराने खिलाड़ियों की योग्यता का उपयोग करते हुए नए खिलाड़ियों की नई खेप पैदा की जा सके. उड़न सिख मिल्खा सिंह ने कई बार कहा है कि अगर पचास और साठ के दशक में भारत में मिल्खा सिंह हो सकता है तो आज ऐसा क्यों संभव नहीं है. खिलाड़ियों के लिए सरकारी बेरुख़ी और उन्हें किसी प्रकार की मदद न मिलती देख नई पीढ़ी ने खेलों से मुंह मोड़ लिया और 60 के दशक के बाद हमारा प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरता गया. खेल प्रबंधन में खिलाड़ियों की जगह नेताओं का क़ब्ज़ा हो गया. नेताओं ने खेल प्राधिकरणों के साथ-साथ खेलों का भी कबाड़ा कर दिया. नेताओं को न तो खेलों का ज्ञान था, और न उन्हें इनके विकास की संभावनाओं की जानकारी थी. वे वर्षों तक उच्च पदों पर कुंडली मारकर बैठे रहे. उन्होंने न तो खेलों का विकास किया और न पुराने खिलाड़ियों के अनुभव का फ़ायदा उठा सके. पुराने खिलाड़ी रोज़ी-रोटी को तरसते रहे और जिन खेलों ने उन्हें नाम दिया था, उसी से वे दूर होते गए. यहां तक कि अपने बच्चों को अपने हुनर का उत्तराधिकारी बनाने की बजाय क्रिकेट, टेनिस और गोल्फ जैसे व्यवसायिक खेलों में जाने दिया. अगर पुराने खिलाड़ियों को खेल प्राधिकरण में जगह दी गई होती तो वे गुमनामी का शिकार न होते और शायद आज देश में खेलों की स्थिति भी बेहतर होती.

आज हम फिर ओलंपिक खेलों के मुहाने पर खड़े हैं. सवा अरब की आबादी वाला देश खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है. सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतकर खिलाड़ी देश को गौरान्वित करें. मगर सरकार अपनी ओर से कोई नई पहल करती नज़र नहीं आ रही है, जिससे ओलंपिक में हमारा रिकॉर्ड सुधर सके. सरकार के पास चीन की तरह खेलों के विकास की कोई दूरदर्शी योजना नहीं है. सरकार अगर कोई योजना बनाती भी है, तो उसमें पूर्व खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है. खिलाड़ियों का काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं. ये योजनाएं ज़मीनी स्तर पर धराशायी हो जाती हैं और वर्षों बाद भी अच्छे परिणाम सामने नहीं आते हैं. हमारे नेता खेलों के विकास के लिए कितने गंभीर हैं, यह नए खेल बिल पर उनके विरोध से ज़ाहिर हो जाता है. आज दुनिया में खेल केवल खेल नहीं रह गए हैं, इसके राजनीतिक मतलब भी हो गए हैं. अब देश के विकास को खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रदर्शन के साथ जोड़कर देखा जाता है. हमारे देश में निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र हित को दरकिनार किया जा रहा है. अगर हम अब भी नहीं जागे तथा पुराने खिलाड़ियों को ऐसे ही दरकिनार करते रहे तो शायद ही हम हॉकी और अन्य खेलों का स्वर्णिम भविष्य देख पाएंगे. ■

मैंचेस्टर सिटी 44 साल बाद चैंपियन बना

मैंचेस्टर सिटी 44 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का ख़िताब जीतने में कामयाब हुई है. मैंचेस्टर सिटी ने आख़िरी बार 1968 में ईपीएल ख़िताब अपने नाम किया था. इस सीजन मैंचेस्टटर सिटी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. फाइनल में मेंचेस्टर सिटी ने क्वीन पार्क रेंजर्स को 3-2 से हराकर ख़िताब जीता. मैच के निर्णायक दो गोल इंजरी टाइम में हुए और गोल अंतर के हिसाब में मैंचेस्टर यूनाइटेड को पछाड़ते हुए मैंचेस्टर सिटी विजेता बन गया. इस ख़िताबी जीत के बाद मेंचेस्टर सिटी के कोच रोबर्टो मैनसिनी ने कहा कि यह दिन क्लब और प्रशंसकों के लिए ऐतिहासिक है. मैंचेस्टर सिटी ने आख़िरी पांच मिनट में दो गोल करके मेंचेस्टर यूनाइटेड को 13 वीं बार ईपीएल विजेता बनने से रोक दिया.

परिमार्जन नेगी एशियाई शतरंज चैंपियन बने

ग्रैंडमास्टर परिमार्जन नेगी ने वियतनाम में हुई एशियन कांटिनेंटल चेस प्रतियोगिता जीत ली है. अंतिम मैच में यूएई के एआर सलह सलेम से हारने के बावजूद नेगी अंक तालिका में शीर्ष पर रहे. नेगी प्रतियोगिता में कुल 7 अंक बटोरकर चीन के यू यंगेई के साथ शीर्ष पर थे. मगर नेगी और यंगेई के बीच हुए मुक़ाबले में नेगी ने जीत हासिल की थी. इसी आधार पर नेगी को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया. यंगेई को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा.

स्पेनिश ग्रां प्री पास्टोर मालडोनाडो की जीत

इस सीजन फॉर्मूला वन में अब तक हो चुकी पांच रेसों में अलग अलग विजेता सामने आए हैं. इस रेस में जीत हासिल करने वाले पास्टोर मालडोनाडो फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले पहले वेनेजुएलाई ड्राइवर बन गए हैं. विलियम्स टीम के मालडोनाडो ने विलियम्स टीम को 132 रेसों और 8 साल बाद विजेता बना दिया. रेस में फेरारी के फर्नेंडो अलोंसो दूसरे स्थान पर रहे और लोटस के किमी रेकोनेन तीसरे स्थान पर रहे. आख़िरी बार विलियम्स टीम के किसी खिलाड़ी ने 2004 में फार्मूला वन रेस जीती थी. नौ बार मैंयुफैक्चर विजेता रह चुकी विलियम्स की टीम आख़िरी बार 1997 में चैंपियन बनी थी.

ओमप्रकाश का गोला फेंक में नेशनल रिकॉर्ड

ओमप्रकाश सिंह ने गोला फेंक (शार्टपुट) का 12 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है. ओमप्रकाश ने 20.69 मीटर की दूरी तक गोला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया. 25 वर्षीय ओमप्रकाश ने शक्ति सिंह द्वारा 2000 में बनाए 20.42 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा. शक्ति सिंह ने लंदन ओलंपिक के लिए ए स्टैंडर्ड की वरीयता हासिल कर ली है, लेकिन ओमप्रकाश के इस प्रदर्शन के बावजूद इसे नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड माने जाने की बहस छिड़ी हुई है.

मिताली इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान होंगी

भारतीय महिला टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए मिताली राज को कप्तान नियुक्त किया गया है. अंजुम चोपड़ा को कप्तानी के साथ-साथ टीम से जगह भी गंवानी पड़ी है. झूलन गोस्वामी को कप्तान के पद से हटाए जाने के बाद मिताली को कप्तान बनाने की अटकलें लग रही थीं. मगर आश्चर्यजनक रूप से दो साल बाद टीम में वापसी कर रही अंजुम को टीम का कप्तान बना दिया गया था. मगर पिछली प्रतियोगिताओं में अंजुम के ख़राब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और यह ज़िम्मेदारी स्टार बल्लेबाज़ मिताली राज को सौंप दी गई है. भारतीय टीम को 25 जून से 11 जुलाई के बीच इंगलैंड के साथ 2 टी-20 और पांच एक दिवसीय मुक़ाबले खेलने हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 मई–03 जून 2012

पंकज कपूर को हिंदी फिल्मों में अभिनय का पहला मौक़ा श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण में मिला. इसके तुरंत बाद वह फिल्म गांधी में प्यारेलाल की भूमिका में दिखे.

हॉलीवुड

मेक अप आर्टिस्ट रिक बेकर

क्या कभी किसी ने सोचा था कि बचपन में अपने घर की रसोई के सामान से राक्षस का मेकअप करने वाले रिक बेकर किंग कांग (1976), एन अमेरिकन वेरेवोल्फ इन लंदन, स्टार वार्स, हेलबॉय, द वोल्फ मैन जैसी बड़ी-बड़ी फिल्मों में बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम करेंगे. ऑस्कर विजेता रिक बेकर ने मेन इन ब्लैक की पिछली दोनों सीरीज में भी बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम किया था. अब इसी जुड़ाव को क़ायम रखते हुए वह सोनी पिक्चर्स इंडिया की फिल्म मेन इन ब्लैक-3 से भी जुड़े हुए हैं. यह फिल्म अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु में भी बनी है. तीनों सीरीज से जुड़े रिक मेन इन ब्लैक-3 के बारे में बताते हैं कि इस फिल्म में काम करते हुए उन्हें न केवल स्टार्स का मेकअप करने में मज़ा आया, बल्कि कहानी भी उन्हें बहुत पसंद आई. वह कहते हैं कि जब भी आप इस तरह की किसी भी फिल्म में काम करते हैं, जिसमें आज के समय यानी 2012 के समय के एलियंस दिखाए गए हैं, वही 1969 के समय के रेट्रो एलियंस भी दिखाए गए हैं, जो बहुत ही अलग होते थे. उनकी आंखें बड़ी-बड़ी होती थीं और वे हेलमेट पहने हुए होते थे.

इसी तरह इस फिल्म के लिए आर्टिस्ट के तौर पर मेकअप करने में मुझे नई चुनौती का भी एहसास हुआ, क्योंकि दो अलग-अलग के तरह के मेकअप एक ही तरह के कैरेक्टर के लिए वह भी ऐसा, जिससे लोग समय को रीलेट कर पाएं, यह थोड़ा मुश्किल है. जब अचानक एक एलियन की ज़रूरत हुई, जो पिछली स्क्रिप्ट से ख़त्म हो गया था. मैंने कुछ डिजाइन भी तैयार किए, लेकिन बात नहीं बनी. फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर मैंने बोलिंग ऐली की बॉल लेकर उसे ही पेंट करके उसका चेहरा बना दिया. इस हिसाब से शूट में भी बदलाव किया गया. हमने इसका लॉन्ग शॉट लेना ही उचित समझा. 62 वर्ष के रिक बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं, और अपने काम को लेकर उन्हें बहुत ही गर्व है. इसके साथ ही उन्हें ख़ुशी है कि वह फिल्म मेन इन ब्लैक की सभी सीरीज से जुड़े हुए हैं. इस फिल्म में काम करते हुए उन्हें न केवल अपनी कल्पना को वास्तविक रूप देने का मौक़ा मिला, बल्कि उन्हें प्रोडक्शन के कई अन्य पहलुओं पर भी एक सहयोगी की तरह काम करने का अवसर मिला. रिक बताते हैं, मैंने बहुत कुछ अपने विचारों के मुताबिक़ भी किया. ख़ासकर मेन इन ब्लैक की पहली सीरीज में, जो कैरेक्टर फिल्म की स्क्रिप्ट में नहीं था, वह भी डाल लिया गया, सिर्फ़ उनके कहने पर. वह कहते हैं, फिल्म के निर्देशक बैरी सोनेनफील्ड मुझे सिर्फ़ राक्षस का मेकअप करने वाला नहीं, बल्कि अपना एक सहयोगी समझते हैं. राक्षस और एलियन का मेकअप करने में माहिर रिक ने सोनी पिक्चर्स इंडिया की फिल्म मेन इन ब्लैक-3 में जोश ब्रोलिन का भी शानदार मेकअप किया है. उन्हें इस फिल्म में जोश को युवा टॉमी ली जोंस का युवा रूप दिखाना था. रिक ने बताया कि जोश ब्रोलिन का ख़ुद का एक व्यक्तिगत मेकअप कलाकार है क्रिस्टन टीन्स्ले, जो अपने काम में माहिर हैं. रिक जानते थे कि जोश उससे ही मेकअप करवाना पसंद करेंगे. फिर भी उन्होंने क्रिस्टन से कहा कि वह जोश का बस नाक और कान का ही मेकअप करें. हॉलीवुड में जोश ऐसे अभिनेता हैं, जो हमेशा अपनी मेकअप प्रक्रिया में शामिल रहते हैं. अपनी समझ से उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि गाल और माथे पर मेकअप हो, लेकिन रिक अपनी बात पर ही अडिग थे. जोश ने आख़िरकार उनकी बात मान ली. पहले उन्होंने गाल और माथे का मेकअप ट्राई किया, फिर दूसरा यानी नाक और कान का. रिक द्वारा किए गए कान और नाक के मेकअप में बहुत ही अच्छे लग रहे थे जोश. जैसा लुक स्क्रिप्ट की डिमांड थी, अगर वैसा ही लुक मेकअप आर्टिस्ट दे दें तो इससे अच्छी बात क्या होगी. ■

लालची कैटरीना

कौन नहीं चाहता कि इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों का नाम उनसे जुड़े, लेकिन कैटरीना की ख्वाहिश तो कुछ और हीं है. वह तो इंडस्ट्री के तीनों ख़ान को अपनी जेब में रखना चाहती हैं, जिससे तीनों ख़ान सिर्फ़ उनके साथ ही फिल्में करें. उन्होंने ख़ुद ही कहा कि उनका बस चले तो आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ इंडस्ट्री की दूसरी अभिनेत्रियों को काम न करने दें. यह कहने का उनका हौसला हुआ, उनकी आगामी फिल्म एक था टाइगर के फर्स्ट लुक की रीलीज के बाद आए फैंस के रेस्पोंस से. इस फिल्म में उनके साथ उनके पुराने यार सलमान हैं, सलमान ख़ान के साथ इस फिल्म की शूटिंग को उन्होंने ख़ूब इंज्वॉय भी किया. न केवल सलमान ख़ान बल्कि वर्ष 2012 में कैटरीना इंडस्ट्री के तीनों बड़े ख़ान यानी सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आएंगी. उनका चहकना ये साबित करता है कि सलमान ख़ान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तभी यशराज बैनर के साथ वह एक रोमांटिक फिल्म में नज़र आएंगी. इस फिल्म में वह शाहरुख के अपोजिट हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्हें अनुष्का के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना पड़ा है. धूम थ्री में तो कैटरीना हैं ही आमिर ख़ान के साथ. अब भला उनसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है जिनके पास इंडस्ट्री के सभी बड़े कलाकारों के साथ काम करने का सुनहरा अवसर हो. हलांकि कैटरीना के लिए ऐसा पहले संभव नहीं था. दरअसल एक वक्त सलमान ख़ान की गर्लफ्रेंड कही जाने वाली कैटरीना पर इंडस्ट्री के दूसरे ख़ान के साथ फिल्में करने पर सख्त पाबंदी लगी हुई थी, और उनमें. ख़ासकर शाहरुख ख़ान. लेकिन अब वह ख़ुद पर लगी पाबंदी कैटरीना तोड़ चुकी हैं. सलमान से अलग होने के बाद कैटरीना का लालच ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. तभी वह किसी भी तरह का बयान देने से नहीं चूक रही हैं, लेकिन एक समझदारी की बात उन्होंने कर दी है कि उन्होंने किसी भी ख़ान को एक दूसरे से कमतर या बेहतर नहीं बताया बल्कि उन्होंने तो सबको अलग-अलग तरह से बेहतरीन बता दिया. कैटरीना ने तीनों ख़ान को विशेष आइकन कहा. और खुद की इस मामले में लकी कहा की उन्हें उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला.

बॉलीवुड को समर्पित पंकज कपूर

जन्मदिन

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक एवं अभिनेता पंकज कपूर का जन्म 29 मई, 1954 को लुधियाना में हुआ. लुधियाना में बचपन के ख़ुशनुमा दिन बिताने के बाद पंकज कपूर ने दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रुख़ किया. यहां से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रंगमंच पर अपनी अभिनय-प्रतिभा का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया. लगभग चार वर्षों तक वह रंगमंच से जुड़े रहे. पंकज कपूर को हिंदी फिल्मों में अभिनय का पहला मौक़ा श्याम बेनेगल की फिल्म आरोहण में मिला. इसके तुरंत बाद वह फिल्म गांधी में प्यारेलाल की भूमिका में दिखे. इन फिल्मों के बाद उन्होंने समानांतर सिनेमा का रुख़ किया. फिल्म मंडी, जाने भी दो यारो, मोहन जोशी हाज़िर हो, खंडहर और ख़ामोश जैसी समानांतर फिल्मों में पंकज कपूर ने अभिनय की नई परिभाषा गढ़ी. वह हिंदी सिनेमा के एक विलक्षण कलाकार हैं. हिंदी सिनेमा के दर्शकों में उस तरह की संस्कृति विकसित नहीं हो पाई है, जिस तरह की संस्कृति भाषाई ख़ासकर बांग्ला और दक्षिण भाषाई सिनेमा के दर्शकों में संजीदगी और जागरूकता के स्तर पर दिखाई देती है. पंकज कपूर शुरू से ही अपने किरदारों के साथ इंसाफ़ करने के मामले में गंभीर रहे हैं. उनका अपना रचनात्मक स्वभाव है. वह अपनी बनाई हुई दुनिया में ही रहते हैं, फिल्में हासिल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही है. निर्देशक उनके पास ख़ुद ही फिल्में लेकर आते हैं और केवल वैसे ही निर्देशक आते हैं जिनको यह मालूम होता है कि उनके साथ किस हद तक दख़ल नहीं देना है. पंकज कपूर अपना किरदार सुनते हैं, यदि वह सहमत होते हैं तो काम करते हैं और वह भी पूरी एकाग्रता से. शांत और चुप रहने वाले पंकज कपूर के निभाए किरदार कभी भी भुलाए नहीं जा सकते. जिन लोगों ने उनके काम को देखा है, वे इस बात को जानते भी हैं. उनके अभिनय की एक ख़ास बात है कि उनका स्वभाव उनके किरदार पर कभी प्रभावी नहीं हुआ. जो चरित्र उन्होंने पर्दे पर निभाया है, वह पर्दे पर बोलता भी है. उसमें पंकज कपूर को ढूंढ पाना असंभव ही है. ऐसा नहीं कि उन्होंने हमेशा केवल गंभीर किरदार ही निभाए हैं, बल्कि कई दिलचस्प किरदारों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. विशाल भारद्वाज की बच्चों के लिए बनाई फिल्म ब्लू अम्ब्रेला में एक लालची दुकानदार के रूप में पंकज कपूर को देखना बड़ा दिलचस्प है. पंकज कपूर एक डॉक्टर की मौत, जाने भी दो यारों फिल्म और सीरियल करमचंद, ऑफिस-ऑफिस और मोहनदास बीए एलएलबी में बड़े अलग नज़र आए हैं. गुलज़ार निर्देशित प्रेमचंद की कहानियों के अलावा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्म रूई का बोझ और विशाल भारद्वाज की ही फिल्म मक़बूल में उनका मुख्य किरदार असाधारण है. ऐसा कह सकते हैं कि यह किरदार उनके सिवा कोई और कलाकार इस प्रभाव के साथ निभा ही नहीं सकता था. भावना तलवार की फिल्म धर्म में भी वह अपने किरदार को उसके स्वभाव और संवेदनशील पहलुओं के साथ जिस तरह से निभाते हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने फिल्म दस में सशक्त खलनायक की भूमिका भी निभाई. उन्होंने फिल्म मौसम का निर्देशन किया, जिसमें उनके बेटे शाहिद और सोनम कपूर नज़र आए. हालांकि यह फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हुई, मगर इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने अपने बचपन के सपने को जिया है. बचपन से उन्हें पायलट बनने का शौक़ था. छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक और कला फिल्मों से लेकर व्यावसायिक फिल्मों तक पंकज कपूर के अभिनय ने दर्शकों पर प्रभावी छाप छोड़ी है. हालांकि पंकज कपूर के निजी जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए, पर विवादों के साये से वह हमेशा दूर रहे. पहली पत्नी नीलिमा अज़ीम से तलाक़ और अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से विवाह को लेकर वह सुर्ख़ियों में रहे. वह नई पीढ़ी के अभिनेता-अभिनेत्रियों के प्रेरणा स्त्रोत हैं. उम्मीद है, आने वाले कई वर्षों तक अभिनय-कला के प्रति समर्पित इस प्रतिभाशाली कलाकार की हिंदी फिल्मों में उपस्थिति दर्शकों को यूं ही आकर्षित करती रहेगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गुल ऊंची उड़ान भरेंगी

ऊंची उड़ान भरने की हसरत किसे नहीं होती, मगर कुछ ही लोग हैं जिनका यह सपना पूरा हो पाता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग इस इंडस्ट्री से पहली अदाकारा हैं, जिनके पास आने वाले दिनों में अपना उड़न खटोला हो सकता है. एडवेंचर की शौक़ीन गुल पनाग इससे पहले सुपरबाइक्स पर बैठकर हवा से बातें करती थीं, लेकिन अब उन्हें फ्लाइंग लाइसेंस भी मिल चुका है. तो अब वह जल्द ही प्राइवेट एयरप्लेन ख़रीदने वाली हैं. उनके इस सपने को पूरा करने में उनका साथ देंगे उनके पति और उनके दोस्तों की मंडली, क्योंकि उनके पति के साथ-साथ उनके दोस्तों की मंडली को भी मस्ती भरी उड़ान का काफ़ी शौक़ है. गुल पनाग इन दिनों फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं, मगर इसका उन्हें कोई ग़म नहीं है, क्योंकि वह ख़ुद ही यह स्वीकार करती हैं कि उनके पैसे से उनका घर नहीं चलता और यही वजह है कि वह बिना किसी तरह की टेंशन लिए अपने शौक़ और दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगा सकती हैं. उन्होंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस पाने में पूरी मेहनत की है. इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और टेस्ट भी दिए. वैसे केवल शौक़ पर ही नहीं, इन दिनों वह अपनी फिगर पर भी काफ़ी ध्यान दे रही हैं. इसका ख़ुलासा तब हुआ, जब उन्होंने नेटवर्किंग साइट पर अपनी वैसी फोटो पोस्ट की, जो उन्होंने वर्क आउट के बाद खिंचवाई है. यह फोटो काफ़ी सेंशुअल और हॉट है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ लोगों ने इसे साइट से हटाने का अनुरोध किया. मगर उन्होंने इस बात का करारा जवाब दिया. मगर फैंस के मन में सवाल तो उठ ही चुका है कि क्या फिटनेस फ्रीक बन चुकी गुल पनाग आने वाले दिनों में बिपाशा बसु और शिल्पा शेट्टी की तरह एक फिटनेस वीडियो सीडी निकालेंगी और फिटनेस का यह संदेश देशभर में बांटेंगी. ■

फिल्म प्रीव्यू

राउडी राठौर

प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही फिल्म राउडी राठौर का लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है. राउडी राठौर से अक्षय कुमार एक बार फिर से एक्शन हीरो के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं. पिछले 12 वर्षों में अक्षय कुमार ने एक भी एक्शन फिल्म नहीं की है. उनकी आख़िरी एक्शन फिल्म खिलाड़ी 420 थी. अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म में लीड रोल किए हैं. फिल्म राउडी राठौर में ख़तरनाक स्टंट करने से पहले अक्षय कुमार को पचास करोड़ का इंश्योरेंस कवर दिया गया है. इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस के मामले में अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे महंगे सेलिब्रिटी बन गए हैं. प्रभु देवा का यह आइडिया था कि राउडी राठौर के ख़तरनाक स्टंट से पहले अक्षय को अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है. बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर में करीना कपूर भी नज़र आएंगी. उन्होंने इस फिल्म के लिए गेस्ट रोल करना स्वीकार कर लिया है और वह भी फ्री में. इस फिल्म के निर्देशक प्रभु देवा हैं, यानी करीना प्रभु के इशारों पर थिरकती हुई दिखाई देंगी. करीना ने इसके लिए कुछ सीन और एक गाना शूट किया है. इस फिल्म में करीना गेस्ट रोल में आएंगी, लेकिन इसमें भी उनका अवतार काफ़ी ग्लैमरस होगा. राउडी राठौर के लिए काम कर करीना ने फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली से दोस्ती निभाई है. करीना के साथ ही फिल्म एजेंट विनोद से बॉलीवुड में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली ईरानी सुंदरी मरियम ज़कारिया भी फिल्म राउडी राठौर में आइटम गीत कर रही हैं. जासूसी कहानी पर आधारित एजेंट विनोद में मरियम, करीना कपूर के साथ मुजरा गीत दिल मेरा मुफ्त का में नज़र आई थीं. इस गीत में वह भारतीय वेशभूषा में नज़र आएंगी. राउडी राठौर फिल्म तेलुगु फिल्म विक्रमाराकुडु की रीमेक है. ■

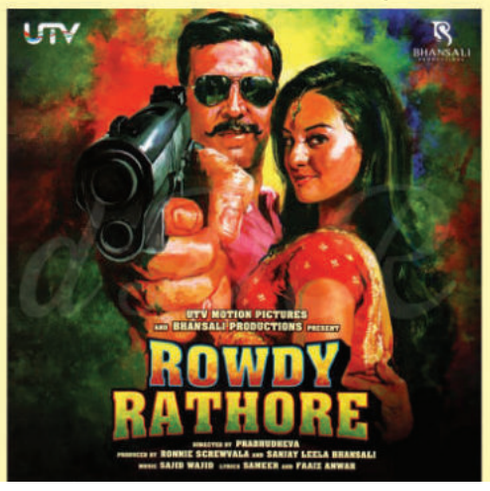

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 मई–03 जून 2012

www.chauthiduniya.com

सिंचाई अनुशेष के बहाने

राज्यपाल पर निशाना

राजेश नामदेव

feedback@chauthiduniya.com

सिंचाई अनुशेष की नीति से राज्य की एकता को ख़तरा है. क्या वाक़ई राज्य की एकता को ख़तरा सरकार की नीति से पैदा हो गया है? यह बेहद अहम सवाल है. सिंचाई अनुशेष की नीति राज्य के उन पिछड़े क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी, जहां सिंचाई के साधनों की कमी है. यह नीति बनाने का मुख्य मक़सद राज्य का संतुलित विकास करना था. हालांकि अब इस नीति को बनाने वाले ही इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि उन्हें आज ही क्यों ख्याल आया कि इस नीति से राज्य की एकता को ख़तरा है? पहले यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया? विदर्भ-मराठवाड़ा अपने हक़ की निधि पश्चिम महाराष्ट्र को देने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए एकता को ख़तरा पैदा हो गया. जब विदर्भ-मराठवाड़ा के विकास के लिए आवंटित निधि बार-बार पश्चिम महाराष्ट्र स्थानांतरित की गई तब कोई ख़तरा नहीं था. क्या शरद पवार ने कभी यह सोचने की ज़हमत उठाई है कि विदर्भ-मराठवाड़ा विकास की दौड़ में पीछे क्यों रह गया? वह राज्य के मुखिया एक बार नहीं, बल्कि कई बार रह चुके हैं और मुख्यमंत्री रहने के दौरान विदर्भ-मराठवाड़ा एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के विषय में उन्होंने क्या किया? यदि वह पूरे राज्य का संतुलित विकास करने के अपने दायित्व का निर्वाह करते तो, उन्हें यह कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि सिंचाई अनुशेष की नीति से राज्य की एकता को ख़तरा है. उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि विदर्भ की उत्पादित बिजली के दम पर ही पश्चिम महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, जबकि दूसरी ओर विदर्भ की जनता को लोडशेडिंग की मार झेलनी पड़ती है. यदि विदर्भ की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना गोसीखुर्द पश्चिम महाराष्ट्र में होती तो क्या वह उसे 25 साल तक निर्माणाधीन रखते? शायद यह परियोजना अगर उनके इलाक़े में होती तो वह वर्षों पहले बन चुकी होती, क्योंकि विदर्भ की सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि हमेशा ही पश्चिम महाराष्ट्र ले जाई जाती रही है.

अब सवाल यह उठता है कि शरद पवार ने यह बयान क्यों दिया? उनके जैसे वरिष्ठ राजनेता से इस तरह के बयान की अपेक्षा किसी को नहीं थी. हालांकि इस बयान के पीछे शरद पवार की सोची-समझी रणनीति की झलक मिलती है. चूंकि इस बार भी विदर्भ-मराठवाड़ा का अनुशेष दूर करने के लिए जो विशेष निधि आवंटित की गई है, उसे पश्चिम महाराष्ट्र में सूखे का हवाला देकर ले जाने की तैयारी कर ली गई थी. इस बार विदर्भ-मराठवाड़ा के जनप्रतिनिधियों ने थोड़ी सजगता दिखाई और राज्यपाल के. शंकरनारायणन से मिलकर अनुशेष निधि की रक्षा करने की गुहार लगाई. इस मसले पर राज्यपाल ने सख़्त रुख़ अपनाते हुए सरकार को हिदायत दी कि विदर्भ-मराठवाड़ा का अनुशेष दूर करने के लिए आवंटित निधि किसी भी स्थिति में पश्चिम महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी. राज्यपाल के इस हस्तक्षेप से पश्चिम महाराष्ट्र के नेता तिलमिला गए. राज्यपाल के इस कड़े रुख़ के कारण ही शरद पवार ने अनुशेष भरने की नीति को राज्य की एकता के लिए ख़तरा क़रार दिया. बात साफ़ है कि जब तक विदर्भ-मराठवाड़ा की अनुशेष निधि पश्चिम महाराष्ट्र ले जाने पर राज्यपाल ने कोई रोक-टोक नहीं की, तब तक इस पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस पर सख्त एतराज़ जताया गया तो वह नीति ही बेकार नज़र आने लगी. यह साफ़-सुथरी राजनीति नहीं, बल्कि राज्यपाल को निशाना बनाने की शरद पवार की कूटनीति है. अब तो काका के साथ उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है और वैधानिक विकास मंडलों को गठित करने को ग़लती बता रहे हैं. इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पश्चिम महाराष्ट्र का सूखा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन विदर्भ का नहीं.

राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों की आपसी लड़ाई में शरद पवार एवं अजीत पवार शायद यह भूल गए हैं कि पिछड़े इलाक़ों से विकास का जो असंतुलन बढ़ा था, उसे दूर करने के लिए संविधान प्रदत्त प्रावधानों के आधार पर वैधानिक विकास मंडलों का गठन किया गया था. इसके गठन में उनकी भूमिका भी रही है. वैधानिक विकास मंडल का गठन कर संविधान के अनुच्छेद 371(2) के तहत पिछड़े इलाक़ों का अनुशेष दूर कराने का अधिकार राज्यपाल को सौंपा गया है, जिसका वर्तमान राज्यपाल के. शंकरनारायणन सख्ती से पालन कर रहे हैं. यही बात राकांपा नेताओं को खटक रही है. इसलिए शरद पवार बार-बार राज्यपाल को निशाना बना रहे हैं. ख़ास बात यह है कि सूखे की समस्या को लेकर कांग्रेस और राकांपा के बीच तक़रार पहले से चली आ रही है. हालांकि राज्यपाल ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार सूखे से निपटने के लिए पश्चिम महाराष्ट्र को चाहे जितनी अतिरिक्त निधि आवंटित करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद भी शरद पवार कांग्रेस नेताओं के साथ ही राज्यपाल पर निरंतर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं. यही वजह है कि पवार लगातार कह रहे हैं कि राज्यपाल सूखे की समस्या को लेकर गंभीर नहीं हैं. राज्यपाल ने सूखाग्रस्त इलाक़ों का दौरा नहीं किया है. इसलिए उन्हें समस्या की गंभीरता का पता नहीं है. पवार के आक्रामक हमलों के बाद भी राज्यपाल ने अब तक कोई प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं समझा है. राज्यपाल पूरी तरह संवैधानिक पद की मर्यादा और राज शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं. राकांपा नेताओं द्वारा की जा रही आलोचनाओं के बाद भी वह अपने रवैये पर क़ायम हैं और विदर्भ-मराठवाड़ा के अनुशेष की रक़म कहीं और ले जाए जाने की अनुमति देने को तैयार नहीं हैं. हालांकि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब वैधानिक विकास मंडलों का गठन किया गया था, उस समय इसके गठन को लेकर शंकरराव चव्हाण ने विरोध किया था और शरद पवार ने इसका समर्थन किया था. इससे यह सवाल उठता है कि तब और अब में क्या स्थितियां बदल गई हैं कि पवार को वैधानिक विकास मंडल और अनुशेष की नीति राज्य के अहित में नज़र आने लगी है. दूसरी बात यह है कि सिंचाई निर्देशांक समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यपाल पिछड़े क्षेत्रों का अनुशेष भरने के लिए हर साल राज्य सरकार को आदेश देते हैं. इसमें कुछ नया नहीं है. इसलिए पवार की लगातार राज्यपाल पर की जा रही बयानबाज़ी उचित नहीं है.

नया यह है कि इस बीच केंद्र सरकार ने के. शंकरनारायणन को दोबारा राज्य का राज्यपाल बना दिया है. इससे राकांपा नेताओं को लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर शंकरनारायणन को राज्यपाल बनाया है. पवार का यह भी कहना है कि शंकरनारायणन को दोबारा राज्यपाल बनाए जाने से पहले उनसे नहीं पूछा गया. शायद इसलिए वह राज्यपाल को निशाने पर रखकर कूटनीति का खेल, खेल रहे हैं. शरद पवार और अजीत पवार को यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि राज्यपाल ने कभी भी कृष्णा खोरे या पश्चिम महाराष्ट्र को बढ़ाकर दी गई निधि का विरोध नहीं किया है.

नया यह है कि इस बीच केंद्र सरकार ने के. शंकरनारायणन को दोबारा राज्य का राज्यपाल बना दिया है. इससे राकांपा नेताओं को लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर शंकरनारायणन को राज्यपाल बनाया है. पवार का यह भी कहना है कि शंकरनारायणन को दोबारा राज्यपाल बनाए जाने से पहले उनसे नहीं पूछा गया. शायद इसलिए वह राज्यपाल को निशाने पर रखकर कूटनीति का खेल, खेल रहे हैं. शरद पवार और अजीत पवार को यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि राज्यपाल ने कभी भी कृष्णा खोरे या पश्चिम महाराष्ट्र को बढ़ाकर दी गई निधि का विरोध नहीं किया है. इस बार भी लगभग 2600 करोड़ रुपये की निधि पश्चिम महाराष्ट्र को मिली है. इस पर किसी तरह की आपत्ति किसी को नहीं है. उसके बाद भी राकांपा नेताओं का राज्यपाल के प्रति आक्रामक होना उचित नहीं हैं, क्योंकि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं. मगर लगता है कि राकांपा के नेता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा सिंचाई परियोजनाओं पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा करने के बाद बौखला गए हैं और उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार भूल कर राज्यपाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. इसलिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सुधीर मुनगंटीवार की इस बात पर दम है कि ज़िंदगी भर मंत्री पद का उपभोग करने के बाद शरद पवार राज्यपाल पर टिप्पणी करने की बजाय महाराष्ट्र की सिंचाई क्षमता बढ़ाने में असफलता क्यों मिली, इस पर विचार करें. राकांपा नेताओं द्वारा अपनी नाकामी छुपाने के लिए राज्यपाल को निशाना बनाया जा रहा है. भाजपा ने सिंचाई परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार को मद्देनज़र रखते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग कई बार की है. यह देखकर राकांपा नेता बौखला गए हैं, क्योंकि श्वेत पत्र जारी हुआ तो राकांपा नेताओं की कार्य क्षमता सबके सामने आ जाएगी. इसलिए जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी मुख्यमंत्री तो कभी राज्यपाल को निशाना बनाया जा रहा है.

सत्ता के शीर्ष पर इस राजनीतिक बयानबाज़ी से क्या राज्य में सूखे की समस्या से जनता को राहत मिलेगी? नेताओं को राजनीति करने से किसने रोका है, लेकिन विदर्भ-मराठवाड़ा का अहित करके पश्चिम महाराष्ट्र का हित साधना कहां की नीति है? राकांपा नेताओं के नज़रिए से तो यही आभास होता है कि वह किसी भी दशा में विदर्भ-मराठवाड़ा का विकास होने ही नहीं देना चाहते हैं. उनके लिए पश्चिम महाराष्ट्र की समस्या, समस्या नज़र आती है, लेकिन विदर्भ-मराठवाड़ा उनके लिए दोयम हैं. यही कारण है कि विदर्भ आज भी पिछड़ा हुआ है. यहां कुपोषण की समस्या है. सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर उन्हें विदर्भ का सूखा नज़र नहीं आता है. उनकी इसी उदासीनता और एकतरफ़ा विकास नीति के कारण विदर्भ का अनुशेष हर क्षेत्र में बढ़ता ही गया है. अब जब राज्यपाल इस मसले को गंभीरता से लेते हुए सख्ती बरत रहे हैं तो उन्हें वैधानिक विकास मंडल और अनुशेष की नीति ही ग़लत नज़र आ रही है. यहां राकांपा मुखिया शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार राजनीतिक तंगदिली का परिचय दे रहे हैं. ■

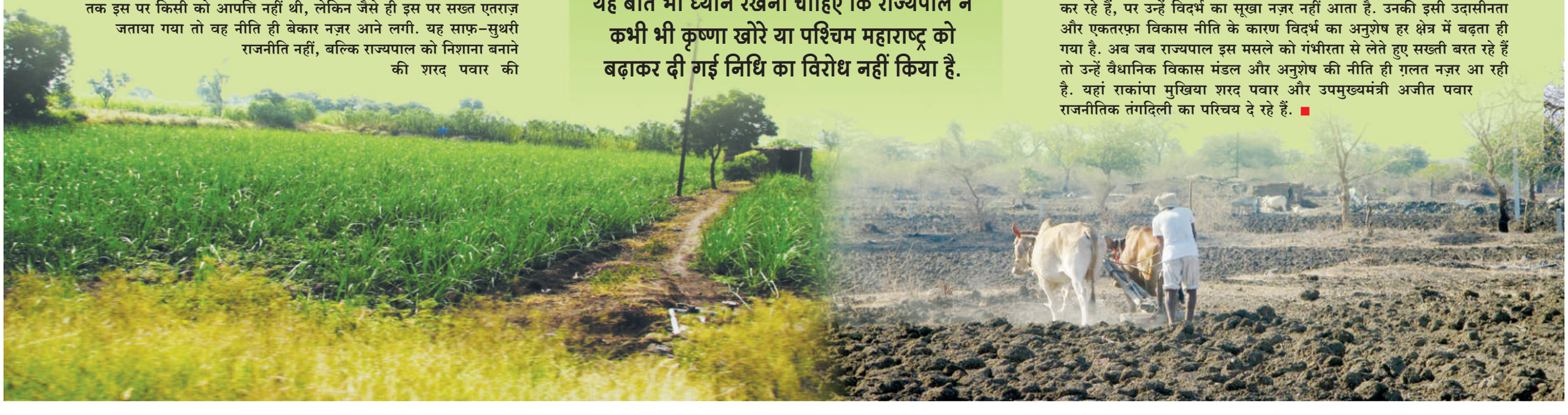

चौथी दुनिया

आमिर ख़ान ने अपने लाइव शो सत्यमेव जयते में कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा उठाकर पूरे देश में इसे चर्चा का विषय बना दिया है.

योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार की आपूर्ति करने का कार्य निजी सामाजिक संगठन (एनजीओ) के हवाले किया गया है, जिसका वितरण आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है.

चौथी दुनिया

महाराष्ट्र हलचल

छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर अकोला में निकाली गई शोभायात्रा का विहंगम दृश्य.

बुलढाना ज़िले में आयोजित भीमशक्ति संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्य अतिथि.

वाशिम में यशवंतराव महाराष्ट्र में यशवंतराव दिल्ली में विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते वरिष्ठ पत्रकार मधुकर भावे एवं मंचासीन अन्य अतिथिगण.

यवतमाल में आचार्य रत्नसुंदरसुरीश्वर महाराज के प्रवचन के शुभारंभ पर दीप प्रज्वलित करते सांसद विजय दर्डा, मंत्री शिवाजीराव मोघे, मनोहर नाइक, विधायक नीलेश पारवेकर, जिप अध्यक्ष प्रवीण देशमुख.

आदिवासी विकास विभाग की ओर से वनामति में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में आयुक्त संभाजी सरकुंडे, अपर आयुक्त पल्लवी दराडे एवं अन्य.

सिंचाई परियोजना में गई अपनी ज़मीन को वापस करने की मांग को लेकर मोर्चा निकालते भंडारा ज़िले के सालबर्डी के पीड़ित ग्रामवासी.

चंद्रपुर में आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर में योगासन का प्रदर्शन करते बच्चे.

नागपुर महानगर पालिका की प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल नवनिर्वाचित नगरसेवक-नगरसेविका.

सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सचिव धनंजय धवड़ का सत्कार करते हुए अमरावती विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीव गणवीर एवं अन्य.

पौष्टिक आहार में भारी अनियमितता

राज्य में कुपोषण एक गंभीर समस्या है. इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कुपोषण की समस्या का जितना ज़िक्र किया जाता है, वहीं उसके उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के प्रति सरकारी उदासीनता देखी जाती है. यही वजह है कि जहां कुपोषण की समस्या है, वहां पौष्टिक आहार समय पर नहीं पहुंचता है और जहां कुपोषण की समस्या नहीं है, वहां पौष्टिक आहार पहुंचता है. ऐसी सूरत में यह आहार जानवरों को खिलाया जाता है. इस तरह की घटनाएं पिछले दिनों राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली हैं. इस बात की पुष्टि एकेडमी ऑफ न्यूट्रीशन इंप्रूवमेंट के सर्वे में भी हुई है. इससे यह तथ्य सामने आया है कि सरकारी स्तर पर कुपोषण से लड़ने की नीति से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, जबकि इस समस्या से निपटने के लिए शासन-प्रशासन को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए.

दरअसल, राज्य के कई क्षेत्रों में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की संख्या हज़ारों में है. इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान योजना चला रखी है. योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार की आपूर्ति करने का कार्य निजी सामाजिक संगठन (एनजीओ) के हवाले किया गया है, जिसका वितरण आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है. इस योजना के तहत पौष्टिक आहार वितरण में भारी अनियमितता होने की शिकायतें मिलती रहती हैं. अब यह भी ख़ुलासा हुआ है कि कुपोषितों के लिए जो पौष्टिक आहार वितरित किया जा रहा है, वह जानवरों को परोसा जा रहा है, क्योंकि एक तो वह निम्न स्तर का होता है, दूसरा वह इंसानों के खाने योग्य नहीं होता है. हाल में कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान में हो रही गड़बड़ियों का पता लगाने हेतु एकेडमी ऑफ न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट के संस्थापक डॉ. शांतिलाल कोठारी के नेतृत्व में युवा वैज्ञानिक सविता गाढ़वे एवं आरती देशमुख ने नागपुर ज़िले की कलमेश्वर, कामठी, कुही, नागपुर तहसील सहित अन्य जगहों का दौरा कर सर्वे किया तो पता चला कि कुपोषण मुक्त ग्राम बनाने के नाम पर छह-सात माह पहले शुरू की गई योजना का किस तरह बंटाधार हो रहा है. मज़े की बात यह रही कि राज्य के शासन-प्रशासन ने ज़िले के जिन गांवों को कुपोषण ग्रस्त घोषित किया था, उनमें से अधिकतर गांवों में एक भी कुपोषित बच्चा नहीं मिला. इसके बावजूद लाखों रुपये के पौष्टिक आहार की आपूर्ति इन गांवों में की जा रही है, जहां इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. डॉ. कोठारी और उनके सहयोगियों का कहना है कि कलमेश्वर तहसील के हरदोली, खानगांव, झिल्पी गांव में एक भी कुपोषित बच्चा नहीं मिला. उसी तरह नागपुर तहसील के कोढाला, परसोडी-गोखले, जयपुर पठार, टेंभरी आलागोंदी एवं मंगली गांव तो कामठी तहसील के नान्हा एवं मांगली गांव और कुही तहसील के सावरगांव, सावरखेड़ा, चिकलीबोडी, कोटी, पिपरी, मोलादा ऐसे गांव है, जहां एक भी कुपोषित बच्चा दिखाई नहीं दिया. उसके बाद भी इन गांवों को कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान के तहत पौष्टिक आहार की निरंतर आपूर्ति की जा रही है. किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास इतना

वक़्त नहीं है कि वह इस बात का पता लगाए कि लाखों रुपये का जो पौष्टिक आहार इन गांवों को भेजा जा रहा है, वह जाता कहां है? ख़ास बात यह है कि जिन गांवों में कुपोषित बच्चे नहीं पाए गए हैं, वहां पौष्टिक आहार के वितरण पर रोक लगाई गई है. रोक लगाने के बाद भी आहार की आपूर्ति किया जाना कई सवाल खड़े करता है. इस संबंध में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि यहां आने वाले पौष्टिक आहार का वितरण बच्चों में नहीं किया जाता है, क्योंकि कुपोषित बच्चे नहीं हैं. साथ ही कुपोषित बच्चों के न होने पर पौष्टिक आहार का वितरण न करने का आदेश दिया गया है. डॉ. कोठारी ने दावा किया कि इन परिस्थितियों में उक्त गांवों को आपूर्ति किया जाने वाला पौष्टिक आहार जानवरों को परोसा जा रहा है. इससे पता चलता है कि राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान के क्रियान्वयन में किस तरह गड़बड़ी हो रही है. इससे कुपोषण जैसी गंभीर समस्या पर शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता साफ़ झलकती है, यानी राज्य में कुपोषण की समस्या गंभीर है, लेकिन शासन-प्रशासन ज़रा भी गंभीर नहीं है और करोड़ों रुपये पानी की तरह योजना के तहत बहाए जा रहे हैं. डॉ. कोठारी ने कुपोषण मुक्त ग्राम योजना में भ्रष्टाचार होने का दावा करते हुए सरकार से मामले की जांच स्वतंत्र रूप से कराने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई को राज्य सरकार ने जिन गांवों को कुपोषण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया है, उन गांवों का किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच या सर्वे न कराने के तथ्य भी सामने आए हैं. इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव से भी संपर्क किया है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है. इसका अर्थ यह हुआ कि राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम योजना स्वार्थी तत्वों को फ़ायदा पहुंचाने वाली योजना बनकर रह गई. वहीं मेलघाट जैसे कुपोषणग्रस्त क्षेत्रों में पौष्टिक आहार कुपोषितों को नहीं मिल पा रहा है. ऐसा लगता है कि शासन ने उक्त योजना कुपोषितों के लिए नहीं, बल्कि कुछ एनजीओ को पालने के लिए चला रखी है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

न्यूनतम पेंशन ख़्याली पुलाव है

सरकार का समय से तालमेल न होने के कारण कई नीतियां मज़ाक़ बनकर रह गई हैं. शासन-प्रशासन में बैठे लोग समय के अनुसार क़ानून में बदलाव करने में इतना आलस क्यों करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है. इस कमज़ोरी के कारण देश में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं. ऐसी नीतियों में शुमार है सरकार की पेंशन नीति. आज भी हज़ारों लोगों को 40-50 या 100 रुपये की पेंशन मिलती है और इतनी कम पेंशन पर वे अपना गुज़र-बसर करने को मजबूर हैं. हालांकि सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया और उसकी चर्चा भी हुई, जिससे 40-50-100 रुपये की पेंशन पर गुज़ारा करने वालों की उम्मीद जागी कि सरकार उनकी भी सुध ले रही है. उन्हें आस थी कि न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव पर सरकार अमल कर पेंशन नीति में सुधार करेगी और उनकी भी ज़िंदगी में कुछ सुधार आएगा. हालांकि जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए न्यूनतम पेंशन एक ख़्याली पुलाव बन कर रह गया है. सरकार ने न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

ग़ौरतलब है कि कारख़ानों, कार्यालयों एवं अन्य जगहों पर नौकरी करने वालों के वेतन से एक निश्चित रक़म काट कर भविष्य निर्वाह निधि संगठन (ईपीएफओ) के खाते में जमा की जाती है. जितनी रक़म कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है, उतनी ही रक़म नियोक्ता द्वारा उसके भविष्य निर्वाह निधि के खाते जमा की जाती है. सेवानिवृत्त होने पर इस रक़म से उस व्यक्ति को अपने गुज़ारे के लिए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, लेकिन आज के ज़माने में 40-50 या 100 रुपये की पेंशन से किसी व्यक्ति का गुज़ारा हो सकता है? यही तो विडंबना है कि आज भी लाखों पेंशनभोगी को 40-50 एवं 100 रुपये की पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सरकार अपनी पेंशन नीति में समय के अनुसार बदलाव करने को तत्पर नहीं दिखाई दे रही है. ऐसे पेंशन भोगियों की संख्या नागपुर विभाग में आने वाले नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली ज़िले में एक लाख से ऊपर है. पूरे राज्य में ऐसे पेंशनभोगियों की संख्या कितनी हो सकती है, इसका अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है. ध्यान रहे कि पूर्व विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरोली ज़िलों में एक समय बीड़ी कारख़ाने बड़ी तादाद में हुआ करते थे और उनमें हज़ारों की संख्या में मज़दूर बीड़ी बनाने और तेंदूपत्ता तोड़ने का काम किया करते थे. उनकी वेतन उस समय 300 से 400 रुपये तक होता था, जिससे भविष्य निर्वाह निधि की रक़म भी बहुत ही कम हुआ करती थी. योगदान बहुत कम होने से आज उनका जीवन नरक जैसा बन गया है. ऐसे कर्मचारियों एवं मज़दूरों की संख्या लाखों में है, जिन्हें मात्र 40 से 100 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं. उनका दोष सिर्फ़ इतना है कि वेतन के आधार पर उनका अंशदान वर्तमान समय के मुक़ाबले बहुत कम था, जिसके आधार पर आज उन्हें नाममात्र पेंशन मिल रही है. इसके लिए उन्हें महीनों इंतज़ार करना पड़ता है और कतार में घंटों खड़ा रहना पड़ता है.

ऐसा भी नहीं है कि इस बात की ख़बर पेंशन नीति बनाने वालों को नहीं है. उनके सामने जब भी यह बात रखी जाती है कि 40 से 100 रुपये में आज एक दिन का गुज़ारा हो पाना संभव नहीं है तो इतनी कम पेंशन पाने वालों को विशेष योजना के तहत जीवन के गुज़ारे लायक़ पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तब सरकार और हमारे नीति निर्धारक नियमों का हवाला देते हुए कहते हैं कि योगदान के आधार पर पेंशन बनती है. सरकार के साथ ही विविध श्रमिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां भी इस तथ्य को मानती हैं और समझती हैं. इसलिए तो पिछले दो साल से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये करने की मांग पिछले दो वर्षों से विविध मंचों से की गई, लेकिन बात नहीं बनी. सरकार भी 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की बात को सैद्धांतिक रूप से मानती है. इस बाबत एक प्रस्ताव भी सरकार ने तैयार किया था, लेकिन इस पर पता नहीं क्यों अब तक विचार नहीं किया गया? हालांकि इस मसले पर कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. हालांकि यह प्रस्ताव ख़्याली पुलाव बनकर रह गया है. सरकार द्वारा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. जो राजनीतिक दल इस मसले पर आवाज़ उठा रहे थे, वे भी उक्त प्रस्ताव संसद में लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं. शायद वे इस मसले को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत भी नहीं समझी, क्योंकि उन्हें इस मामले में सियासी फ़ायदा ज़्यादा और पीड़ितों का दर्द कम नज़र आता है. इस स्थिति में 40 से 100 रुपये की पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की हालत में कोई सुधार होने के आसार नज़र नहीं आते हैं. इससे उनमें निराशा व्याप्त है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बर

नक़ली क्रेडिट-डेबिट बनाने वाला गैंग का पर्दाफ़ाश

सावधान हो जाइये, क्योंकि अब नक़ली क्रेडिट-डेबिट कार्ड बनाने वाला गिरोह पूरे राज्य में सक्रिय है. मुंबई पुलिस ने नक़ली क्रेडिट-डेबिट कार्ड बनाने वाले गैंग के दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. इस गिरोह का सरगना फ़रार बताया गया है. इस गिरोह का जाल महाराष्ट्र सहित गुजरात, राजस्थान तक फैला है और अब तक उसने नक़ली क्रेडिट-डेबिट कार्ड के दम पर लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा चुका है. पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस गिरोह से जुड़े 42 मामलों का पता चला है. इसका सरगना नाइजीरिया में बैठे एक सदस्य के मार्फ़त नक़ली डेबिट-क्रेडिट कार्ड बनाने का कारोबार करता है. कस्तूरबा मार्ग पुलिस के अनुसार, इस गिरोह के दो सदस्य श्रवण सिंह स्वरूप सिंह राव और देवानंद मारुति कोकणे को गिरफ्त में लिया गया है और उनके पास से 2 लाख 34 हज़ार रुपये का माल ज़ब्त किया है. इस गिरोह का पर्दाफ़ाश तब हुआ, जब बोरीवली पूर्व में मैट्रो कैश एंड कैरी मॉल से नक़ली क्रेडिट कार्ड से लाखों की ख़रीद का मामला पुलिस के पास पहुंचा. जांच में यह भी पता चला है कि इस गिरोह का सरगना हुकुम सिंह करोड़पति है. राजस्थान में उसकी एक आइसक्रीम फैक्ट्री है. स्थानीय मीरा रोड पर उसके नाम 10 करोड़ रुपये की प्रापर्टी है. इसके अलावा उसके पास चार कारें भी हैं. उसके द्वारा बनाए गए नक़ली कार्डों की विशेषता यह है कि उसे किसी का कार्ड चुराना नहीं पड़ता है, बल्कि स्टीमर नामक तकनीक का उपयोग करने से किसी असली क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पास ले जाने पर वह उसके मैग्नेटिक स्ट्रिप को कॉपी कर लेता है और उसी नंबर पर नकली कार्ड बनाकर उपयोग किया जाता है.

घरकुल की 48 फाइलें ग़ायब

यवतमाल पंचायत समिति के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना के तहत दिए गए घरकुलों में हुई गड़बड़ी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पंचायत समिति से इंदिरा आवास योजना से संबंधित 70 फाइलों में से 48 फाइलों के लापता होने का ख़ुलासा तब हुआ, जब जांच समिति के बार-बार मांगने पर भी उक्त फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गईं. जांच समिति के सदस्यों ने जब भी उक्त फाइलों को देखने के लिए मांगा तो उसे टाल दिया गया. दरअसल इंदिरा आवास आवंटन मामले में यहां 70 लाख रुपये का गोलमाल हुआ है. इन 70 लाख रुपये का बंदरबांट किस तरह और किसने की, इसका पता लगाने के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन ज़िला ग्राम विकास विभाग द्वारा किया गया है. इस मामले पर अब तक ग्रामसेवक आरएस दुधे, वाईडब्ल्यू काले, पं.स. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) टी.एम. महाजन, शाखा अभियंता एसयू शिंदे, एसबी वाठोड को निलंबित किया जा चुका है. निलंबित एक अधिकारी को बहाल भी करने की ख़बर है. इसके अलावा बनावटी कागज़-पत्रों के आधार पर घरकुल का लाभ लेने वाले 28 लोगों के ख़िलाफ़ वडगांव थाने में फौज़दारी का मामला भी दर्ज कराया गया है. जांच में और भी अधिकारियों के नाम आने की आशंका है, जिन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है.

कृपाशंकर सिंह पर मामला दर्ज

मुंबई शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले ही उन पर आय से अधिक संपत्ति जोड़ने के लिए चर्चा में रहे कृपाशंकर सिंह पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने कालाधन रखने का मामला दर्ज किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति जोड़ने की जांच करने के सिलसिले में की है. इस जांच के दायरे में उनके परिवार के सदस्य भी हैं. उनके ख़िलाफ़ यह कार्रवाई करने का निर्देश दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय से दिया गया था. वैसे भी जबसे कृपाशंकर सिंह पर राजकीय कृपा होना बंद हुई है, तब से वे महाराष्ट्र सरकार की प्रर्वतन एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं. राज्य सरकार ने भी आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एक जांच रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया है. वहीं केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय सिंह के लेन-देन और बेहिसाब संपत्ति ख़रीदी मामलों की जांच भी करेगा. लिहाज़ा कृपाशंकर सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों को कहीं से राहत मिलने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है. साथ ही अब उनके पार्टी के हितचिंतक भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कभी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे.

शिकारी का पता बताओ और इनाम पाओ

सरकार वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अब तक जितने भी उपाय किए, वे सभी बेकार साबित हुए हैं. जंगलों में शिकारी वन्यजीवों का शिकार कर रहे हैं. यह बात पिछले दिनों चंद्रपुर के जंगलों में एक बाघ के मृत पाए जाने और दूसरे की शिकारी द्वारा लगाए गए यंत्र में फंसने से ज़ाहिर हो जाती है. वन विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी के अनुसार, राज्य सरकार ने वन्यजीवों, ख़ासकर बाघों का शिकार रोकने के लिए सीक्रेट फंड योजना बनाई है. इस योजना के तहत अवैध शिकार करने या शिकार करने की योजना बनाने वालों के संबंध में सूचित करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा. इससे शिकार करने वालों पर अंकुश लगाया जा सकेगा. इसलिए सरकार ने शिकारी का पता बताओ और इनाम पाओ योजना शुरू की है. इसके अलावा मानव एवं जानवरों के बीच टकराव को टालने के लिए सरकार जंगल के आसपास के गांवों को पुनर्स्थापित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके तहत नवेगांव और ताड़ोबा के कुछ गांवों को भी हटाया जाएगा. इतना ही नहीं सरकार ने पर्यावरण संवर्धन और जंगलों के विस्तार के लिए पूरे राज्य में 8 करोड़ पौधे लगाने की योजना पर अमल करने का निर्णय लिया है. अब देखना यह होगा कि सरकार को इस योजना से वन्यजीवों एवं वन संवर्धन में कितनी कामयाबी मिलती है.

राज्य में सूखे का रहस्य

राज्य में सूखे को लेकर राजनीति जारी है. ऐसे में पश्चिम महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने से जलापूर्ति मंत्री लक्ष्मण ढोबले ने रहस्य हटाया और बताया कि वहां पड़े सूखे की मुख्य वजह बड़ी मात्रा में गन्ने की फ़सल का होना है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि पश्चिम महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का स्थायी समाधान खोजना है तो सबसे पहले वहां अधिक पानी लगने वाली फ़सलों को लगाने में कमी लानी होगी. ग़ौरतलब है कि 15 ज़िलों में सूखे की स्थिति भयावह है और वहां स्थायी समाधान करने की ज़रूरत है. भू-जल के स्रोत सूख जाने से वहां के हैंडपंप भी बंद पड़ गए हैं. इतना ही नहीं वहां टैकरों से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन टैंकर भी कम पड़ रहे हैं. अब तो यह हालत यह है कि पड़ोसी राज्यों से टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं. हैदराबाद तक से पानी के टैंकर लाए गए हैं. ऐसे में ढोबले की बातों में दम है, लेकिन राज्य के अन्य नेता उनकी बातों को सुन रहें हैं क्या?

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सूखा राहत में भी सियासी दांवपेंच

राज्य के 15 ज़िलों में सूखे की समस्या से निपटने में भी जमकर राजनीति हो रही है. जिन सूखाग्रस्त ज़िलों में राहत राशि जारी की गई है, वहां के चारा-पानी ठेकेदारों, पानी टैंकर माफ़ियाओं के साथ ही स्थानीय छुटभैये नेताओं द्वारा चांदी काटने की बात आम बात हो गई है. वहीं राज्य का ऊर्जा विभाग भी इस लूट में पीछे नहीं है. वह भी सूखा राहत की बहती गंगा में डुबकी लगा रहा है और जमकर राहत राशि का गबन कर रहा है. ख़ास बात यह है कि ऊर्जा मंत्रालय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पास है. इसे लेकर सियासी हलक़ों में कहा जा रहा है कि जब राज्य के आला राजनेता ही इस लूट को रोकने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो दूसरे विभाग और लोगों से क्या उम्मीद करें.

दरअसल, यह मामला राज्य की अधूरी पड़ी जल परियोजनाओं से जुड़ा है. राज्य का ऊर्जा विभाग बंद पड़ी जल परियोजनाओं को बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए पुराने बक़ाया बिल भरने पर ज़ोर दे रहा है. वह पुराने बिल का भुगतान न होने की स्थिति में बिजली का री-कनेक्शन देने को तैयार नहीं है. इस तरह उसने सूखा राहत की इस बहती गंगा से अब तक 15 करोड़ रुपये अपनी तिजोरी में जमा कर लिए हैं. ख़ास बात यह है कि इन जल परियोजनाओं के बक़ाया बिजली बिलों का भुगतान उस निधि से करने पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिससे सूखाग्रस्त इलाक़ों में पानी की व्यवस्था की जानी है. ध्यान रहे कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऊर्जा मंत्रालय को बिजली का बिल न भुगतान करने के कारण बंद पड़ी जल परियोजनाओं को अविलंब री-कनेक्शन देने का आदेश दिया था. इस आदेश के तहत ही विभागीय आयुक्तों और ज़िलाधिकारियों को जल परियोजनाओं के बिजली बिल का भुगतान करने का अधिकार भी दिया था. इस पर ऊर्जा विभाग ने ज़िलाधिकारियों को साफ़ शब्दों में कहा कि पहले बक़ाया बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा, तभी जल परियोजनाओं को री-कनेक्शन दिया जाएगा. नतीजतन, जिलाधिकारियों के सामने सूखा राहत से आई निधि से पहले बिजली का बिल भरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है. हालांकि इस मामले पर उच्चस्तरीय निर्णय लिया जाना था, लेकिन बाबा-दादा के बीच की तक़रार की वजह से बात बनी नहीं.

राजनीतिक दांवपेंच के चलते अब तक सूखा राहत निधि से 15 करोड़ रुपये के बिजली बिलों को वसूल करने में ऊर्जा विभाग कामयाब रहा है. भले सूखाग्रस्त इलाक़ों के पीड़ितों को राहत मिले या न मिले, लेकिन ऊर्जा विभाग की इस अडंगेबाज़ी से यह बात तो साफ़ है कि सरकार के अंदर ही सूखा राहत जारी करने की नीति में गहरे मतभेद हैं. ऊर्जा विभाग का दो टूक शब्दों में कहना है कि जल परियोजनाओं को बिजली की आपूर्ति तभी बहाल की जाएगी, जब पुराने बिलों का भुगतान किया जाएगा. इस फ़रमान से उनकी सूखा पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता का पता चलता है. ऊर्जा विभाग को यह तो पता होना लाज़िमी है कि सूखाग्रस्त ज़िलों को सूखा राहत जारी की जा रही है और इस दौरान दबाव बनाकर अपना पैसा वसूला जा सकता है. उसकी वजह यही है कि जिस वित्त मंत्रालय

से सूखा राहत राशि जारी की जा रही है, वह भी अजीत दादा के पास है. बिजली बिल वसूल करने वाले ऊर्जा विभाग की लगाम भी अजीत दादा के हाथ में है. इसका मतलब यह हुआ कि दादा ने एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले का दांव यहां पर चला है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही है कि दादा के इस दांवपेंच से किसका भला होने वाला है?

सूखा राहत को लेकर चल रही राजनीतिक उठा-पटक पर कांग्रेस नेता और राज्य के वन एवं पुनर्वास मंत्री पतंगराव कदम का कहना है कि इस समय सभी को मिलकर संकट में पड़े किसानों की मदद करनी चाहिए न कि ओछी बयानबाज़ी. उन्होंने सूखा राहत पर हो रही राजनीति पर नाख़ुशी ज़ाहिर करते हुए सिंचाई विभाग पर श्वेत पत्र जारी करने के मुख्यमंत्री के फ़ैसले का समर्थन किया और उसे राजनीतिक दृष्टि से न देखने का अनुरोध किया, लेकिन इन बातों से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सूखे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पृथ्वी बाबा और उपमुख्यमंत्री अजीत दादा के बीच तालमेल नहीं है. दोनों के मध्य तक़रार जारी है. इसका ख़ामियाज़ा सूखा पीड़ितों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मतभेद प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देता है. जिन विभागों को एकजुट होकर सूखाग्रस्त इलाक़ों में राहत पहुंचाने के कार्य में जुट जाना चाहिए, वे अलग-अलग राह पर चल रहे हैं. हर विभाग अपने आक़ा के इशारे पर एक-दूसरे के काम में टांग अड़ाने का काम कर रहा है. इसी का नतीजा है ऊर्जा विभाग का अड़ियल रवैया. कम से कम सूखे के मामले में राज्य के कर्ताधर्ताओं को राजनीतिक मतभेद भुलाकर उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जो सूखे से बदहाल होकर उनकी ओर आशाभरी नज़रों से देख रहे हैं. यदि वे अपनी राजनीतिक तक़रार में सूखा पीड़ितों को रामभरोसे छोड़ेंगे तो आगामी दिनों में उसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दो वर्ष बाद ही चुनाव होने वाले हैं.

यह मामला राज्य की अधूरी पड़ी जल परियोजनाओं से जुड़ा है. राज्य का ऊर्जा विभाग बंद पड़ी जल परियोजनाओं को बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए पुराने बक़ाया बिल भरने पर ज़ोर दे रहा है. वह पुराने बिल का भुगतान न होने की स्थिति में बिजली का री-कनेक्शन देने को तैयार नहीं है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

नवजात का सौदा...?

कन्या भ्रूण हत्या पर राज्य में ख़ूब वाद-विवाद, भाषणबाज़ी, लेखनबाज़ी हो रही है. साथ ही लड़कियों की ख़रीद-फ़रोख्त के मामले सामने आते रहते हैं. यहां ये मुद्दे सामान्य बात बन गए हैं. जब कभी सुप्रिया सुले जैसी कोई शख़्सियत शहर में आकर कुछ बतकही कर जाती है तो वह अख़बार की सुर्ख़ियां बन जाती है. मगर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है. यह बहुत ही संवेदनशील मसला है. आमिर ख़ान ने अपने लाइव शो सत्यमेव जयते में कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा उठाकर पूरे देश में इसे चर्चा का विषय बना दिया है. राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सरकारों के बाद हमारी राज्य सरकार की आंखें खुली और उसने आमिर ख़ान को कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान का एम्बेसडर बनने का निमंत्रण दिया. आमिर ने अब तक इसे स्वीकार नहीं किया. अब एक नया मामला सामने आया है वर्धा ज़िले के पुलगांव में दो दिन की बच्ची को बेचे जाने का. अब जिस राज्य में दुधमुंही बच्चियों की ख़रीद-बिक्री में हमारे पढ़े-लिखे डॉक्टर ही भूमिका निभाने लगें तो उस राज्य में कन्या भ्रूण की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. बड़ी-बड़ी बातें और बोल वचन से समस्या का समाधान तो नहीं होता है. ऐसी समस्याओं का समाधान वैचारिक परिवर्तन के बाद ही होता है.

सरकार आधे-अधूरे मन से उन लोगों के प्रति कार्रवाई की जो लिंग परीक्षण का धंधा चला रहे हैं. पुलिस की दबिश बढ़ने पर वे कुछ दिनों के लिए अपना धंधा बंद कर देते हैं और पुन: वही कार्य करने लग जाते हैं, जो समाज एवं क़ानून की दृष्टि में अपराध है. वैसे आजकल जिस काम से कमाई होती हो, उसे अपराध नहीं माना जाता है. पुलगांव की घटना में भी एक नवजात शिशु के सौदा होने की बात सामने आई. इस घटना में एक प्रेम विवाह करने वाली युवती को प्रसव पीड़ा हुई तो वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई. उसने अस्पताल में ही एक बच्ची को जन्म दिया. कहा जाता है कि युवती के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नवजात दुधमुंही बच्ची को डॉक्टर और एक दवा दुकानदार की मदद से पुलगांव के ही एक दंपत्ति को बेच दिया गया. उसके बाद इस बच्ची की तबीयत बिगड़ गई तो उसे ख़रीदने वाला दंपत्ति उपचार के लिए सावंगी मेघे अस्पताल में ले गया. मगर वहां के डॉक्टर ने बच्ची के माता-पिता के विषय में पूछ-परख की तो ख़रीददार दंपत्ति के होश उड़ गए. संदेह होने पर सावंगी मेघे के डॉक्टरों ने इस मामले की शिकायत सेवाग्राम पुलिस थाने में की. इस तरह मामले का ख़ुलासा हुआ. अब इस मामले में भी लीपापोती कर शांत करने का प्रयास किया जा रहा है. मगर इस मामले के ख़ुलासे से एक बात साफ़ हो जाती है कि राज्य के अस्पतालों में क्या चल रहा है. कहीं बच्चा चोरी होने की वारदातें बार-बार सामने आती हैं तो कहीं कन्या भ्रूण कचरे में पड़े मिलते हैं तो कहीं नवजात बच्ची का सौदा होता है. आख़िर राज्य में यह हो क्या रहा है?

क्या चल रहा है? सीधी सी बात है कि जब बहस होती है तो इसमें भाषणबाज़ी बहुत होती है. आदर्शवादी बातें कही जाती हैं. लेकिन कन्या भोज का आयोजन करके उनकी पूजा करने वाले हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या या बच्ची को बेचे जाने की घटना का घटित होना दर्शाता है कि हमारी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. कहने और करने की बात अलग-अलग होती है. कन्या को आज भी बोझ समझने की मानसिकता ही यह सब कराती है. विडंबना यह है कि इस कार्य में घर की महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है. अब ऐसे मामलों में डॉक्टर भी भूमिका निभाने लगे हैं.

राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सरकारों के बाद हमारी राज्य सरकार की आंखें खुलीं और उसने आमिर ख़ान को कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान का एम्बेसडर बनने का निमंत्रण दिया. आमिर ने अब तक इसे स्वीकार नहीं किया. अब एक नया मामला सामने आया है वर्धा ज़िले के पुलगांव में दो दिन की जन्मी नवजात बच्ची को बेचे जाने का.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गेहूं उत्पादन में भारी कमी

आलोक मिश्रा
feedback@chauthiduniya.com

राज्य में सिंचाई सुविधाओं के अभाव में खेती-किसानी का काम घाटे का सौदा साबित हो रहा है. ऊपर से इस बार सूखे की समस्या से भी कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है. इसका असर गेहूं के उत्पादन पर भी पड़ा है. पानी के अभाव में गेहूं उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई है. पिछले तीन साल के आंकड़ों के अनुसार, इस बार राज्य में 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन कम हुआ है. दूसरी ओर देश में इस बार गेहूं का बंपर उत्पादन होने की बात कही जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में तस्वीर बिल्कुल उलट है. यह स्थिति राज्य के लिए चिंताजनक कही जा सकती है. ग़ौरतलब है कि देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और पंजाब में होता है. इन दोनों राज्यों से गेहूं की आपूर्ति अन्य राज्यों में भी की जाती है. मध्य प्रदेश से गेहूं का आयात महाराष्ट्र में किया जाता है. देश में उत्पादित गेहूं का 50 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 35 प्रतिशत पंजाब में उत्पादन होता है. इसके बाद अन्य राज्यों का गेहूं उत्पादन में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी रहती है. इस बार मध्य प्रदेश और पंजाब में गेहूं का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ है. वहां गेहूं की सरकारी ख़रीद शुरू करने के लिए किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गेहूं उत्पादन की स्थिति मध्य प्रदेश और पंजाब के बिल्कुल विपरीत है. यहां इस बार गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आई है. 2009-2010 में गेहूं का उत्पादन जहां 70 लाख 40 हज़ार मीट्रिक टन हुआ था. वहीं 2010-11 में गेहूं का उत्पादन घटकर 23 लाख मीट्रिक टन हो गया था, लेकिन इस ओर सरकार ने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी. इस साल हालत और ख़राब हो गई है. चालू साल में गेहूं का उत्पादन घट कर मात्र 13 लाख मीट्रिक टन रह गया है. इससे यह बात साफ़ हो जाती है कि राज्य में गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आई है, लेकिन प्रदेश सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष गेहूं की फ़सल के लिए राज्य में 13 लाख 7 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई थी, लेकिन इस साल मात्र 8 लाख 43 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में ही गेहूं की फ़सल लगाई गई है. गेहूं की फ़सल लेने के प्रति किसानों में बढ़ती उदासीनता कुछ तो सरकारी नीति के कारण है तो कुछ इस साल पड़े सूखे का असर है. राज्य में गेहूं की सर्वाधिक फ़सल अहमदनगर में होती है. अहमदनगर ज़िले में पिछले साल एक लाख 33 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फ़सल लगाई गई थी, लेकिन इस बार ज़िले में सूखे का प्रकोप साफ़ नज़र आ रहा है, जिसके चलते मात्र 48 हज़ार 100 हेक्टेयर क्षेत्र में ही गेहूं लगाया गया, यानी तक़रीबन दो तिहाई गेहूं बुआई क्षेत्र अमहदनगर में घटा है. हालांकि सरकार द्वारा इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि किए जाने पर किसानों ने थोड़ी राहत महसूस की है, लेकिन खेतों को सिंचाई का पानी न मिलने से उनके चेहरों पर निराशा छाई हुई है. पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1180 रुपये था, जिसे इस बार सरकार ने बढ़ाकर 1285 रुपये कर दिया है. हालांकि सरकार के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि की अपेक्षा गेहूं के उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है. देश में जिस तरह गेहूं का पैदावार बढ़ा है. इस लिहाज़ से राज्य में उत्पादन घटना चिंता का विषय है. किसानों का कहना है कि गेहूं की फ़सल के लिए जितना पानी चाहिए, उतना समय पर मिल नहीं पाता है. यहां सिंचाई के साधन भी सीमित हैं. इसलिए गेहूं के उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक है. वैसे भी सरकार के समर्थन मूल्य से कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ता है, क्योंकि गेहूं की फ़सल लेने में लागत निरंतर बढ़ती जा रही है. बीज और खाद की क़ीमतों में दोगुने से अधिक इजाफ़ा हो गया है. लोकवन और सिहोर क़िस्म के गेहूं की क़ीमत में सरकारी समर्थन मूल्य के घोषित किए जाने पर भी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है. इसलिए उक्त क़िस्म के गेहूं का भाव पिछले वर्ष जितना ही है. निम्न क़िस्म के गेहूं की ख़रीद आटा मिल और केंद्र सरकार द्वारा की जाती है. इसके अलावा कुछ किसानों का रुझान परंपरागत खेती की बजाय व्यावसायिक खेती की तरफ़ भी होने लगा है. इस वजह से भी गेहूं उत्पादन में कमी आने की बात व्यापारी कर रहे हैं.

यह क़ानून व्यवस्था के लिहाज़ से बेहद ख़तरनाक है. जनता में जो असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, उसे कम करना भी सरकार और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

क़ानून हाथ में लेते लोग

राज्य की उपराजधानी नागपुर की कलमना बस्ती में भीड़ ने क़ानून अपने हाथों में लेते हुए तीन पैसा मांगने वाले बहुरूपिया को जिस तरह मौत के घाट उतार दिया, उससे पूरा शासन–प्रशासन कठघरे में खड़ा नज़र आता है. साथ ही राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, इसका पता भी चलता है. अपनी कार्य प्रणाली के कारण पुलिस–प्रशासन किस क़दर जनता का विश्वास खो बैठा है, इस घटना के बाद यह बख़ूबी पता चलता है. पुलिस के प्रति बढ़ता यह अविश्वास ही जनता को क़ानून अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करता है. इस तथ्य की पुष्टि करती है कलमना क्षेत्र में घटित घटना. इस घटना के बाद यह पता चलता है कि यदि क़ानून के रखवाले अपना दायित्व निभाने में कोताही बरतते हैं तो किस तरह भीड़तंत्र पूरी क़ानून व्यवस्था पर हावी हो जाता है. ऐसे में जब भीड़तंत्र क़ानून व्यवस्था पर हावी होने लगता है तो वह स्थिति सामाजिक दृष्टि से बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि भीड़तंत्र का संचालन अफ़वाहों से होता है. वह बिना सोचे–समझे उकसाने पर आक्रामक हो उठता है. इसी का प्रकटीकरण हुआ है कलमना बस्ती की घटना में.

इस घटना की मूल वजह थी पुलिस का उदासीन रवैया. ग़ौरतलब है कि पिछले कई दिनों से कलमना बस्ती के लोग दिनदहाड़े घरों से सामान चोरी होने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती वारदातों से हलकान थे. बस्ती के लोग जब भी पुलिस से मदद की गुहार लगाते थे, तो पुलिस अधिकारी मामले को अफ़वाह होने की बात कहकर टाल देते थे. पुलिस के इस रवैये से अपराधियों के हौसले जहां बुलंद थे, वहीं लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था. ऐसे में उनका पुलिस–प्रशासन के प्रति विश्वास भी कमज़ोर पड़ता जा रहा था. यही कारण था कि बस्ती के लोग रात–दिन अपनी क्षेत्र में बारी–बारी से गश्त लगाते थे. गत 9 मई को जब यह घटना घटी, उस वक़्त बस्ती के लोग रात भर गश्त लगाने के कारण पहले से तनाव में थे. ऐसे में सुपड़ा मगन नागनाथ (28), हसनराव दादाराव सोलंकी (30), पंजाबराव भिकाजी शिंदे (20) और पंजाबराव लक्ष्मण सोलंकी (36) महिलाओं का स्वांग रच कर पैसे मांगने पहुंचे. महिलाओं के भेष में चार युवकों को बस्ती में घूमते देखकर लोगों को संदेह हुआ और आगे–पीछे सोचे बिना उन्होंने चारों पर हमला बोल दिया. चारों युवकों ने उग्र भीड़ से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चारों ओर से घिर जाने के कारण वे भाग नहीं पाए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों का आक्रोश इतना अधिक था कि पुलिस वाहन से एक युवक को खींच कर उसकी हत्या कर दी गई. कुछ लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया. हालांकि घायल पंजाबराव लक्ष्मण सोलंकी को भीड़ के चंगुल से किसी तरह पुलिस छुड़ाने में कामयाब रही, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, तब तक लोगों ने क़ानून अपने हाथ में लेकर दोनों युवकों को मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना से कुछ दिन पहले ही रविवार के दिन विजयनगर बस्ती के लोगों ने एक युवक को देर रात नाले की ओर भागते हुए पकड़ा. उसके हाथ–पैर में चिकना पदार्थ लगा था. पहले तो लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद उसे कलमना थाने में पुलिस के हवाले कर दिया. स्थानीय लोगों ने इस बाबत पुलिस से उचित कार्रवाई करने की भी मांग की. बस्ती के लोगों के अनुसार, वहां से वापस आते ही उस युवक को पुलिस ने छोड़ दिया. इस तरह की कई घटनाएं होने से बस्ती वालों का विश्वास पुलिस पर नहीं रहा और लोगों ने क़ानून अपने हाथ में लेते हुए इस निर्मम घटना को अंजाम दिया.

इस हादसे के बाद जहां पुलिस अधिकारियों ने अपनी ख़ामियों पर पर्दा डालने के लिए बेतुका बयान देना शुरू कर दिया. वहीं इसे लेकर नेताओं द्वारा राजनीति भी होने लगी. नागपुर के क़ाबिल पुलिस आयुक्त अंकुश धनविजय ने कहा कि पुरुषों को महिला के रूप में देखकर लोगों को संदेह हुआ और लोगों ने उन्हें अपराधी समझ कर हमला कर दिया. इस ग़फ़लत में तीन लोगों को उग्र भीड़ ने मार डाला. वहीं उपायुक्त संजय दराड़े ने कहा कि ग्रीस गैंग के सक्रिय होने की ख़बर से पुलिस पहले ही हरकत में आ चुकी थी. उन्होंने लोगों से अफ़वाहों पर ध्यान न देने और संयम बरतने की सलाह जनता को दी. संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हर हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों के इन बयानों से उनकी ख़ामियां छुप सकती हैं? उपायुक्त दराड़े की मानें तो शहर में ग्रीस गैंग सक्रिय है, फिर इस घटना के पहले जब विजयनगर के लोगों ने संदिग्ध युवकों को कलमना पुलिस के हवाले किया था तो बिना कोई कार्रवाई किए, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? जब भी बस्ती के लोग अपराधियों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं की इज्ज़त से ख़िलवाड़ करने और सामान चोरी होने की शिकायत करने आते थे तो उनकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया लिया जाता था? घटना के चार दिन बाद जांच के लिए नागपुर पहुंची अतिरिक्त पुलिस महासंचालक श्रीदेवी गोयल ने भी घटनास्थल का दौरा करने और प्रत्यक्षदर्शियों से मिलने के बाद उपराजधानी की पुलिस को क्लीन चिट दे दी. हालांकि उन्होंने यह ज़रूर कहा कि जिस तरह लोगों ने तीनों युवकों की हत्या की, उससे तय इरादे से वारदात को अंजाम देने का पता चलता है. हालांकि उन्होंने यह माना कि यह घटना अमानवीय है और किसी व्यक्ति द्वारा क़ानून को हाथ में लेना बेहद ख़तरनाक है. हालांकि उन्होंने इस बारे में चुप्पी साध रखी कि आख़िर लोग क़ानून अपने हाथ में लेने को मजबूर क्यों हुए? इसके अलावा वारदात को अंजाम देने वाली भीड़ में शामिल लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि पुलिस निर्दोष नागरिकों को बलि का बकरा बना रही है. अब मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले कई संगठन सामने आए और हमलावर भीड़ के बचाव में विधायक, नगरसेवक एवं स्थानीय नेता भी अपने–अपने तर्क पेश कर रहे हैं.

घटना के बाद मृतकों के विषय में पता चला कि वे सभी बुलढाणा ज़िले स्थित जलगांव जामोद के निवासी थे. इस हादसे की ख़बर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया. घर की महिलाएं विलाप कर रही थीं, तो पुरुषों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे क्या करें. उग्र भीड़ के शिकार हुए युवकों का भरा–पूरा परिवार है और अब चिंता यह है कि उनके परिवार का गुज़ारा कैसे होगा? गांव वालों का कहना है कि यहां रोज़गार का कोई साधन नहीं है. वैसे मृतकों का मूल व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उससे पूरे साल गुज़ारा नहीं हो पाता था. चूंकि वे जोगी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए दूसरे गांवों–शहरों में बहुरूपिया बनकर लोगों का मनोरंजन कर पैसे कमाते थे. यह बहुरूपिया व्यवसाय ही आज उनकी मौत का कारण बन गया. वे जब शहरों से माह–दो माह बाद गांव लौटते तो आटा, अनाज एवं अन्य सामग्री और पैसों से परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था. यही सोचकर वे बीती 3 मई को नागपुर गए थे और अब उनकी मौत से पूरा गांव मर्माहत है. सुपड़ा मगन नागनाथ का विवाह दो महीने पहले ही हुआ था. उसके परिवार में उसकी बूढ़ी मां और पत्नी है. वहीं हसनराव दादाराव सोलंकी के घर में मां–बाप, पत्नी, एक लड़की और तीन लड़कों का भरा–पूरा परिवार है. पंजाबराव भिकाजी शिंदे के भी मां–बाप, पत्नी सहित दो लड़कियों का परिवार है. अब इन परिवारों के सामने रोज़ी–रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि क़ानून के रखवालों के गाल पर लोगों ने तमाचा जड़ा हो. क़ानून हाथ में लेने की नागपुर में घटी यह पहली घटना नहीं है. कुछ साल पहले जरीपटका थाने के अंतर्गत ही अक्कू यादव नामक व्यक्ति की हत्या भी पीड़ित महिलाओं ने कर दी थी. इसलिए यह सवाल उठना लाज़िमी है कि यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि लोग क़ानून हाथ में ले रहे हैं? आज अपराधियों की पुलिस से दोस्ती और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में उदासीनता बरतना इसका मुख्य कारण है. कई अपराधी पकड़े जाने पर लेन–देन कर छूट जाते हैं. इससे सामान्य नागरिकों में पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ने के साथ ही असुरक्षा की भावना भी गहराती जाती है. यहां पर बढ़ती असुरक्षा की भावना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से असुरक्षा की भावना जब चरम पर पहुंच जाती है और जब व्यक्ति के पास अपने बचाव का कोई उपाय नज़र नहीं आता है तो वह आत्मघाती क़दम उठाता है. ऐसे में वह क़ानून हाथ में लेकर वह सब कुछ कर डालता है, जो उसे नहीं करना चाहिए. अविश्वास की भावना ने कलमना बस्तीवासियों को क़ानून अपने हाथ में लेने को मजबूर किया, जिसका नतीजा है तीन निर्दोष बहुरूपियों की मौत. आज जब चारों तरफ़ आतंकवाद, नक्सलवाद और अपराधियों का साया मंडरा रहा है और अविश्वास का वातावरण व्याप्त है, तो ऐसे में जनता अपनी हर शिकायत पर पुलिस से यह अपेक्षा रखती है कि वह इस पर ग़ौर करे और दोषी व्यक्ति के ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई करे. यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर व्याप्त असुरक्षा की भावना उसे क़ानून हाथ में लेने के लिए बार–बार मजबूर करेगी. जनता में जो असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, उसे कम करना भी सरकार और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है.

राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि क़ानून के रखवालों के गाल पर लोगों ने तमाचा जड़ा हो. क़ानून हाथ में लेने की नागपुर में घटी यह पहली घटना नहीं है. कुछ साल पहले जरीपटका थाने के अंतर्गत ही अक्कू यादव नामक व्यक्ति की हत्या भी पीड़ित महिलाओं ने कर दी थी. इसलिए यह सवाल उठना लाज़िमी है कि यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि लोग क़ानून हाथ में ले रहे हैं? आज अपराधियों की पुलिस से दोस्ती और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में उदासीनता बरतना ही इसका मुख्य कारण है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 28 मई-03 जून 2012

www.chauthiduniya.com

The Most Cost Effective Builder In India

www.vastuvihar.org

वास्तु विहार®

एक विश्वस्तरीय टाउनशिप

AN ISO : 9001-2008 CERTIFIED COMPANY

हम बनाते हैं आपके सपनो का घर...!

7 लाख में घर

स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग सेन्टर, 24 घन्टे बिजली एवं जलापूर्ति

Multiple Option to choose your dresme shelter in any city...

पटना	– 07488538120/21/23, 0612-6450735	रांची	– 07488535220
मुज़फ्फरपुर	– 07488535211, 0621-6499030	आरा	– 07488535201
गया	– 07488535291/93, 0631-2221624	छपरा	– 07488535202
हाजीपुर	– 07488538151, 07488538139	दरभंगा	– 07488538162
हजारीबाग	– 07488538192/93	पूर्णिया	– 07488535250
भागलपुर	– 07488535249/50	सिवान	– 07488538145
धनबाद	– 07488535261/62	बिहारशरीफ	– 07488538178
बक्सर	– 07488535204	कोलकाता, सिल्लीगुडी	– 09331339202
बक्सर	– 07488535204		

For details Enquiry Type SMS VASTUVIHAR and send it to 56677

ADMISSION चाहिए तो सम्पर्क करें M.S. EDUCATIONAL TRUST

Registration is Going on

DIRECT & CONFIRM ADMISSION IN : Engineering, Medical, MBA, PGDM, POLYTECHNIC, BBA, BCA, MCA, B.ED, MEDIA, FASHION DESIGNING, NURSING

Without Donation & No Consultancy Charge Admission in Top College Low Rank/Marks No Problem No, Worry no waiting,No Donation

एम.एस. एजुकेशनल ट्रस्ट पहले कॉलेज AICTE Approved है या नहीं Building, Sructure, Library, Lab, Hostel, Mess, Faculty Visit करने के बाद ही बच्चों का एडमिशन कराते हैं।

ATTENTION AIEEE

Admission Helpline : 9334842167, 9931619796

M.S. Educational Trust द्वारा Admission कराने पर 10,000/-का SCHOLARSHIP मिलेगा

PLACE: •DELHI NCR •MEERUT •HARYANA •PUNJAB •PUNE •MUMBAI •AMRITSAR •COIMBATORE •HYDERABAD •SECUNDERABAD •BANGALORE •CHENNAI •VISAKHAPATNAM •ORISSA •KOLKATA •DURGAPUR

M.S. EDUCATIONAL TRUST - 14 BRANCHES IN BIHAR & JHARKHAND

1. Hajipur 2. Chapra 3. Muzaffarpur 4. Motihari 5. Sitamarhi 6. Bettiah, 7. Bhagalpur 8. Katihar 9. Aurangabad 10. Ranchi 11. Jamshedpur 12 Dhanbad 13. Bokaro

Bihar Head Office: Maa Complex Saketpuri, Bazar Samiti, Bahadurpur, Patna -16, Ph : 0612-2673939, email : maheshsushilatrust@gmail.com, website : www.mset.co.in

मायकर होगा लालू का नया ब्रह्मास्त्र

सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

सत्ता की राजनीति के लिए नए समीकरण गढ़ने एवं सरकार बनाने के लिए नए गठबंधन बनाने की कला में लालू प्रसाद माहिर रहे हैं. अपनी पिछली चुनावी हारों के सदमे से उबर कर एक बार फिर लालू प्रसाद बिहार एवं केंद्र की राजनीति में अपनी हैसियत बढ़ाने एवं नीतीश सरकार को बेदख़ल करने के लिए नए चुनाव जिताऊ समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं. बिहार की जनता उनके इस नए राजनीतिक क़दम को कितना समर्थन देगी यह तो आने वाला समय बताएगा, पर उनके तेवरों को देखकर लगता है कि वह नए दांवपेंचों के साथ नूराकुश्ती को छोड़कर अब असली कुश्ती के मैदान में कूद पड़े हैं.

आम धारणा रही है कि माय समीकरण की बदौलत लालू प्रसाद ने बिहार एवं केंद्र की राजनीति में डेढ़ दशक से ज़्यादा अपना सिक्का चलाया. हनक ऐसी कि लालू ने जो कहा, वही नियम बन गया. ताक़त ऐसी कि जिसे टिकट दिया, वही एमएलए और एमपी बन गया, लेकिन इस दौर की एक सच्चाई यह भी है कि इस समय कुशवाहा और राजपूतों का पूरा नहीं तो एक बड़ा तबक़ा निश्चित तौर पर लालू प्रसाद के साथ था और चुनावी राजनीति में हार को जीत में बदलने में कुशवाहा और राजपूतों के इस तबक़े ने बड़ी ही निर्णायक भूमिका निभाई. 1990 से 2000 तक के आंकड़े बताते हैं कि यादव, मुसलमान, राजपूत एवं कुशवाहा की जातीय गोलबंदी राजद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही. यहां यह बताना ज़रूरी है कि 2000 के बाद कुशवाहा और राजपूतों का मोह लालू प्रसाद से भंग होने लगा और 2005 आते-आते स्थिति यह हो गई कि इन वोटों में बिखराव आया और इसका अधिकांश हिस्सा जदयू के खाते में चला गया. सत्ता के मद में चूर लालू प्रसाद ने इन दोनों जातियों को तवज्जो नहीं दी और नीतीश कुमार इसका पूरा लाभ उठा ले गए. कहा जाए तो आधा अधूरा (मायकर) माय समीकरण में बदल गया. राजद के थिंक टैंक लालू प्रसाद को यह समझा रहे हैं कि बिहार में नीतीश सरकार के प्रति जनता का मोह लगातार कम हो रहा है और ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते राजद को राज्य में बड़ा आंदोलन छेड़ने में देर नहीं करनी चाहिए. ऐसे में लालू प्रसाद को इसी चुनाव जिताऊ समीकरण को फिर से मज़बूती से अपने पाले में लाने की रणनीति बनाने में जुटना चाहिए. यह काम चल ही रहा था कि औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के सोनहथु पंचायत के मुखिया देवेंद्र कुमार कुशवाहा उर्फ़ छोटू की हत्या और इसके बाद 2 मई को धमनी में हुई पुलिसिया कार्रवाई ने लालू प्रसाद और उनके थिंक टैंकों को सुनहरा मौक़ा दे दिया. धमनी में आयोजित सभा में पुलिस ने जो तांडव किया, उससे कुशवाहा समाज बेहद गुस्से में आ गया. भाकपा माले एवं प्रेम कुमार मणि ने इस घटना के विरोध में अगले दिन पटना में मार्च निकाला. उपेंद्र कुशवाहा एवं अरुण कुमार ने राजभवन मार्च निकाला. भाकपा माले के बिहार बंद का ख़ासा असर रहा, लेकिन बीती छह मई को लालू प्रसाद का क़ाफ़िला जब धमनी पहुंचा तो लगा कि बिहार की राजनीति में एक नई जातीय गोलबंदी को आकार लेने से अब कोई नहीं रोक सकता है. कुशवाहा समाज ने लालू प्रसाद को हाथों हाथ लिया और मौक़े की नज़ाकत को अच्छी तरह समझने वाले लालू प्रसाद ने भी बिना देर किए ऐलान कर दिया कि कुशवाहा समाज के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी. कुशवाहा समाज की आन एवं शान पर आंच नहीं आने दी जाएगी.

इस समाज को हर स्तर पर इसका वाजिब हक़ दिया जाएगा. धमनी में कुशवहा समाज ने लालू प्रसाद का दिल खोलकर स्वागत किया और आगे संघर्ष के लिए हरी झंडी दिखा दी. लालू ने मगध बंद का ऐलान कर इस न्यौते को स्वीकार कर लिया. छोटू मुखिया हत्याकांड ने भाकपा माले एवं कुशवाहा समाज और लालू प्रसाद के बीच की दुरियों को पाटने का काम किया. लालू के दौरे के समय धमनी में मौजूद पूर्व पार्षद प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि छोटू मुखिया की हत्या एवं इसके बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई से आहत कुशवाहा समाज ने इस दिन धमनी में लालू प्रसाद का जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया, वह साबित करता है कि कुशवाहा समाज अपनी राजनीतिक प्राथमिकता अब नए सिरे से तय कर रहा है. इस समाज का नेता होने का दावा करने वाले दिग्गज काफ़ी पीछे छूट गए हैं और पूरा समाज आशा भरी निगाह से लालू प्रसाद की ओर निहार रहा है. मणि मानते हैं कि अगर लालू प्रसाद माय का विस्तार मायकर यानी मुसलमान, यादव, कुशवाहा और राजपूत में करने में सफल हो गए तो बिहार की राजनीति की पूरी दशा एवं दिशा ही बदल जाएगी और नीतीश का शासन ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा. दरअसल, लालू प्रसाद भी मायकर को लेकर बेहद उत्साहित हैं. मौटे तौर पर बिहार में यादव 19 फ़ीसदी, मुसलमान 17 फ़ीसदी, कुशवाहा 9 फ़ीसदी और राजपूत 8 फ़ीसदी माने जाते हैं यानी 53 फ़ीसदी वोटरों का गठबंधन. काग़ज़ पर राजीनीतिक चश्मे से देखने में मायकर भले ही चुनाव जिताऊ गठबंधन दिखता हो, पर मायकर को ज़मीन पर उतारना बेहद ही कठिन काम है. काग़ज़ों पर जो बात इतनी सीधी है वह ज़मीन पर कड़ा इम्तहान लेने वाली है. कुशवाहा समाज के वोटों पर उपेंद्र कुशवाहा की मज़बूत पकड़ मानी जाती है. इसके अलावा नागमणि, अर्जुन मंडल आदि जैसे क्षत्रप भी इस वोट बैंक पर अपना हक़ मानते हैं. लालू प्रसाद को मायकर के लिए इन चुनौतियों से निपटना होगा. धमनी में कुशवाहा समाज का मिला समर्थन लालू प्रसाद के लिए रास्ता खोलता है. अब यह उनके राजनीतिक कौशल की अग्नि परीक्षा है कि वह इस रास्ते पर आगे बढ़कर किस तरह मंज़िल तक पहुंचते हैं. राजद की राज्यस्तरीय बैठक में प्रभुनाथ सिंह ने लालू प्रसाद को साफ़ कहा कि वह चापलूसों से दूर रहें. जगदानंद सिंह, रघुवंश सिंह और उमाशंकर सिंह लालू प्रसाद को ताक़त देते हैं, लेकिन राजपूत समाज का दिल जीतने के लिए लालू प्रसाद को एक बार फिर नए सिरे से कमर कसनी होगी. वह जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह को नमन कर शुरुआत कर चुके हैं. राजद में इस बात पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि अगर आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है तो उनका साथ नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने में लिया जा सकता है.

अगर आनंद मोहन उपेंद्र कुशवाहा से मिले तो उनके मोर्चे के साथ राजद का गठबंधन भी संभव है. मायकर की कामयाबी के लिए राजपूतों का पूर्ण समर्थन लालू प्रसाद के लिए बेहद ज़रूरी माना जा रहा है. दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि राजपूतों का पूरा समर्थन जदयू को मिले. राज्यसभा में वशिष्ठ बाबू और परिषद में नरेंद्र सिंह और संजय सिंह को भेजकर वह इसका संदेश दे चुके हैं. इसलिए इस मोर्चे पर लालू प्रसाद को कड़ा होमवर्क करना होगा. लालू प्रसाद को मुसलमानों को भी यह भरोसा दिलाना होगा कि वह पहले से ज़्यादा मज़बूती से उनके हक़ की लड़ाई लड़ेंगे और उनके सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगे. इसके अलावा यादव वोटरों को भी लालू प्रसाद को एक बार फिर नए सिरे से रिचार्ज करना होगा, मतलब मायकर के लिए काम ही काम है. इसमें थोड़ा भी आराम सारे समीकरण बदल सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद के सामने बड़ी चुनौती नीतीश कुमार हैं. राजद की बैठक में लालू प्रसाद ने यह साफ़ तौर पर कहा कि पुरानी ग़लतियों को दोहराया नहीं जाएगा और सभी को साथ लेकर चला जाएगा. लालू चाहते हैं कि मायकर को मज़बूती से चुनावी अखाड़े में उतारा जाए, इसके अलावा और कोई साथ आता है तो वह बोनस होगा. ■

इस समाज को हर स्तर पर इसका वाजिब हक़ दिया जाएगा. धमनी में कुशवहा समाज ने लालू प्रसाद का दिल खोलकर स्वागत किया और आगे संघर्ष के लिए हरी झंडी दिखा दिया. लालू ने मगध बंद का ऐलान कर इस न्यौते को स्वीकार कर लिया. छोटू मुखिया हत्याकांड ने भाकपा माले एवं कुशवाहा समाज और लालू प्रसाद के बीच की दूरियों को पाटने का काम किया. लालू के दौरे के समय धमनी में मौजूद पूर्व पार्षद प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि छोटू मुखिया की हत्या एवं इसके बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई से आहत कुशवाहा समाज ने इस दिन धमनी में लालू प्रसाद का जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया वह यह साबित करता है कि कुशवाहा समाज अपनी राजनीतिक प्राथमिकता अब नए सिरे से तय कर रहा है.

जाली काग़ज़ पर रेलवे जंक्शन से बुकिंग कराई जा रही है और इसे गंतव्य स्टेशनों तथा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि महानगरों तक पहुंचाया जा रहा है.

एक नज़र

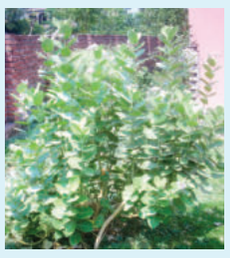

जड़ी-बूटियां विलुप्त हो रही हैं

सहरसा का कहरा प्रखंड क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण रहा है. इन क्षेत्रों में ख़ासकर देवना जंगल में तुलसी, अकवन, धतुरा, वाकस, भंगरोईया, छतियान, अमरलत्ती, टेकनमा, आंवला, अंडी, बगंडी, गुलाब, गुरीज, इसरगत, अर्जुन, नीम, भैंट आदि जड़ी–बूटियां व्यापक पैमाने पर होती थीं, लेकिन यहां के किसानों की उदासीनता के कारण अब ये विलुप्त हो रही हैं. कही–कहीं आक, धतूरा एवं नीम आदि देखने को मिल जाते हैं. पहले ख़ासकर गांव–घरों में लोग उदर रोग, खांसी, बुख़ार, पीलिया रोग, बवासीर आदि बीमारी होने पर इन जड़ी–बूटियों का उपयोग करते थे, लेकिन अब तो यह देखने को भी नहीं मिलता. *–अशोक झा*

बच्चों को सुपाच्य भोजन दें

डॉ. विपिन कुमार वर्मा

बिहार शरीफ़ के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विपिन कुमार वर्मा ने शिशुओं से संबंधित विभिन्न रोगों के संदर्भ में चौथी दुनिया से बातचीत की. प्रस्तुत है प्रमुख अंश.

डायरिया से कैसे बचा जा सकता है?

डायरिया एक जानलेवा बीमारी है. डायरिया होने के बाद उल्टी–दस्त होने के साथ–साथ शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है. डायरिया से

बचने के लिए गर्मी के इस मौसम में ताज़ा और सुपाच्य भोजन श्रेयस्कर होगा. पानी का अत्यधिक सेवन करना चाहिए.

बच्चों में विकलांगता का मुख्य कारण क्या है?

बच्चों की देखभाल में कमी होने तथा आंशिक रूप से बीमार पड़ने पर माता–पिता द्वारा लापरवाही बरतना विकलांगता का मुख्य कारण है. बच्चों के जन्म के बाद ही चिकित्सक के सलाह पर समय–समय पर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीका दिया जाना चाहिए. वैसे कमज़ोरी के कारण भी विकलांगता पांव पसार सकती है.

बच्चों में अक्सर पेट दर्द की बीमारी क्यों होती है?

खान–पान के प्रति लापरवाही बरतने के कारण पेट में गैस तथा कीड़े पैदा होने लगते हैं. इसलिए बच्चों के खान–पान के प्रति सजग रहना तो चाहिए ही, समय–समय पर चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक़ एलबेंडाजोल का सस्पेंसन देना चाहिए.

राजेश
feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों से लोहा लेने वालों से सरकार ने सुरक्षा छीनी

अमरेंद्र प्रताप सिंह feedback@chauthiduniya.com

झारखंड से नक्सल समस्या को जड़ से समूल नाश करने के लिए केंद्र सरकार एनसीटीसी लागू करने में काफ़ी गंभीर दिख रही है. राज्य में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय से हर रोज़ नए–नए निर्देश जारी हो रहे हैं. राज्य के मुखिया अर्जुन मुंडा के निर्देश पर नक्सलियों के ख़िलाफ़ पुलिस ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन यह राज्य की विडंबना है कि नक्सलियों से लोहा लेकर हिट लिस्ट में शामिल हो चुके कई ऐसे दिलेर हैं, जिनका पूरा परिवार नक्सलियों से हमेशा ही अपने दम पर लोहा लेता रहा है, जिनकी सुरक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. सरकार की इस सौतेले व्यवहार से कब ऐसे लोग नक्सलियों का कोप भाजन बन जाएंगे, कहा नहीं जा सकता. चतरा ज़िले के सर्वाधिक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शामिल वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में एक गांव है घंघरी. इस गांव के निवासी हैं दुर्गाशंकर सिंह. इनकी दिलेरी का नतीजा है कि पिछले 20 वर्षों से नक्सलियों ने उनके गांव की ओर रुख़ नहीं किया. दुर्गाशंकर सिंह राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस के चतरा ज़िला इकाई के अध्यक्ष हैं. विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने वर्ष 1990 में नक्सलियों के ख़िलाफ़ लोहा लेना प्रारंभ किया, नतीजा यह निकला कि नक्सली संगठन एमसीसी, जो अब भाकपा माओवादी के नाम से जाना जाता है, ने दुर्गाशंकर सिंह पर दो बार जानलेवा हमला किया.

दुर्गाशंकर सिंह

दोनों घटनाएं वर्ष 1994 में ही घटित हुईं. इन घटनाओं में शामिल आरोपी आज भी जेल की सज़ा काट रहे हैं. आपको बता दें कि नक्सलियों से लोहा लेने के लिए दुर्गाशंकर सिंह ने पूरे परिवार को हथियार चलाना सिखाया है और शायद इसी का नतीजा रहा कि दर्जनों बार नक्सलियों को खदेड़ा गया, लेकिन झारखंड सरकार से उन्हें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है. बक़ौल दुर्गाशंकर सिंह प्रारंभिक वर्षों में संयुक्त बिहार सरकार ने 20/06/99 तक घंघरी पुलिस पिकेट की स्थापना करके सुरक्षा मुहैया कराई थी, जिसमें 2–8 का पुलिस बल दिया गया था, लेकिन अलग झारखंड राज्य बनने के पश्चात यह सुविधा हटा ली गई. बाद में काफ़ी अनुनय विनय के बाद झारखंड सरकार, गृह विभाग के सरकार के उपसचिव ने अपने कार्यालय के ज्ञापांक– 862/पत्रांक 992, दिनांक 16.03.04 के तहत पुलिस अधीक्षक को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिया गया था.

इसके निमित दो पिस्टलधारी अंगरक्षक मुहैया करवाया गया, लेकिन नक्सली गतिविधियों को देखते हुए यह सुरक्षा नाकाफ़ी सिद्ध हो रही है. आश्चर्य की बात तो यह है कि पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के ज्ञापांक 8241 अभियान दिनांक 30/12/04 के तहत चतरा के पुलिस अधीक्षक को घंघरी पुलिस पिकेट को पून: चालू करने का निर्देश दिया गया है. इसके बावजूद मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. सरकार का यह कैसा मज़ाक़ है कि एक ओर सरकार नक्सलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ढोल पिट रही है, वहीं दुसरी ओर नक्सलियों के ख़िलाफ़ लोहा लेने वाले दिलेरों को यूं ही मरने के लिए छोड़ रही है. ■

तस्करों का स्वर्ग रक्सौल स्टेशन

इंतेज़ारुल हक़ feedback@chauthiduniya.com

लाख कोशिशों के बाद भी भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी का कारोबार बदस्तूर जारी है और रक्सौल रेलवे स्टेशन से विभिन्न ट्रेनों पर चीन निर्मित वस्तुओं की ढुलाई बेधड़क हो रही है. भारत–नेपाल सीमा पर होने के कारण यह स्टेशन तस्करों के लिए सुरक्षित जोन बनता दिख रहा है और एसएसबी एवं कस्टम समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता पर सवालियां निशान खड़ा हो रहा है. पूर्वी चंपारण ज़िले में सीमावर्ती प्रमुख व्यावसायिक शहर रक्सौल प्रारंभिक काल से ही तस्करों का अभयारण्य बना हुआ है और यहां अनेक प्रकार के सिंडिकेटों का जमावड़ा होता रहा है. भारतीय रेलवे के रक्सौल जंक्शन से चीन उत्पादित लहसुन, खिलौने, पाकिस्तान निर्मित जाली भारतीय नोट, नेपाल उत्पादित लौंग, इलायची, गरम मसाला, क़ीमती जंगली वनस्पति, नारकोटिक्स यथा गांजा, अफ़ीम, चरस, स्मैक समेत अनेक इस तरह की वस्तुएं धड़ल्ले से बाहर भेजे जा रही हैं. जाली काग़ज़ पर रेलवे जंक्शन से बुकिंग कराई जा रही है और इसे गंतव्य स्टेशनों यथा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि महानगरों तक पहुंचाया जा रहा है. आश्चर्य तो यह है कि रेलवे में बुकिंग कराने वाले तथा गंतव्य स्टेशन पर प्राप्त करने वाले का पता भी जाली होता है और भेजने और पाने वाले मोबाईल बातचीत से समझ जाते हैं कि फ़लां पते से इनका माल आ रहा है. इस धंधे में अगर सूत्रों की मानें तो रेलवे के बुकिंग विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ–साथ जीआरपी और आरपीएफ की भूमिका भी संदिग्ध बताई जाती है.

चार वर्ष पूर्व मोतिहारी कस्टम के सहायक आयुक्त ने इस बाबत विस्तृत प्रतिवेदन कई अकाट्य प्रमाणों के साथ रेलवे के उच्चाधिकारियों तक भेजे थे और जांच का आग्रह किया था. लेकिन आज तक इस मामले की रेलवे के किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच के परिणाम क्या हुए, यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया. खुलेआम रक्सौल स्टेशन पर तस्करी का सामान लेकर तस्कर पहुंचता है और सभी की नज़रों के सामने ट्रेन में सामान लेकर यात्रा के लिए बैठ जाता है. जीआरपी के जवान इन तमाम लोगों से वसूली करने में मशगूल होते हैं जिसे किसी भी क्षण देखा जा सकता है. यह धंधा लगातार जारी है. कई तस्कर जीआरपी थाना एवं इसके इर्द–गिर्द मौजूद रहते हैं और कई तो थाने की चाकरी भी कर रहे हैं. इसमें ऐसे तस्कर भी शामिल हैं, जो रेलवे की बोगी में स्क्रू खोलकर इसके भीतर नारकोटिक्स एवं अन्य क़ीमती तस्करी की वस्तुएं रख देते हैं. इन पर किसी की नज़र भी नहीं जाती और माल गंतव्य तक पहुंच जाता है. यह बहुत बड़ा रैकेट है, जो बड़ी चालाकी से सक्रिय है और इसे विभागीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. ऐसे अनेक मामले विभिन्न स्टेशनों पर पकड़े जा चुके हैं. यहां नेपाल से स्टोन चिप्स खुलेआम हर रात रक्सौल शहर में लाया जा रहा है, तो आधिकारिक रूप से भी स्टोन चिप्स की रेलवे बैगनों के माध्यम से तस्करी हो रही है. इसकी रोकथाम के लिए तैनात प्राय: सभी विभाग घाल–मेल में जुटे हुए हैं और ग़ैर आधिकारिक इस धंधे को आधिकारिक रूप दे रहे हैं. इस पर अनेक बार सवाल उठाए गए, लेकिन न तो केंद्रीय एजेंसियां और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी जांच कराना मुनासिब समझा. जानकार बताते हैं कि गुप्त एजेंसियां अगर निष्पक्षता से इस मामले की जांच करें तो अनेक अधिकारी, राजनेता समेत तस्कर बेनक़ाब होंगे. ■

अररिया में जाली नोट के कारोबारी

उपेंद्र यादव feedback@chauthiduniya.com

भारत-नेपाल सीमा के आस-पास जाली नोट का धंधा व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है. इस गोरखधंधें में किसी बड़े रैकेट के संलिप्त होने की बात तो पहले से सामने आ रही थी, लेकिन जाली नोट के साथ पकड़े गए कई सौदागरों ने अब इस बात का स्पष्ट ख़ुलासा भी कर दिया है. बात अलग है कि एसएसबी एवं बिहार पुलिस द्वारा पकड़े गए कई सौदागरों के रहस्योद्घाटन के बाद भी जाली नोट के बड़े सौदागरों तक पहुंच पाना पुलिस के लिए आसान नहीं दिख रहा है. समय-समय पर अभियान चलाकर एसएसबी एवं बिहार पुलिस ऐसे तत्वों के मंसूबों को चकनाचूर करने का प्रयास करती रही है. बावजूद इसके जाली नोट का कारोबार थमता नज़र नहीं आता. पुलिसिया कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने के लिए काफ़ी है. जानकारों का कहना है कि किसी न किसी रूप में जाली नोट के कारोबारी जाली नोट को बाज़ार में खपाने में सफल हो रहे हैं. अररिया की स्पेशल पुलिस टीम द्वारा फारबिसगंज के दल्लू टोला स्थित कुसमाहा पंचायत के पूर्व मुखिया मो. अशफ़ाक़ आलम के आवास से जाली नोट के साथ-साथ दो देसी कट्टे तथा 16 ज़िंदा कारतूस का बरामद किया जाना इस बात का प्रमाण है कि इस धंधे में रसूख़ वाले लोग भी संलिप्त हैं. गिरफ्तार किए गए पूर्व मुखिया मो. अशफ़ाक़ आलम से पूछताछ कर पुलिस मामले को खंगालने में जुटी हुई है.

पूर्व मुखिया के आवास पर हुई छापेमारी में 7 हज़ार 500 के जाली नोट, यूएसए अंकित 8 पीस बोतल एवं 10 रुपये के अधकट्टी नोट के साथ-साथ एक पर्चा मिलना अररिया ही नहीं आस-पास के इलाक़ों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. एसपी शिवदीप लांडे ने स्पष्ट कहा कि जाली नोट की आपूर्ति के पूर्व बतौर नमूना 7500 का जाली नोट पूर्व मुखिया को कहीं से भेजा गया था. 10 रुपये के अधकट्टी नोट का उपयोग हवाला या रुक्का के रूप में किए जाने की बात सामने आ रही है. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जाली नोट का कारोबार किया जाना कारोबारियों के लिए आसान दिख रहा था. बक़ौल एसपी, छापेमारी के दौरान बरामद पर्चे में अंकित है कि मुखिया जी, आपके भतीजे अफ़रोज़ एवं पिंटू ख़ान को 10 लाख रुपये पहले ही भेजा जा चुका है. हालांकि इसका भुगतान हो गया है, अब अगले खेप का सेंपल भेजा जा रहा है. एसपी ने बताया कि पूर्व मुखिया के घर से बरामद बोतलों में दिख रहे बुरादे को जांच के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाएगा. बहरहाल, जब यह प्रमाणित हो गया है कि भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में किसी बड़े रैकेट द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है तो फिर सरकार या पुलिस के आलाधिकारियों द्वारा क्या विशेष पुलिस बलों की तैनाती कर इस कारोबार पर विराम लगाया जाएगा, या इस राष्ट्रद्रोही धंधे को यूं ही फलने-फूलने के लिए छोड़ दिया जाएगा.

सीमा क्षेत्रों में एसएसबी जवानों की तैनाती के बाद भी जाली नोट के कारोबारियों द्वारा इस तरह के काले धंधे को सफलता पूर्वक अंजाम देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर दाग़ के समान है. ठोस व्यवस्था नहीं होने का रोना रोकर पुलिस अपने दामन को दाग़दार होने से इसलिए नहीं बचा सकती, क्योंकि नेपाल सीमा से सटे सीमांचल के जोगबनी, कुआड़ी,बथनाहा, फुलकाहा आदि क्षेत्रों में जाली नोट के साथ-साथ खाद, सुपारी सहित अन्य खाद्य पदार्थों की तस्करी में युवा वर्ग एवं कुछ चुनिंदा दुकानदार भी शामिल हैं. ■

सीमांचल में नए चेहरे चमकने लगे

नीरज कुमार सिंह feedback@chauthiduniya.com

बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद के सीमांचल की राजनीति में भी परिवर्तन आया है, जो पुराने दिग्गज नेता थे वे जनता की नज़रों से ओझल हो गए. इसके परिणाम स्वरूप उन्हें चाहने वालों समर्थकों की संख्या भी घटने लगी. इस दौरान सीमांचल का विकास हुआ, ऐसा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आज भी इन इलाक़ों में बड़े पैमाने पर अशिक्षा, ग़रीबी बाढ़ और कटाव की समस्या जस की तस बनी हुई है. सीमांचल की राजनीति की विशेषता रही है कि यहां जाति आधारित राजनीति कभी हावी नहीं रही, जिससे सामाजिक न्याय के नारे का यहां विशेष प्रभाव नहीं पड़ा. पहले शाहनवाज़ हुसैन, तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव, तारीक़ अनवर, अजीत सरकार जैसे नेताओं की तूती बोलती थी. वे किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते थे, लेकिन नए दिग्गजों के मैदान में आ जाने के कारण पुराने नेताओं की जनता पर पकड़ ढीली हो गई और उनका राजनीतिक पतन होने लगा. वर्तमान में उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह, दिलीप जयसवाल, अख्तरूल ईमान, गोपाल अग्रवाल, सिकंदर सिंह जैसे कई नेता हैं जो सुर्ख़ियों में हैं.

विगत लोकसभा के चुनाव में सीमांचल की चार सीटों में से पूर्णिया, कटिहार, अररिया भाजपा के खाते में गई, जबकि किशनगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी असरारुल हक़ कासमी ने जीत हासिल की. पूर्णिया से भाजपा प्रत्याशी उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह लगातार दूसरी बार जीते और पूर्णिया में विकास, शांति-व्यवस्था को लेकर उन्हें मिलने वाले मतों में बड़े पैमाने पर उछाल आया. पप्पू सिंह के सांसद बनने से पूर्व पूर्णिया को क्राइम सिटी का दर्जा प्राप्त था और आम लोग धमदाहा, रूपौली, भवानीपुर आदि इलाक़ों में शाम के बाद जाने से कतराते थे.

विगत लोकसभा के चुनाव में सीमांचल की चार सीटों में से पूर्णिया, कटिहार, अररिया भाजपा के खाते में गई, जबकि किशनगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी असरारुल हक़ कासमी ने जीत हासिल की. पूर्णिया से भाजपा प्रत्याशी उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह लगातार दूसरी बार जीते और पूर्णिया में विकास, शांति-व्यवस्था को लेकर उन्हें मिलने वाले मतों में बड़े पैमाने पर उछाल आया. पप्पू सिंह के सांसद बनने से पूर्व पूर्णिया को क्राइम सिटी का दर्जा प्राप्त था और आम लोग धमदाहा, रूपौली, भवानीपुर आदि इलाक़ों में शाम के बाद जाने से कतराते थे. यहां की सड़कें इस हद तक जर्जर थी कि पैदल चलना भी मुश्किल था, लेकिन इनके सांसद बनते ही पुल-पुलिया और सड़कों का जाल बिछा, जिससे गांवों से पूर्णिया का सफ़र दिन के बदले घंटों में तय होने लगा. धमदाहा, रूपौली, भवानीपुर के लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया था. यहां अपराधियों का भी बहुत आतंक था, लेकिन पप्पू सिंह द्वारा किए गए विकास कार्य एवं अपराध नियंत्रण को लेकर क्षेत्र के लोगों का विश्वास सांसद के प्रति जगा और बहुसंख्यक तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने गोलबंद होकर स्वत: पप्पू सिंह के पक्ष में बड़े पैमाने पर मतदान किया. वर्तमान में लोगों का मानना है कि सीमांचल की राजनीति का कंट्रोलिंग पावर पप्पू सिंह के हाथों में चला आया है. उनके प्रभाव से ही कटिहार, अररिया की सीटें भी भाजपा की झोली में आ गईं. वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की अधिकतर सीटें राजग के खाते में गईं. पूर्णिया की सात सीटों में से छह सीटों को राजग के पक्ष में लाने से लेकर टिकट वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. दरअसल सीमांचल में जदयू की पकड़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तस्लीमुद्दीन को जद (यू) में लाया, जिनको लेकर उन्हें विश्वास था कि सीमांचल में जद (यू) का जनाधार मज़बूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. विगत विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर भाजपा और जद (यू) में काफ़ी खींचतान चली. परिणामस्वरूप जद (यू) के खाते में तीन सीटें आईं, वहीं भाजपा को एक सीट दी गई. जहां तस्लीम समर्थक सभी उम्मीदवारों की हार हुई, वहीं किशनगंज से भाजपा प्रत्याशी की मात्र लगभग 200 वोटों से हार हुई. जानकारों का कहना है कि पूर्व विधायक सिकंदर सिंह ने अपनी ऊपर तक पहुंच एवं सांसद पप्पू सिंह के प्रयास से जहां किशनगंज सीट भाजपा के कोटे में लेने में कामयाब रहे, वहीं टिकट पत्नी स्वीटी सिंह को दिलाया. बहादुरगंज से वरुण सिंह भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली. वरुण सिंह विधान पार्षद दिलीप जायसवाल के क़रीबी माने जाते हैं. वहीं विगत वर्षों से सांसद पप्पू सिंह के विश्वासपात्र के रूप में किशनगंज में उभरकर सामने आ रही है. परिसीमन में टेढ़ागाछ प्रखंड के बहादुरगंज में जुड़ने से माहौल उनके अनुकूल था. किशनगंज लोकसभा सीट से शाहनवाज़ हुसैन जीते थे और केंद्र में वाजपेयी सरकार में मंत्री बने तभी किशनगंज एकाएक भारत के राजनीतिक पटल पर आ गया. शाहनवाज़ ने किशनगंज को विकास की सौग़ात दी, वहीं किशनगंज की जनता ने उन्हें भुला दिया जिससे उनकी हार हुई. मायूस होकर उन्हें किशनगंज छोड़ना पड़ा. भाजपा के कोषाध्यक्ष, विधानपरिषद, सह बिहार खाद्य भंडार निगम के अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में चर्चित नेता हैं. अपनी प्रभावशाली छवि के कारण और अल्पसंख्यकों में लोकप्रियता से विगत विधान परिषद चुनाव में पूर्णिया, अररिया किशनगंज के स्थानीय पंचायती राज प्रतिनिधियों ने चुनकर उन्हें विधान परिषद में भेजा. स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने के कारण आख़िर जनप्रतिनिधियों का अधिकार क्या है? वे अपनी ही सरकार को जब-तब कटघरे में खड़ा करने में पीछे नहीं रहे हैं. विगत लोकसभा चुनाव में किशनगंज से उनकी भाजपा उम्मीदवारी सुनिश्चित थी, लेकिन जद (यू) द्वारा भाजपा की यह सीट छीन लेने पर उन्हें मौन रहना पड़ा. उनके बारे में जानकारों का कहना है कि जायसवाल किशनगंज ही नहीं सीमांचल की किसी भी सीट से लोकसभा में पहुंचने की क्षमता रखते हैं. नीतीश लहर के बावजूद लगातार हैट्रिक बनाने वाले राजद विधायक अख्तरुल ईमान सीमांचल के चर्चित चेहरे हैं. उनकी लोकप्रियता का ग्राफ दिनोदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर यह क़यास लगाया जा रहा है कि भविष्य में किशनगंज लोकसभा सीट से उनकी दावेदारी पक्की है. मालूम हो कि राजनीति की पाठशाला में उन्हें तस्लीमुद्दीन लेकर आए थे. लालू की सत्ता जाने के बाद जहां तस्लीम दल-बदलकर जद (यू) में चले गए, वहीं अख्तरुल ने लालू और राजद का दामन नहीं छोड़ा. नीतीश को अख्तरुल के समान ही जद (यू) में करिश्माई नेता की तलाश थी. इसी संभावना को लेकर उन्होंने ठाकुरगंज से लोजपा के टिकट पर जीते नौशाद आलम को जद (यू) में शामिल कराया, लेकिन ठाकुरगंज में जद (यू) संगठन पर वर्तमान में भी पकड़ पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल की ही दिख रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक अवध बिहारी सिंह एवं सेवानिवृत्त अभियंता सुभाष सिंह की उम्मीदवारी के चलते गोपाल अग्रवाल की हार हुई थी. कुल मिलाकर सीमांचल में कांग्रेस एवं जद (यू) को करिश्माई चेहरे की तलाश है, जो उनकी नैया को पार लगा सके. ■

एक नज़र

उच्च विद्यालय का उद्घाटन

गोगरी अनुमंडल लगार पंचायत के मध्य विद्यालय को बिहार विधानसभा के विराधी दल के मुख्य सचेतक राकेश कुमार उर्फ़ सम्राट चौधरी द्वारा उच्च विद्यालय में परिणत किया गया, उद्घाटन के मौक़े पर उन्होंने कहा कि लगार जो परवत्ता प्रखंड से आठ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जहां की बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे चल रही थीं. उनके विकास को ध्यान में रखकर ही मैंने इस विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत करवाया है. इस अवसर पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश्वर दास, जितेंद्र यादव, बीईओ अखिलेश कुमार यादव, अंजनी कुमार, मनोहर यादव, मुखिया बबलू रजक, राहुल कुमार बच्चन, पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव सिंह, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दशरथ दास, राजद नेता सुधीर यादव, नारद यादव, अनुज कुशवाहा, निरंजन कुमार, शंकर यादव, मोहम्मद जब्बार आलम, रवि कुमार पवन कुमार, मनोज कुमार, झिंगों पंडित, राजाराम दास, उमेश शर्मा, मोहम्मद इस्लाम एवं महेश्वर साह उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री साईकिल योजना की राशि वितरित

बिहार विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक सम्राट चौधरी ने परवत्ता प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में मुख्यमंत्री साईकिल योजना के तहत दर्जनों छात्र-छात्राओं के बीच पच्चीस सौ रुपये की दर से राशि वितरित की. मिली जानकारी के अनुसार, उच्च विद्यालय तेमथा, उच्च विद्यालय कन्हैया चक, उच्च विद्यालय परबत्ता में राशि का वितरण किया गया. इस मौक़े पर प्रधानाध्यापक सफ़ी आलम, मनिकांत, अखिलेश्वर दास एवं मुखिया पवन चौधरी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे. *-गीता कुमार*

विधायक ने स्कूलों का निरीक्षण किया

गुरुजी से विधायक बने रामचंद्र सदा सरकारी स्कूल और निजी विद्यालयों की पढ़ाई से अवगत हुए. विधायक ने कहा कि अभी भी गांव एवं शहर के बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी अंतर है. उन्होंने कहा कि जिस उम्र में गांव के बच्चे घर में खेलने में मशगूल रहते हैं, उसी उम्र में शहर के बच्चे न सिर्फ़ ककहरा पढ़ लेते हैं, बल्कि एबीसीडी भी फ़र्राटे से पढ़ते हैं. प्राचार्य अजय कुमार सिंह द्वारा बच्चों से जब विधायक के सामने सवाल पूछे गए तो छात्रों ने बिना किसी झिझक के जवाब दिए. विधायक ने कहा कि सरकारी एवं निजी विद्यालय की पढ़ाई में अब भी काफ़ी अंतर है.

शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ : पूनम

सूबे में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आया है. राज्य सरकार के प्रयास से अब गांव में भी साईकिल से एक साथ दर्जनों छात्र-छात्राएं विद्यालय जाते हैं. ये विचार स्थानीय विधायक पूनम देवी यादव ने व्यक्त किए. इस अवसर पर रहीमपुर मध्य पंचायत स्थित एसएन उच्च विद्यालय सोनवर्षा में मुख्यमंत्री साईकिल योजना के तहत छात्रों के बीच राशि का वितरण किया गया. विधायक ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी थी. ज़िला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने कहा कि हमने ज़िले के अधिकांश वैसे उच्च विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराने का फ़ैसला लिया है, जिन विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है. *– मनेंद्र कुमार*

कटाव शुरू होने से ब्रिज को ख़तरा

कोसी क्षेत्र के लाइफलाइन कहे जाने वाले डूमरी पुल के समीप बनाए गए स्टील पाइल ब्रिज के दक्षिण दिशा में फिर से कटाव शुरू हो गया है. अगर शीघ्र कटाव निरोधक कार्य नहीं किए गए तो पुल पर कभी भी वाहनों का परिचालन बंद हो सकता है. उल्लेखनीय है कि उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाले डुमरी पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कोसी नदी में स्टील पाइल ब्रिज का निर्माण किया गया था. विभाग द्वारा यदि अविलंब कटाव निरोधक कार्य नहीं किए गए तो कटाव उग्र रूप धारण कर लेगा. कटाव के उग्र रूप धारण करने के बाद कटाव रोकना आसान नहीं होगा. वहीं कटाव निरोधक कार्य पर अत्यधिक ख़र्च भी आएगा. कटाव की रफ्तार बढ़ने से आसपास के लोग भी भयभीत हैं. लोगों ने शीघ्र कटाव निरोधी कार्य शुरू किए जाने की मांग विभागीय अधिकारियों से की है.

– ज्योतेंद्र नारायण सिंह

मनरेगा में लूट मची है

सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में कार्य किया जा रहा है. कार्य के साथ-साथ मज़दूरी भुगतान में भी व्यापक गड़बड़ी की शिकायत क़रीब-क़रीब सभी पंचायतों में है, लेकिन इन शिकायतों को आख़िर कौन सुनेगा. प्रखंड के सिर्फ़ उत्तरी पंचायत में मनरेगा के तहत एनएच 107 से नवजिया पोखर होते हुए सिमरी बख्तियारपुर तक पुराना पोखर नाला उराही कार्य का योजना सं. 79/10-11 में भी ख़ूब लूट मची है. प्राक्कलित राशि एक लाख 20 हज़ार 700 रुपये एवं कार्य में कहीं भी तालमेल नहीं है, जबकि कार्य पहली फरवरी 2011 को ही बंद हो गया. लोजपा के ज़िला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने भी इन योजना की जांच की मांग कर रोज़गार गारंटी प्रदान करने वाली योजना को ग़रीब हितकारी बनाने की मांग सीएम से किया है. *-चंदन पासवान*

ग़रीबी पूरी दुनिया की चिंता है: नीतीश मिश्र

सहरसा के रविनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय में आहूत व्याख्यान माला समारोह में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि ग़रीबी सिर्फ़ बिहार और देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता है. आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सोच में परिवर्तन से ही उन्नति संभव है. समारोह में मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि संस्थान के विकास के लिए सभी को आगे आना होगा. इस मौक़े पर विधि स्नातक के विश्वविद्यालय टॉपर अजय कुमार सिंह को मंत्री मिश्र ने 5 हज़ार की राशि भेंट कर पुरस्कृत किया, जबकि कॉलेज के पूर्व छात्र एवं पत्रकार नवीन निशांत को भी मंत्रीजी ने पुरस्कृत किया. इस अवसर पर अजय कुमार सिंह ने सहरसा में भारती मंडन मिश्र विश्व विद्यालय की स्थापना की मांग की, जबकि समारोह को डॉ. रेणु सिंह, ऊषा रमण झा, इंद्रकांत चौधरी, सुरेंद्र नाथ झा ने भी संबोधित किया.

-संजय सोनी

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 28 मई–03 जून 2012

www.chauthiduniya.com

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा

अपनी ग़लतियों से सबक़ लेते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम घोषित करके अन्य दलों के मुक़ाबले बढ़त लेना चाहती है. उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कार्यकाल में नगर निकाय चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव भी संपन्न होंगे. नगर निकाय चुनाव की मदद से भाजपा हवा का रुख़ अपनी तरफ़ मोड़ने का प्रयास करेगी और लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा उठाने की पुरज़ोर कोशिश करेगी.

संजय सक्सेना

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय प्रत्याशियों के चयन करने में लेटलतीफ़ी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सदबुद्धि आ गई है. अब वह लेटलतीफ़ी छोड़कर फास्ट ट्रैक पर दौड़ने की तैयारी कर रही है. इसके लिए उसने मिशन–2014 पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है. विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में देरी के कारण मिली करारी शिकस्त से सबक़ लेते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अहम निर्णय लिया है. इसके तहत 2014 में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे. नगर निकाय चुनाव सम्पन्न होते ही पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से नाम मांगेगी और 2012 के अंत तक प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर देगी. प्रत्याशी का नाम तय होने के बाद ज़िला संगठनों और प्रत्याशियों के बीच सामंजस्य बैठाकर आगे की चुनावी लड़ाई पूरी की जाएगी.

अपनी ग़लतियों से सबक़ लेते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम घोषित करके अन्य दलों के मुक़ाबले बढ़त लेना चाहती है. उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कार्यकाल में नगर निकाय चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव भी संपन्न होंगे. नगर निकाय चुनाव की मदद से भाजपा हवा का रुख़ अपनी तरफ़ मोड़ने का प्रयास करेगी और लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा उठाने की पुरज़ोर कोशिश करेगी.

नई और ठोस रणनीति के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए भाजपा व्याकुल है. पार्टी आलाकमान का सबसे अधिक ध्यान कार्यकर्ताओं को नए जोश और स्फूर्ति के साथ आगामी चुनाव के लिए तैयार करने में है. कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिलाया जाएगा कि पार्टी हर क़दम पर उनके साथ खड़ी है. इसके लिए कार्यकर्ताओं को शामिल कर कुछ अहम फ़ैसले भी लिए जाएंगे, जैसे नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने के बाद ही किया जाएगा. भाजपा के आला नेता सभी ज़िलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत करेंगे. पंचायत में उनके पक्ष को गंभीरता से सुना जाएगा. इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तरफ़ निकाय चुनाव के लिए उपयुक्त प्रत्याशी का नाम उभरकर सामने आएगा तो दूसरी ओर पार्टी में बग़ावत का माहौल नहीं बनेगा. इसके बाद कोई यह नहीं कह पाएगा कि प्रत्याशी को ऊपर से थोपा गया है. पार्टी यह समझती है कि यदि कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया कि पार्टी उनके साथ है, तो आधी लड़ाई भाजपा स्वत: ही जीत जाएगी. भाजपा कार्यकर्ता अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चुनाव प्रचार करने और प्रत्याशी को जितवाने की उम्मीद कार्यकर्ताओं से की जाती है, लेकिन जब पार्टी में फ़ैसला करने और उम्मीदवार चुनने की बात आती है तो ऊंचे पदों पर बैठे नेता मनमानी पर उतर आते हैं. टिकट बंटवारे के समय कार्यकर्ताओं की सुनने की बजाय अपने परिवार वालों और चहेतों को कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया जाता है. उस वक़्त यह भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि थोपे गए प्रत्याशी की राजनीतिक हैसियत क्या है, उस प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन हासिल है. शीर्ष नेतृत्व अब ऐसा नहीं करना चाहता है, जिससे कार्यकर्ताओं का हौसला कमज़ोर हो. सभासद के प्रत्याशी का चयन ज़िला इकाई करेगी. मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष के नाम का फ़ैसला तो लखनऊ में होगा, लेकिन ज़िला संगठन इकाई से तीन–तीन प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने को कहा जाएगा. इसी पैनल में से किसी एक प्रत्याशी का चयन किया जाएगा. इन नामों के अलावा कोई और नाम प्रदेश मुख्यालय, आलाकमान या बड़े नेता अब नहीं जोड़ पाएंगे. यही फार्मूला लोकसभा चुनाव के समय भी दोहराया जाएगा. सभी फ़ैसलों में ज़िला संगठन इकाई की प्रमुख भूमिका रहेगी.

लोकसभा चुनाव के लिए दो वर्ष पूर्व प्रत्याशी के नाम तय किए जाने के फ़ैसले को ज़रूरी बताते हुए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि पार्टी पर हमेशा प्रत्याशियों के चयन में देरी का आरोप लगता है. ख़राब चुनावी नतीजों के बाद पार्टी पर अक्सर आरोप लगता है कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा में हुई देरी की वजह से उम्मीदवार को चुनावी तैयारी के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता है. कुछ हद तक यह बात जायज़ भी लगती है. भाजपा इस बार इस तरह के आरोपों से पीछा छुड़ाना चाहती है.

प्रत्याशियों का चयन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों को धार देने में लग जाएंगे. विधानसभा चुनाव के समय उसके सामने लक्ष्य बसपा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा के निशाने पर होगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं कि अगर क़ब्रिस्तान की चारदीवारी सरकार बनवा रही है तो हिंदुओं के श्मशानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है. उन पर भी तो अवैध क़ब्ज़े हो रहे हैं. इन मुद्दों के अलावा भाजपा अपने पुराने मुद्दों को भी नहीं भूलेगी. अति पिछड़े और दलित तो उसके एजेंडे में होंगे ही, इसके अलावा किसानों की समस्याओं और उस पर राज्य और केंद्र सरकारों की बेरुख़ी, महंगाई, केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार, आतंकवाद के ख़िलाफ़ मनमोहन सरकार का लचीलापन, असफल विदेश नीति के सहारे भी भाजपा केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करेगी. हर स्तर पर केंद्र सरकार की नाकामी के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के बनते ही गुंडागर्दी का बोलबाला होना भी भाजपा के एजेंडे में शामिल होगा.

बहरहाल, यह सिक्के का एक पहलू था, दूसरा पहलू में देखा जाए तो भाजपा 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से फिट नहीं दिख रही है. भाजपा नेताओं में उत्साह की कमी साफ़ झलक रही है. उसका नेतृत्व बूढ़ा हो गया है. सभी दलों में युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी 40–50 के दशक के नेता खूंटा गाड़े बैठे हैं. प्रदेश अध्यक्ष पद पर लगभग अनजान और उम्रदराज़ लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बैठाकार भाजपा ने एक बार इतिहास को दोहराने का ही काम किया है. ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास नेताओं की कमी है, लेकिन पार्टी के भीतरी कलह–कलेश और आपसी गुटबाज़ी के कारण कोई बड़ा नेता अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर चुनाव की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है. सब पर्दे के पीछे से काम करना चाहते हैं. उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि भाजपा में हारने के बाद क्या हश्र होता है. यहां जीत के बाद कई साथी मिल जाते हैं, लेकिन हार की ठीकरा एक–दो लोगों के सिर फोड़ दिया जाता है. लोकसभा चुनाव के लिहाज़ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करना भी ज़रूरी है. अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने से पहले तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक अनजान सा चेहरा थे, लेकिन अब वह चर्चित होने लगे हैं. उनका सादा जीवन, सुलझे विचार पार्टी के ज़मीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास आने लगे हैं. वाजपेयी जी के साथ सबसे बड़ा प्लस प्वाइंट यह है कि उनके पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें कुछ खोने का डर बिलकुल नहीं है. वह अपने छोटे राजनीतिक क़द को पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचा कर बड़ा करने का सपना पाले हैं. उनका तो बस यही कहना है कि व्यक्ति की सोच सार्थक हो और उसकी नीयत साफ़ हो तो मंज़िल ख़ुद–ब–ख़ुद मिल जाती है. पिछले लोकसभा में उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति काफ़ी ख़राब रही थी. यहां कुल 80 सीटों में से मात्र 10 सीटों पर ही भाजपा प्रत्याशियों को सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 22–22 सीटों पर, बसपा को 20 सीटों पर तथा राष्ट्रीय लोकदल को 05 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी. एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी. भाजपा ने जिन दस सीटों पर सफलता हासिल की थी उसमें से मात्र आंवला लोकसभा क्षेत्र की एक सीट पर भाजपा की महिला प्रत्याशी मेनका गांधी को विजयी मिली थी. उत्तर प्रदेश में उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं आने के कारण ही भाजपा 2009 में सत्ता की लड़ाई में पिछड़ गई थी. ■

भाजपा कार्यकर्ता अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चुनाव प्रचार करने और प्रत्याशी को जितवाने की उम्मीद कार्यकर्ताओं से की जाती है, लेकिन जब पार्टी में फ़ैसला करने और उम्मीदवार चुनने की बात आती है तो ऊंचे पदों पर बैठे नेता मनमानी पर उतर आते हैं. टिकट बंटवारे के समय कार्यकर्ताओं की सुनने की बजाय अपने परिवार वालों और चहेतों को कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया जाता है. उस वक़्त यह भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि थोपे गए प्रत्याशी की राजनीतिक हैसियत क्या है, उस प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन हासिल है.

- **नगर निकाय चुनाव संपन्न होते ही पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से नाम मांगेगी**
- **भाजपा के आला नेता सभी ज़िलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत करेंगे**
- **कार्यकर्ताओं को शामिल कर कुछ अहम फ़ैसले भी लिए जाएंगे.**
- **पार्टी 2012 के अंत तक प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर देगी**
- **समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा के निशाने पर होगी**
- **भाजपा अपने पुराने मुद्दों को भी नहीं भूलेगी**

आवश्यकता है

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया को उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों एवं ज़िलों में आवश्यकता है संवाददाताओं, विज्ञापन प्रतिनिधियों एवं प्रसार व्यवस्थापकों की. अनुभवी एवं कार्यरत लोगों को वरीयता दी जाएगी. सम्मानजनक वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय. इच्छुक लोग पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं:–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11
नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष –0120–6451999, 6452888, 6450888

Email –advt.uttarpradesh@gmail.com

पहले इस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, किसी स्वामी ने वहां एक छोटा सा मल्ला (देव स्थल) ज़रूर बना दिया था. राजस्व अभिलेखों में भी कालीशिला यह स्थल मंदिर समिति के नाम पर दर्ज है.

प्रदीप शुक्ला की तरह कई आईएएस अफ़सर हैं, जिनके भ्रष्टाचार की कहानियां सबको मालूम हैं, मगर उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है.

खुले आसमान के नीचे पढ़ाई

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राकेश कुमार यादव feedback@chauthiduniya.com

पिछले महीने ही उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक स्वीकार्यता दे दी है. 1 अप्रैल, 2010 में शिक्षा का अधिकार क़ानून को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था. इस क़ानून के प्रावधानों के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान चलाने और इसके प्रचार-प्रसार पर सरकार प्रति वर्ष अरबों रुपये ख़र्च कर रही है. शिक्षा विकास की कुंजी है इसलिए इस पर ख़र्च किया जाना भी लाज़िमी है. शिक्षित देश तेज़ गति से तरक़्क़ी करता है. इसलिए शिक्षा योजना की विशेष आवश्यकता भी थी. ज्यों-ज्यों समाज शिक्षित हो रहा है, त्यों-त्यों रूढ़िवादिता, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास आदि से लोग दूर हो रहे हैं. लेकिन सरकार की शिक्षा योजना कैसी है, इसका एक उदाहरण अयोध्या के सरकारी प्राथमिक विद्यालय पाली मंदिर में देखा जा सकता है. अयोध्या में राजकीय तुलसी उद्यान के पीछे पश्चिम पाली मंदिर के निकट एक जर्जर भवन में तक़रीबन पचास साल से यह प्राथमिक विद्यालय चल रहा है. स्कूल भवन की हालत इतनी ख़राब है कि वह कभी भी धराशायी हो सकती है. इस इमारत की सीढ़ियां टूट चुकी हैं, फ़र्श पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. फ़र्श जगह-जगह पर धंस गया है, छत कई जगह लटक रही है. ईंट-रोड़े छत से गिरते रहते हैं, यहां रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है. कमरों में इतना अंधेरा है कि दिन में भी देख पाना मुश्किल होता है. नमी और गंदगी की वजह से मच्छरों का आतंक है. बरसात में छत से पानी टपकता रहता है. यहां हमारे देश का भविष्य शिक्षा पा रहा है. आजकल सरकारी स्कूलों में अधिकांश ग़रीबों के ही बच्चे शिक्षा लेते हैं. कक्षा एक से पांच तक के इस विद्यालय में एक अध्यापिका एवं एक अध्यापक नियुक्त हैं. पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या तक़रीबन सत्तर है. स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं है बच्चे बैठने के लिए बोरी घर से लाते हैं. बंदरों के आतंक से भी बच्चों को जूझना पड़ता है. मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाला भोजन भी वे बंदरों की वजह से नहीं खा पाते हैं. बंदर अक्सर उनके खाने पर झपट्टा मार जाते हैं. इस विद्यालय में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है. अब स्थिति यह है कि न तो विद्यालय का कोई अपना भवन है और न कोई और संसाधन है. दूसरों की दीवार पर श्यामपट (ब्लैकबोर्ड) बनाया गया है. वहीं खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठकर शिक्षा का अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हैं. कड़ी धूप में दूसरी दीवार की ओट में छांव खोजकर बच्चे बैठते हैं. इस तरह अपनी-अपनी बोरी लेकर दिन भर जगह बदलते रहते हैं. शौचालय की भी यहां कोई व्यवस्था नहीं है. यह काम भी खुली नाली में चल रहा है. पीने का साफ़ पानी भी बच्चों को नसीब नहीं हो पा रहा है. मिड डे मील भोजन भी नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है. ठंड में खुले मैदान में सर्द हवाओं के झोंको में ठिठुरना, गर्मी और धूप में तपना, बरसात में बंदरों की तरह इधर-उधर दुबक कर किताबों को बचाना ही इस विद्यालय में पढ़ने वाले कोमल बच्चों की दिनचर्या बन गया है. तमाम परेशानियों और बाधाओं के बाद भी विद्यालय में तैनात अध्यापक दिवाकर उपाध्याय और शिक्षा मित्र रमा देवी बच्चों को शिक्षित करने में लगे हैं. विद्यालय शिक्षक दिवाकर उपाध्याय बताते हैं कि वह पिछले 10 वर्षों से इस विद्यालय में तैनात हैं. भवन निर्माण को लेकर विभागीय तौर पर कई बार शिकायत की गई, मगर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है. इसलिए खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाना मजबूरी है. जब फ़ैज़ाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश से बात की गई तो उन्होंने विद्यालय के जर्जर भवन के संबंध में अनभिज्ञता ज़ाहिर की. हालांकि उन्होंने जांच कराने की बात कही है.

कुछ भी हो इस विद्यालय की अव्यवस्था को देखकर यही लगता है कि देश की आज़ादी के 65 वर्ष हो गये हैं, लेकिन इस देश की सरकार अभी तक बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं कर सकी है. दावे बहुत हैं, वादे बहुत हैं, प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपये ख़र्च हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा की तस्वीर धूमिल ही है. यह बच्चे कक्षा पांच तक कैसे पढ़ पाएंगे. जैसे-तैसे पढ़ भी लिए तो अगले दर्जे में प्रवेश कैसे हो पाएगा. ग़रीब बच्चों की शिक्षा भी ग़रीब ही रह गई. ऐसी शिक्षा से अच्छा तो बचपन से कोई हुनर सीख कर कमाने खाने लायक़ तो हो सकते हैं. दो जून की रोटी जुटा सकते हैं. सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये ख़र्च किए, लेकिन कोई बूढ़ा तोता राम-राम नहीं सीख पाया और जो बच्चे शिक्षा के क़ाबिल हैं, उनके लिए शिक्षालय और शिक्षा के साधन तक सरकार नहीं दे पाती है. ग़रीबी समाप्त न हो पाने का कारण शिक्षा की यह लचर व्यवस्था ही है. ■

ज्यों-ज्यों समाज शिक्षित हो रहा है, त्यों-त्यों रूढ़िवादिता, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास आदि से लोग दूर हो रहे हैं. लेकिन सरकार की शिक्षा योजना कैसी है, इसका एक उदाहरण अयोध्या के सरकारी प्राथमिक विद्यालय पाली मंदिर में देखा जा सकता है. अयोध्या में राजकीय तुलसी उद्यान के पीछे पश्चिम पाली मंदिर के निकट एक जर्जर भवन में तक़रीबन पचास साल से यह प्राथमिक विद्यालय चल रहा है. स्कूल भवन की हालत इतनी ख़राब है कि वह कभी भी धराशायी हो सकता है. इस इमारत की सीढ़ियां टूट चुकी है, फ़र्श पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. फ़र्श जगह-जगह पर धंस गया है. छत कई जगह लटक रही है. रह-रहकर ईंट-रोड़े छत से गिरते रहते हैं. यहां रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है. कमरों में इतना अंधेरा है कि दिन में भी देख पाना मुश्किल होता है. नमी और गंदगी की वजह से मच्छरों का आतंक है. बरसात में छत से पानी टपकता रहता है. यहां हमारे देश का भविष्य शिक्षा पा रहा है.

प्रदेश के भाषाई संस्थान अनाथ हैं

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में भाषाओं के प्रचार-प्रसार और बुद्धिजीवियों की कला को सहेजने वाले भाषाई संस्थान अनाथ से दिखने लगे हैं. ऐसे कुपोषित संस्थानों में भाषा कैसे पोषित हो सकती है. भले ही प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है. संस्थान को उबारने के लिए न तो सरकार रूचि दिखाती है और न आने वाले अधिकारी भाषाओं के प्रचार-प्रसार में ख़ासी दिलचस्पी लेते हैं. हालात इतने ख़राब हैं कि कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ जाते हैं. कभी-कभी ये संस्थान सियासत के शिकार हो जाते हैं. इस वजह से यह संस्थान अध्यक्ष एवं निदेशक विहीन रह जाते हैं. संस्थानों को विभागीय अधिकारी अपनी मनमर्ज़ी से चलाते रहे हैं. इस कारण संस्था निरंतर पंगु होती गई. इस संस्थान से साहित्य के मूर्धन्य लेखक, कलाकार, साहित्यकार आदि जुड़े हैं. इसलिए प्रदेश के कुछ साहित्यकारों ने ध्यान देते हुए यहां ख़ाली पड़े अध्यक्ष एवं निदेशक पद पर मनोनयन के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई. अपनी गर्दन फंसती देख बसपा सरकार ने जुलाई 2011 डॉ. प्रेम शंकर को अध्यक्ष मनोनीत किया था. साथ ही निदेशक पद पर डॉ. एसएस सिंह को पदस्थ किया था, लेकिन मार्च 2012 में बहुमत के साथ सत्ता में लौटी सपा सरकार ने एक बार फिर सारे महकमों के आला अधिकारियों की अदला-बदली कर दी. ऐसे संस्थानों के अध्यक्षों को अपने-अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा है. इसी कारण हिंदी संस्थान के निदेशक और अध्यक्ष को भी हटा दिया गया. जबसे सपा की सरकार प्रदेश में बनी है. लोगों को इन संस्थानों के दिन बदलने की आस लगने लगी है. बुद्धिजीवियों का कहना है कि सपा सुप्रीमो साहित्य प्रेमी हैं. ऐसा लगने की वजह मुलायम सिंह यादव के पिछले कार्यकाल में संस्थान के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत की गई एक करोड़ की धनराशि है. इसकी वजह से ख़स्ताहाल संस्थान चमक उठा. तब पुरस्कारों की धनराशि में बढ़ोत्तरी की गई थी और संस्थान के कार्यकलापों में शासकीय हस्तक्षेप को नगण्य कर दिया गया था. उन्हीं के समय में कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी. समिति की एक बैठक में सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से 60 वर्ष करने, पेंशन सुविधा लेने के संबंध में मंत्री परिषद के विचारार्थ एक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया था. हिंदी संस्थान के प्रति और साहित्यिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण क़दम सपा शासनकाल में ही उठाए गए थे. तब पुरस्कारों की राशि में अच्छी ख़ासी बढ़ोत्तरी हुई थी. संस्थान का अधूरा पड़ा यशपाल सभागार मुलायम सरकार में पूर्ण हुआ था. साहित्य प्रेमियों का कहना है कि इन संस्थानों की दुर्दशा के पीछे भाषा विभाग है.

कहने को तो अकादमियों को ऑटोनॉमस संस्थानों का दर्जा दिया गया है. लेकिन ये भाषा विभाग के अधीन हैं. कभी कार्यकारी अध्यक्ष, कभी निदेशक, कभी कार्यकारिणी तो कभी सामान्य सभा के अभाव में इनका स्वायत्तशासी रूप कभी भी बनने ही नहीं दिया जाता है. इस वजह से विभाग का दख़ल संस्थान पर बना रहता है. अपने बजट प्रस्तावों की स्वीकृति आदि में ये संस्थान भाषा विभाग पर आश्रित रहते हैं. बसपा शासन में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पुरस्कारों की नियमावली में संशोधन का बड़ा फ़ैसला हो या फिर हिंदी संस्थान के पुरस्कारों में कटौती जैसा अलोकप्रिय फ़ैसला, इस सभी निर्णयों के पीछे भाषा विभाग ही रहा है. उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान में तो लंबे समय से निदेशक की नियुक्ति ही नहीं हुई. यहां तो पुरस्कार घोषित करने के बाद वितरण रोक दिए गए वह भी तब, जब पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाना था. इस तरह के निर्णयों से संस्थान की छवि ख़राब हुई. इन सबके बीच अगर उर्दू अकादमी थोड़ा स्वतंत्र होकर कार्य कर सकी है और अपना बजट बढ़ा सकी है तो इसका कारण था कि उसकी उपाध्यक्ष तरन्नुम अकील ने शासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया. पंजाबी और सिंधी अकादमियों जैसे सरकारी संस्थान भी हैं. भाषा साहित्य से जुड़े बहुत सारे लोगों को इनकी जानकारी ही नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इन अकादमियों में कोई गतिविधि नहीं हुई है. हिंदी संस्थान में पहले मिलने वाले पुरस्कारों की संख्या सौ के आसपास थी, आज यह संख्या घटकर केवल तीन रह गई है. कई वर्षों से पुरस्कारों पर विचार नहीं किया जा रहा है. पुरस्कार नियमावली में संशोधन कर संस्थानों की स्वायत्ता समाप्त कर दी गई है. आयोजनागत बजट 15 लाख से घटकर तीन लाख रुपये किया गया है. भाषा संस्थान की पुरस्कार योजना पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, जो घोषित होकर भी वितरित नहीं हो सका. संस्कृत संस्थान की बात करें तो काफ़ी दिनों से कोई आयोजन ही नहीं किया गया है. 2009-10 के पुरस्कार लंबे समय से अटके हुए हैं. 2010-11 एवं 2011-12 के पुरस्कारों पर अभी तक विचार नहीं हुआ है. सिंधी, पंजाबी अकादमी की हालत ख़राब हो रही है. यहां पूर्णकालिक अध्यक्ष और निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है. पंजाबी एवं सिंधी अकादमी में तो 2009 से पद ख़ाली पड़े हुए हैं.

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान समेत प्रदेश की अन्य भाषाई संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं. संस्कृत संस्थान में निदेशक कार्य पहले संयुक्त सचिव (भाषा) सत्येंद्र सिंह देख रहे थे. अब यह ज़िम्मेदारी प्रमुख सचिव (भाषा) अशोक घोष के पास है. बहरहाल, हिंदी संस्थान में डॉ. एसएस सिंह की जगह डॉ. सुधाकर अदीब की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे संस्थान को कुछ राहत मिल गई है. इसी तरह संस्कृत संस्थान से कार्यकारी अध्यक्ष रेखा वाजपेयी के हटने के बाद पद अभी तक ख़ाली है. उर्दू अकादमी में उपाध्यक्ष तरन्नुम अकील के इस्तीफ़े के बाद अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी है. भाषा संस्थान में 6 मार्च, 2012 कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी के इस्तीफ़े के बाद पद ख़ाली पड़ा हुआ है. नई सरकार के गठन के बाद हिंदी संस्थान को निदेशक मिल गया है. डॉ. सुधाकर अदीब की हिंदी संस्थान को हिंदी बनाया गया है. संस्थान के कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार हिंदी संस्थान में निदेशक नहीं भेजती तो देश के सबसे बड़े हिंदी प्रदेश की यह संस्था बंद हाने के कगार पर पहुंच जाती. हिंदी साहित्यकार और कलाकार मुलायम सरकार आने से बेहद संतुष्ट दिख रहे हैं. उनका मानना है कि मुलायम सिंह साहित्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों के हित की बात सोचने वाले नेता रहे हैं. सपा सरकार के आने से भाषाई संस्थानों के दिन बदलने वाले हैं. ■

संरक्षित भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति और वन विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से मंदिर बनाने का मामला सामने आया है. सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिली जानकारी से इस बात का ख़ुलासा हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि जब राज्य सूचना आयोग ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को मामले की जांच का आदेश दिया तो जिलाधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले का उल्लेख कर सूचना आयोग को टका सा जवाब दिया कि दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह जांच नहीं करा सकते, जबकि आयोग ने उन्हें किसी सक्षम अधिकारी से मामले की जांच करवाने का आदेश दिया था. आयोग ने जिलाधिकारी के रवैये पर आपत्ति जताते हुए तीखी टिप्पणी की है. सूबे के प्रशासनिक अमले के लिए आरटीआई क़ानून गले की फांस बन गया है, जिसे धता बताने में ज़िले के आला अफ़सर लगे हैं. सूचना आयोग ने बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एवं वन विभाग की जानकारी के कालीशिला में मंदिर बनाने वाली स्थानीय उत्तरी महासिद्ध पीठ महाकालेश्वर सनातन धर्म एवं विकास समिति से जवाब तलब किया है. श्रीनगर निवासी कैलाश चंद्र जुगरान ने रुद्रप्रयाग ज़िले के कालीमठ के राजस्व निरीक्षक से काली शिला मंदिर की भूमि के मालिकाना हक़ एवं उसमें बने मंदिर के बारे में सूचनाएं मांगी थीं. सूचनाएं न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर दी. राज्य सूचना आयोग ने मामले में प्रभागीय वन अधिकारी रुद्रप्रयाग को पक्ष बनाया तो पता चला कि मांगी गई सूचना केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर से जुड़ी है. प्रभागीय वन अधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने बताया कि कालीशिला केदारनाथ वन्य जीव विहार संरक्षित क्षेत्र में आता है. कालीशिला मंदिर से जुड़े (आज़ादी से पहले एवं बाद के) भू-बंदोबस्त के अभिलेख वन विभाग के पास नहीं हैं. अब आयोग ने मार्च में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को मामले की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं. आयोग ने लोक प्राधिकारी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जवाब तलब किया तो पता चला कि कालीशिला मंदिर केदारनाथ मंदिर के अधीन है. इस मंदिर के प्रकरण को लेकर 14 अप्रैल, 2012 को कालीमठ में स्थानीय व्यक्तियों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें 82 वर्षीय रूप सिंह राणा ने बताया कि कालीशिला पाषाण खंड की पूजा सिर्फ़ विशेष अवसरों पर की जाती है. पहले इस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, किसी स्वामी ने वहां एक छोटा सा मल्ला (देव स्थल) ज़रूर बना दिया था. राजस्व अभिलेखों में भी कालीशिला यह स्थल मंदिर समिति के नाम पर दर्ज है. मंदिर समिति ने उत्तरी महासिद्धपीठ महाकालेश्वर सनातन धर्म सांस्कृतिक एवं विकास समिति, कालीशिला नामक स्थानीय समिति को इसका जिम्मा नहीं दिया है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को इस समिति द्वारा उस स्थान पर मंदिर बनाने की कोई जानकारी नहीं है. राज्य सूचना आयुक्त ने इन तथ्यों की रोशनी में बिना अनुमति मंदिर बनाने की आरोपित समिति को पक्ष बनाते हुए जवाब तलब किया है.

राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने जिलाधिकारी के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जिलाधिकारियों के इसी तरह के उदासीन रवैये के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की देहरादून में 62 एकड़ और रामनगर में 45 बीघा ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा हो गया है. आयोग ने जिलाधिकारी के असहयोगपूर्ण रवैए पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि लगता है कि जांच कराने का आदेश जिलाधिकारी को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगा. राज्य सूचना आयोग कई प्रकरणों में प्रदेश के मुख्य सचिव समेत तमाम उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दे चुका है और सभी अधिकारियों ने आयोग के साथ पूरा सहयोग किया है. आयोग ने साफ़ किया है कि 1939 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अगर किसी अन्य समिति द्वारा मंदिर समिति की ज़मीन पर क़ब्ज़े की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई है तो उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए. जंगल की संरक्षित भूमि पर सूबे में तैनात कई अफ़सर करोड़पति बनने के साधन के रूप में उपयोग कर काली कमाई कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है. ■

भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिल सकता है

भारत सरकार भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दे सकती है. यह घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने संसद में की. संसद में चिदंबरम ने भोजपुरी में कहा कि हम रउआ सबके भावना समझातनी भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने की बात बहुत दिनों से उठ रही है. सरकार लोगों की इस मांग को लेकर गंभीर भी है. सरकार ने भोजपुरी सहित अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में बनी सीताकांत महापात्रा कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मार्च में ही मिल गई है. सरकार इस विषय पर काम कर रही है. सरकार इस बारे में घोषणा मानसून सत्र में कर सकती है.

इस मुद्दे पर लोकसभा में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान चर्चा में गृहमंत्री पी चिदंबरम ने यह जवाब दिया. सांसद चिदंबरम के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि सामान्यत: चिदंबरम अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने भोजपुरी में अपनी बात कही है. इसलिए उनकी बात पर यक़ीन किया जाना चाहिए. सांसद चिदंबरम से भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की एक निश्चित समयसीमा जानना चाहते थे, लेकिन चिदंबरम ने कोई नियत समय नहीं बताया. अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दी गई है. आख़िरी बार सरकार ने बावनवां संविधान संशोधन करते हुए बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह दी थी. भोजपुरी भाषाई तौर पर आर्य भाषा है. यह मुख्य रुप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बोली जाती है. भोजपुरी को जानने वालों की संख्या लगभग 25 करोड़ है. भारत में लगभग 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं. अंग्रेजी शासन काल के दौरान उत्तर भारत के मज़दूरों के पलायन की वजह से यह दुनिया भर में फैल गई. भारत के अलावा सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना, फिजी, त्रिनिदाद और टोबेगो आदि देशों में भोजपुरी बोली जाती है. भोजपुरी भाषा का नाम आरा ज़िले के पास भोजपुर नामक गांव की वजह से पड़ा. यह भाषा लगभग 1000 साल पुरानी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

नौकरशाहों की भ्रष्टाचार गाथा

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

एनआरएचएम घोटाले में प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सचिव को सीबीआई ने हाल ही में गिरफ्तार किया है. दरअसल, प्रदीप शुक्ला की गिरफ्तारी एक साल पहले ही हो जानी चाहिए थी. लेकिन आधा दर्जन आईएएस रिश्तेदार, प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात उनके सगे संबंधियों और कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल से रिश्तेदारी की वजह से सीबीआई उन पर अब तक हाथ नहीं डाल रही थी. इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन घोटाले में तमाम रसूखदार लोगों की गिरफ्तारी होने के बावजूद एक साल से प्रदीप शुक्ला पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था. अब उनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े लोगों के भी इस मामले में फंसने की आशंका बढ़ गई है. यह बात जगज़ाहिर है कि उत्तर प्रदेश में प्रदीप शुक्ला की तरह कई आईएएस अफ़सर मौजूद हैं, जिनके भ्रष्टाचार की कहानियां सबको मालूम हैं, मगर उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है.

यह बात सभी जानते हैं कि प्रदीप शुक्ला अपने अपने बैच के टॉपर रहे हैं. लिहाज़ा बुद्धि की उनके पास कोई कमी नहीं है. मगर इस बुद्धि को कुबुद्धि में बदलने में प्रदीप शुक्ला ने कोई देर नहीं लगाई. अपने इसी हुनर के कारण वह पहले मुलायम दरबार में काफ़ी विश्वसनीय हुआ करते थे, लेकिन बाद में मायावती के सबसे क़रीबी लोगों में भी उनका नाम शुमार किया जाने लगा. माया सरकार में वह प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) के पद पर थे. प्रदेश की सभी स्वास्थ्य योजनाओं की ज़िम्मेदारी उनकी ही थी. मगर इस ज़िम्मेदारी को सही तरह से निभाने की जगह वह ख़ुद ही भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हो गए. वैसे भी माया सरकार में सब कुछ मायामय हो गया था. स्वास्थ्य विभाग पैसे कमाने की मशीन बन गया था. प्रदीप शुक्ला और बाबूसिंह कुशवाहा की जोड़ी ने भ्रष्टाचार की नई गाथाएं लिखीं. काग़ज़ी कंपनियों को करोड़ों रुपये के फ़र्ज़ी भुगतान किए गए. उन रुपयों को अफ़सरों और नेताओं ने आपस में बांट लिया.

प्रदीप शुक्ला के बाद अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है. माया सरकार प्रदीप शुक्ला पर कम मेहरबान नहीं रही. पिछली सरकार ने आईएएस प्रोमिला शंकर को इसलिए निलंबित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सरकार से बिना अनुमति के विदेश यात्रा की थी, जबकि प्रदीप शुक्ला ने बिना अनुमति लिए दर्जनों विदेश यात्राएं कर डालीं. इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विदेश जाकर भारी धनराशि वहां के बैंकों में जमा की. इन यात्राओं की जांच अभी भी लंबित है. इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आज तक राज्य सरकार ने प्रदीप शुक्ला को निलंबित नहीं किया था. प्रदीप शुक्ला ही नहीं प्रदेश के दर्जनों आईएएस अफ़सर ऐसे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले लंबित हैं. मगर उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है. सीबीआई ने नेहरू युवा केंद्र के ज़िला समन्वयक डीके सिंह को गिरफ्तार किया था. डीके सिंह की संस्तुती पर कई करोड़ के ठेके दिए गए थे. सभी जानते हैं कि डीके सिंह आईएएस अफ़सर नवनीत सिंह के क़रीबी थे. डीके सिंह ने पूछताछ में सीबीआई को नवनीत सहगल की जायदाद के विषय में बड़ी जानकारी दी थी. मगर सहगल पर हाथ डालने की हिम्मत सीबीआई नहीं जुटा पाई. सीबीआई के पास भ्रष्ट अफ़सरों की लंबी लिस्ट है. 2008 में प्रदेश के मुख्य सचिव रहे अखंड प्रताप सिंह को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की वजह से जेल भी जाना पड़ा. प्रमुख सचिव नीरा यादव को भी लोग भूले नहीं हैं. उन्हें सज़ा हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे हैं. 1999 में रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में हुए भर्ती घोटाले में आईएएस महेश गुप्ता समेत कई लोग सीबीआई जांच के दायरे में आए. 1971 बैच के यूपी कैडर के आईएएस बलजीत सिंह लाली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा. प्रसार भारती के सीईओ पद पर रहते हुए वह भ्रष्टाचार के दायरे में आए और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनके ख़िलाफ़ जांच को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया. अंतत: उन्हें प्रसार भारती के सीईओ का पद छोड़ना पड़ा. आईएएस भाई अभिनव चंद्रा और अभिषेक चंद्रा जाली सर्टिफिकेट लगाने के लिए चर्चा में आए थे. ये दोनों अलग-अलग राज्यों में तैनात हैं. 1984 बैच के ललित वर्मा जन्मतिथि के हेरफेर और कई बड़े प्रकरणों में सीबीआई की जांच के दायरे में आए. नोएडा भू आवंटन घोटाले में देवदत्त समेत चार आईएएस(अवकाश प्राप्त) सुर्ख़ियों में रहे थे. जिनके ख़िलाफ़ सीबीआई ने जांच के बाद चार्जशीट दाख़िल की. इसके अलावा पंद्रह बड़े अफ़सर निलंबित हुए. नोएडा घोटाले में काफ़ी समय तक निलंबित रहे आईएएस राकेश बहादुर और संजीव शरण को बहाली मिल चुकी है. राज्य के दो दर्जन से ज़्यादा आईएएस और पीसीएस अधिकारी खाद्यान्न घोटाले में आरोपी हैं. उनके ख़िलाफ़ सीबीआई जांच जारी है. पुलिस भर्ती घोटाले में 25 आईपीएस और 104 उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हो चुका है. मुलायम सरकार में 17 हज़ार पुलिस कर्मियों की भर्ती में सारे क़ायदे क़ानून को ताक पर रखकर भर्तियां की गई थीं. निर्यात निगम के एमडी रह चुके (हाल में रिटायर हुए) आईएएस तुलसी गौड़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच हो चुकी है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन 87, सतर्कता विभाग 178, और आर्थिक अपराध संगठन 123 मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें अधिकांश अफ़सर आरोपी हैं. ■

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(2005-2012)

मंत्री से बड़ा अफ़सर

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1981 बैच के टॉपर रहे आईएएस प्रदीप शुक्ला मंत्री से भी ज़्यादा ताक़तवर रहे. शुक्ला की मंत्री से भी ज़्यादा चलती थी. वह एनआरएचम में मिशन डायरेक्टर थे. 2007 से 2011 के बीच केंद्र सरकार ने 6 हज़ार 680 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिए थे, जिसमें से 1800 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों पर है. इसी घोटाले में प्रदीप शुक्ला नामज़द हैं. सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए लगातार सम्मन भेज रही थी और वह 16 बार इसी सिलसिले में सीबीआई दफ्तर भी गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह न तो लोगों के फोन रिसीव कर रहे थे और न पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस में उपस्थित हुए. हाल में एनआरएचएम महाघोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी प्रदीप शुक्ला के रूप में हुई है. सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद उनसे 6 घंटे पूछताछ की गई. उन्हें आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत गिरफ्तार किया गया है. उन पर राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा पैकफेड के ज़रिये प्रदेश के 89 अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनाने में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी करने का आरोप है. प्रदीप शुक्ला नौकरी में रहते हुए गिरफ्तार होने वाले प्रदेश के पहले आईएएस अधिकारी हैं. कार्यवाही पूरी होने के बाद सीबीआई टीम प्रदीप शुक्ला को लेकर दिल्ली चली गई. उसके बाद उन्हें ग़ाज़ियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. माना जा रहा है प्रदीप शुक्ला की गिरफ्तारी के पीछे कोर्ट का भी काफ़ी योगदान है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई के इंवेस्टिगेशन ऑफिसर को फटकार लगाते हुए पूछा था कि घोटाले से जुड़े मामलों में अब तक सीबीआई ने क्या किया है. इसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाए और यह भी बताया जाए कि किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस केस में सीबीआई ने अब तक लघु उद्योग निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक अभय कुमार वाजपेयी सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक रामप्रसाद, जल निगम की पीएसयू कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विस के महाप्रबंधक पीके जैन, तत्कालीन प्रोजेक्टर मैंनेजर बीएन श्रीवास्तव, इंजीनियर करतार सिंह, बीएन राम यादव, अकाउंटेंट जेके सिंह, ग़ाज़ियाबाद की सर्जिकल मेडिकिप प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जीके बत्रा और मार्डन इंटीरियर्स के आरके सिंह प्रमुख हैं.

गणना के दौरान बरेली मंडल के चार ज़िलों में 38 गिद्ध ही खोजे जा सके थे, जबकि बरेली और बदायूं में इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

RIGHT TO INFORMATION

संपत्ति घोषित करने से कतराते नौकरशाह

कुछ समय पहले सूचना आयोग ने रोशन लाल बनाम केंद्रीय विद्यालय संगठन मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि वार्षिक संपत्ति विवरण यानी वार्षिक संपत्ति रिटर्न पब्लिक डोमन के तहत आते हैं. अत: ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इसे सार्वजनिक न किया जाए. आयोग ने अपने फ़ैसले में कहा था कि ऐसा करने से सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर क़ाबू पाया जा सकता है. इससे हम ऐसे मामलों को उजागर कर सकते हैं, जिनमें घोषित आय साधनों से ज़्यादा संपत्ति एकत्र की गई हो. इसी तरह का एक और फ़ैसला वर्ष 2008 में गुजरात सूचना आयोग ने भी दिया था.

अजय कुमार feedback@chauthiduniya.com

देश में राजाओं की तरह जीवन यापन करने वाले नौकरशाहों को यह बात कभी भी रास नहीं आती है कि कोई उनके ऊपर पहरा बैठाए. न्यायपालिका, सरकार या फिर कोई और जांच एजेंसी, वे सभी से कन्नी काटते नज़र आते हैं. नौकरशाह अपने को हुक्मरान समझते हैं. नौकरशाही के इसी अंदाज़ की वजह से जनता से लेकर विभिन्न सरकारें हलकान रहती हैं. जनता का सीधे नौकरशाहों से पाला नहीं पड़ता है, लेकिन जब उनसे पाला पड़ता है तब उन्हें नाकों तले चने चबाने पड़ते हैं. नौकरशाह अपनी हदें भूल बैठे हैं. किसी भी प्रदेश का सारा दारोमदार नौकरशाहों पर ही रहता है. नौकरशाही को प्रशासन का दिमाग़ कहा जाता है. कई बार मंत्री सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि नौकरशाही पर लगाम लगाना आसान नहीं है. नौकरशाह हर बात का ठीकरा सरकार के सिर फोड़ने में महारथ रखते हैं. कई बार नौकरशाही पर लगाम लगाने की नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं. लेकिन नतीजा सिफ़र ही रहा.

कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय ने अपने एक फ़ैसले से नौकरशाहों पर लगाम कसने की कोशिश की है. न्यायालय ने नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है. जब विभिन्न चुनावों के पूर्व उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति का सार्वजनिक तौर पर ख़ुलासा करना अनिवार्य है तो ऐसा सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के मामले में क्यों नहीं हो सकता है.

केंद्रीय सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग तथा हाईकोर्ट के नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के आदेश ने नौकरशाहों के बीच हड़कंप मचा रखा है. कुछ नौकरशाहों ने अपनी संपत्ति का गोलमोल ब्योरा देकर मामला रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की है, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया. पिछले साल केंद्रीय सूचना आयोग के फ़ैसले के बाद माया के चहेते रहे उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडेय समेत कुछ आईएएस अधिकारियों ने अति उत्साह में अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश किया था. मगर उनकी ईमानदारी बनावटी साबित हुई. ईमानदारी का ड्रामा रचने वाले आईएएस अफ़सरों ने केंद्र सरकार को यह बताना उचित नहीं समझा कि सेवा नियमों के अनुसार उन्हें हर वर्ष अनिवार्य रूप से ऐसा करना चाहिए था. सवाल यह है कि उन्होंने अपनी चल अचल-संपत्ति के ब्योरे की घोषणा पहले क्यों नहीं की थी? दरअसल, अपने आप को सरकार से ऊपर समझने वाले नौकरशाहों ने आम से लेकर ख़ास तक सभी का अपने हिसाब से दोहन किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया है, तब नौकरशाही के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 नौकरशाहों के लिए गले की हड्डी बन गया है. यह क़ानून अकेले ही नौकरशाहों के कारनामों को जगज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है. बहुत ही कम समय में जनता सूचना के अधिकार क़ानून की ताक़त समझ गई. नौकरशाह लालफ़ीताशाही की पकड़ को कमज़ोर होते देख बेचैन हो उठे.

लोग यह जान गए कि नौकरशाहों के लिए अपनी संपत्ति का हर साल ब्योरा देना आवश्यक है. इसके लिए पहले से ही देश में क़ानून है. ज़रूरत केवल नौकरशाहों से उसका पालन कराने की है. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली-1956 के नियम-24 के अनुसार, प्रथम नियुक्ति के समय एवं इसके पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष का समय बीतने पर हर सरकारी कर्मचारी तथा उचित माध्यम से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी, ऐसी सभी चल-अचल संपत्ति की घोषणा करेगा, जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने ख़ुद अर्जित किया हो, जिसे उसने दान या उपहार के रूप में पाया हो, उसके द्वारा पट्टे या रेहन पर रखे गए हों और अन्य ली हुई पूंजियों की घोषणा करेगा जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे. आचरण नियमावली से साफ़ हो जाता है कि सरकार के हर अधिकारी/कर्मचारी के लिए अपनी संपत्ति का विवरण निर्धारित फार्म में देना अनिवार्य ही नहीं है बल्कि क़ानूनन ज़रूरी भी है. उनके लिए यह भी ज़रूरी है कि जब कभी भी सक्षम विभाग या अधिकारी उनसे उनकी संपत्ति का विवरण मांगे तो वह विवरण तुरंत सक्षम विभाग या अधिकारी को विवरण उपलब्ध कराएं. आईएएस अधिकारियों को इस संबंध में फार्म-16 बी में उपरोक्त सूचना देनी होती है. इसके अंतर्गत उन्हें अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों या किसी ऐसे व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होता है, जो उनसे जुड़ा हुआ है. इस संपत्ति में ऐसे घर या भूमि का विवरण निर्धारित विधि से देना होता है, जो स्वयं हासिल की गई हो या पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हो.

ग़ौरतलब हो, कुछ समय पहले सूचना आयोग ने रोशन लाल बनाम केंद्रीय विद्यालय संगठन मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि वार्षिक संपत्ति विवरण यानी वार्षिक संपत्ति रिटर्न पब्लिक डोमन के तहत आते हैं. अत: ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इसे सार्वजनिक न किया जाए. आयोग ने अपने फ़ैसले में कहा था कि ऐसा करने से सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर क़ाबू पाया जा सकता है. इससे हम ऐसे मामलों को उजागर कर सकते हैं, जिनमें घोषित आय साधनों से ज़्यादा संपत्ति एकत्र की गई हो. इसी तरह का एक और फ़ैसला वर्ष 2008 में गुजरात सूचना आयोग ने भी दिया था.

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने भी नौकरशाहों अतुल कुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, देवदत्त, ललित श्रीवास्तव, चंचल तिवारी, आएन त्रिवेदी, रविंद्र नायक, राजन शुक्ला और चंद्र प्रकाश के बारे में मांगी गई चल- अचल संपत्ति का ब्योरा देने के संबंध में विस्तृत फ़ैसला तब सुनाया, जब नियुक्ति विभाग ने इन अफ़सरों की संपत्ति का ब्योरा देने से इंकार कर दिया था. बृजेश मिश्रा ने उक्त नौकरशाहों के सेवाकाल से अब तक के वेतन भत्तों की मद में अर्जित की गई धनराशि की जानकारी मांगी थी. इस पर नियुक्ति विभाग ने कहा था कि संबंधित अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति के बारे में मांगी गई सूचना व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है. इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है. तत्कालीन राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपने फ़ैसले में कहा था कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपने विभाग में जमा कराए, इसलिए यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की संपत्ति का विवरण संबंधित विभाग एवं लोक प्राधिकारी कार्यालय में एक रिकॉर्ड की तरह जमा होता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (आई) के तहत रिकॉर्ड की परिभाषा में भी आता है. इस नियम में रिकॉर्ड (अभिलेख) की जो परिभाषा दी गई है, उसके अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ पांडुलिपि और फाइल होना चाहिए. इस जमा रिकॉर्ड या सूचना को धारा 8 (1) जे के तहत व्यक्तिगत सूचना नहीं माना जा सकता है. एक बार जब कोई कर्मचारी कोई विवरण अपने विभाग को दे देता है तो वह उसकी निजी सूचना नहीं रह जाती है.

राज्य सूचना आयोग का यह आदेश तत्कालीन बसपा सरकार और नौकरशाही को नागवार गुज़रा एवं उसने आयोग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया. यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है. एक ओर प्रदेश का नियुक्ति विभाग आईएएएस अफ़सरों की संपत्ति को उजागर न करने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहा है, तो दूसरी ओर राज्य के कुछ नौकरशाह बनावटी ईमानदारी दिखाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अपनी संपत्ति को उजागर करने की वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के विश्वास प्राप्त आईएएस अधिकारियों विजय शंकर पांडेय, राजू शर्मा, सुनील कुमार और जसवीर सिंह (आईपीएस) तथा नवनीत सहगल (आईपीएस) ने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी. लेकिन सवाल यह उठता है ये सब अधिकारी इतनी जद्दोजहद के बाद क्यों जागे? सभी ने हर वर्ष संपत्ति के विवरण देने की नियमावली को क्यों अनदेखा किया? क्या अभी तक शासन स्तर पर आईएएस अधिकारियों पर लागू होने वाले तत्संबंधी नियम ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स- 1968 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या प्रदेश के सभी नौकरशाहों और दूसरे अधिकारियों को स्वत: अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना करना चाहिए?

नौकरशाहों ने 2011 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया, उसमें सच्चाई कम है. देखा जाए तो हर तीसरा आईएएस अधिकारी करोड़पति है. कुछ अरबपति भी हैं. इन अधिकारियों ने ग़ैर क़ानूनी रूप से यह पैसा एकत्र किया है. अवैध तरीक़े से धन अर्जित करने और भ्रष्टाचार के चलते यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव, आईएएस सिद्धार्थ बेहुरा, प्रदीप शुक्ला को तो जेल तक की हवा भी खानी पड़ गई. इन नौकरशाहों की गिरफ्तारी तभी हो पाई जब न्यायपालिका या फिर जनता का काफ़ी दबाव पड़ा. सीबीआई के ऊपर आईएएस लॉबी की अच्छी पकड़ रहती है. उसकी लिस्ट से नौकरशाह दूर ही रहते हैं. इसके अलावा अगर सीबीआई उन पर कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगती है तो उन्हें जांच की अनुमति नहीं मिल पाती है. एक आम आदमी को छोटे से छोटे अपराध में ज़मानत लेने में लंबा समय लग जाता है, वहीं यह अधिकारी बड़े से बड़ा गुनाह करके भी कुछ ही दिन में बाहर आ जाते हैं.■

गिद्धों से ही बचेगा पर्यावरण

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गिद्ध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाने के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन वन विभाग के सभागार में किया गया. उत्तर प्रदेश वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, कतर्निया घाट फाउंडेशन और तराई नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के पदाधिकारी कार्यशाला में मौजूद थे. परियोजना की फंडिंग इंग्लैंड की संस्था रॉयल सोसायटी फोर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स द्वारा की जा रही है. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी फोर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के डायरेक्टर असद रहमानी तथा डिप्टी डायरेक्टर डॉ. विभु प्रकाश ने अपने कहा कि डाईक्लोफेनेक दवा का जानवरों के इलाज में उपयोग बंद किया जाना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि विलुप्त होने की कगार पर खड़े गिद्धों को बचाने के लिए पशुपालकों एवं पशुओं का इलाज करने वाले चिकित्सकों को यह बताना आवश्यक है कि डाईक्लोफेनेक के स्थान पर सुरक्षित दवा मेलोक्सीकैम का प्रयोग करें. कतर्निया घाट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सुरेश चौधरी ने गिद्धों के संबंध में हो रहे संरक्षण कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) रूपक डे ने की. इस कार्यशाला में इक़बाल सिंह, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, नीरज कुमार उपमुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा वन विभाग के मुख्यालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. उन्होंने उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए सेफ जोन की स्थापना के लिए एक सुर में आवाज़ उठाई.

देश में तेज़ी से घटते गिद्धों को बचाने के लिए जल्द ही दर्द निवारक दवाओं पर रोक लगानी होगी. यदि सरकार ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो गिद्ध भी डोडो पक्षी की तरह विलुप्त हो जाएंगे. अगर गिद्ध जीवित रहेंगे तो पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा. यह बात हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को समझ में आ चुकी है. नेपाल ने अपने जंगलों को नो डाईक्लोफेनेक जोन घोषित कर दिया है. हालांकि 15 दिसंबर, 2011 को पूरे उत्तर प्रदेश में गिद्धों की गणना की गई थी. केवल आगरा की बात की जाए तो आगरा ज़िले में गिद्धों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है. यहां गिद्धों की कुल संख्या 330 हो चुकी है. इनमें से 200 कुबेर पशु वधशाला में और 130 अछनेरा पशु वधशाला में पाए गए है. प्रदेश में पहली बार गिद्धों के संरक्षण को ध्यान में रखकर इस तरह की गणना की गई थी. इस दौरान आसमान में विचरण कर रहे गिद्ध नहीं गिने जा सके थे. गणना में कुल 2097 गिद्ध पाए गए थे. दस साल पहले भी कतिर्नया घाट वन्यजीव प्रभाग में गणना की गई थी. गिद्धों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है. गिद्धों की प्रमुख प्रजातियां ऑरिएंटन वाइट बैक्ड, लांग बिल्ड, इजिप्सियन, किंग वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, हिमायन ग्रिफान, रे हेडेड, यूरेशियन ग्रिफान तथा सेनेरियस हैं. प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक के के झा का कहना है कि हर बार गिद्धों की गणना में ग़लती हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. गिद्ध उड़ने वाला पक्षी है. इनके मरने के प्रमुख कारणों में वृक्षों की कमी, संक्रामक रोग, प्रदूषण एवं पशुओं का विषैला मांस है. पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाईक्लोफेनेक इनकी मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है. उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं ज़िलों में गिद्ध अब लुप्त हो गए हैं. गणना के दौरान बरेली मंडल के चार ज़िलों में 38 गिद्ध ही खोजे जा सके थे, इलाज के दौरान पशुओं को दर्द निवारक के रुप में दी जाने वाली डाईक्लोफेनेक दवा के कारण पशुओं के मांस में डाईक्लोफेनेक साल्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसके खाने से गिद्धों की किडनी ख़राब हो जाती है और इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है. नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत में गिद्धों की संख्या करोड़ों में थी. लेकिन अब इनके दर्शन तस्वीरों में ही हो पाते हैं. आश्चर्यजनक रुप से एक दो गिद्ध कहीं-कहीं देखने को मिल जाते हैं. प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के भैंसिया गांव में 28 नवंबर, 2011 को एक विशाल आकार का गिद्ध ग्रामीणों ने देखा, जिसे देखकर सभी हैरान थे. कुछ लोग उसे रामायणकाल का जटायु बता रहे थे. पर्यावरणविदों का मानना है कि जिस तरह से विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, कहीं गिद्ध दिवस भी मनाना न पड़ जाए. इसके साथ-साथ तोता दिवस, सारस दिवस भी मनाना पड़ सकता है. इन सभी पक्षियों की नस्ल ख़तरे में है पर्यावरण संरक्षण के लिए गिद्धों के साथ साथ अन्य पक्षियों की नस्लों को बचाना आवश्यक हो गया है. ■

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाईल : 09266627366